

• गले की फांस बना प्रमोशन में आरक्षण • शराब से भरेगा मध्यप्रदेश का खजाना!

In Pursuit of Truth

आक्षर

पाक्षिक

www.akshnews.com



क्या शापित है विधानसभा?

वर्ष 18, अंक-10

16 से 29 फरवरी 2020

मूल्य 25 रुपये

अबकी बार दिल्ली में जय हनुमान

R.N.I NO:HIN/2002/8718 M.P. BPL/642/2015-17



PRISM[®]
CEMENT

प्रिज़्म[®] चैम्पियन प्लस

ज़िम्मेदारी मज़बूत और टिकाऊ निर्माण की.



दूर की सोच[®]

Toll free: 1800-3000-1444

Email: cement.customerservice@prismjohnson.in

विवाद

9 | गले की फांस बना प्रमोशन में आरक्षण

पदोन्नति में आरक्षण केंद्र सरकार के साथ ही राज्य सरकारों के लिए गले की फांस बन गया है। दरअसल, गत दिनों सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पदोन्नति में आरक्षण मौलिक अधिकार नहीं है और इसे लागू करना या ना करना राज्यों पर निर्भर करता है।

राजपथ

10-11 | कमजोर हो रही पकड़

मप्र में 2018 का विधानसभा चुनाव हारने के बाद भाजपा की मैदानी पकड़ कमजोर पड़ती जा रही है। अपने गढ़ में भाजपा की कमजोर होती ताकत को मजबूत करने के लिए संघ ने अपनी सक्रियता बढ़ा दी है।

घोटाला

12 | कागज पर शौचालय

मध्यप्रदेश में स्वच्छ भारत योजना में बड़ा घोटाला हुआ है। तस्वीरों और पेपर पर तो 4.5 लाख शौचालय दिख रहे हैं। लेकिन स्पॉट पर जाने पर एक भी नहीं दिखा है। ऐसे में सवाल है कि क्या वह वहां से पलायन कर गए...

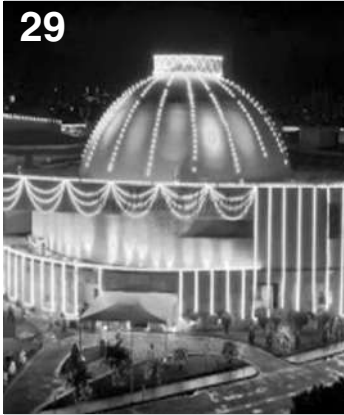
बजट

16 | उम्मीदों का बजट

मप्र सरकार का वर्ष 2020-21 का बजट प्रदेश के विकास के लिए मील का पत्थर साबित हो सकता है। मुख्यमंत्री कमलनाथ इस बजट को लेकर काफी संजीदा हैं और उनका साफ तौर पर मानना है कि इस बजट के माध्यम से आंकड़ों की बाजीगरी से परे विकास...



महाभारत काल में इन्द्रप्रस्थ के नाम से ख्यात दिल्ली में संपन्न हुए विधानसभा चुनाव में इस बार कुरुक्षेत्र जैसा नजारा देखने को मिला। दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार को हराने के लिए भगवान श्रीराम के नाम पर राजनीति करने वाली भाजपा ने साम-दाम-दण्ड-भेद सबका प्रयोग किया, लेकिन अरविंद केजरीवाल की हनुमान भक्ति के सामने उनकी एक नहीं चली। और दिल्ली में 'अबकी बार जय हनुमान' का नारा बुलंद हो गया।



29



32-33



40



45

अपराध

17 | जानलेवा गोरखधंधा!

मप्र में खेती-किसानी की आड़ में एक ऐसा गोरखधंधा चल रहा है जिसमें दलाल जमकर कमाई कर रहे हैं और खामियाजा मजदूर और किसानों को भुगतना पड़ रहा है। धार जिले के मनावर के बोरलाई गांव में हुई मौब लीचिंग की घटना इसका प्रमाण है।

राजनीति

30-31 | संघ का पदचिन्ह

कहने को तो संघ एक सामाजिक संगठन है, लेकिन इसकी महत्वकांक्षाएं किसी सियासी दल से कम नहीं। संघ भाजपा का मुखौटा लगाकर शासन करना चाहता है। हालत यह है कि भाजपा अपने मुख्यालय 11, अशोक रोड की बजाय नागपुर या झंडेवालान से संचालित होती है।

मुद्दा

34 | गंभीर नहीं सरकारें

भारत में खासकर महिलाओं और बच्चों को कुपोषण-मुक्त करने और उनमें एनीमिया यानी खून की कमी की समस्या दूर करने के मकसद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आठ मार्च 2018 को महिला दिवस के मौके पर राजस्थान के झुंझनू में पोषण अभियान की शुरुआत की थी।

6-7 | अंदर की बात

41 | महिला जगत

42 | आध्यात्म

43 | कहानी

44 | खेल

45 | फिल्म

46 | व्यंग्य



मुझ को गुनाह करने की आदत सी हो गई है...

बे खुद मोहानी का एक शेर है...

लज्जत कभी थी अब तो मुन्शीबत सी हो गई।

मुझ को गुनाह करने की आदत सी हो गई।।

ऐसा ही कुछ हाल है मप्र की एक महिला आईएएस का। महोदया पर ब्यूरोक्रेसी का दंभ कुछ इस तरह चढ़ा है कि वे जाने-अनजाने में ऐसी गुनाह कर जाती हैं कि उन्ससे नौकरशाही की पूरी बिरादरी पर बदनामी की चादर ओढ़ा दी जाती है। दरअसल, एक आम युवक या युवती अपनी मेहनत और लगन के बाद ब्यूरोक्रेट बनता है तो उन्समें कुछ ऐसा गुरूर आ जाता है कि वह नौकरशाही के कर्तव्य को भूल जाता है। वह सरदार वल्लभभाई पटेल का वह वक्तव्य भूल जाता है जिसमें उन्होंने नौकरशाह के कर्तव्य का उल्लेख करते हुए कहा था कि- 'यह आपका कर्तव्य है कि आप अपनी पूरी क्षमता से अपने देश के लोगों की सेवा करें। निष्पक्ष रहें, विनम्र बनें और दृढ़ प्रतिज्ञा रहें, जो काम आपके पास है, उसके लिए अच्छी तरह से तैयार रहें और उसे सफलतापूर्वक पूर्ण करें।' प्रदेश में कई प्रशासनिक पदों की जिम्मेदारी संभाल चुकी आईएएस महोदया अपनी प्रारंभिक पदस्थापना से ही थपड़मार मैडम बन चुकी हैं। अभी हाल ही में एक आंदोलन के दौरान भाजपा कार्यकर्ता को थपड़ मारकर सुब्रिचियों में आई मैडम ने पहली बार अपने शौर्य का प्रदर्शन सिंगरौली जिले में जिला पंचायत सीईओ के तौर पर तैनाती के दौरान दिखलाया था, जब उन्होंने शौचालय बनवाने में घपला करने वाले पंचायत सचिव से उठक-बैठक करवाई थी। यही नहीं मैडम पर एक एएसआई को भी थपड़ मारने का आरोप लगा है। हद तो यह है कि थपड़ मारने वाली महोदया को अपने किये पर जरा भी पछतावा नहीं है। कलेक्टर जैसे जिम्मेदारी भरे पद पर बैठे अधिकारी को थपड़ नहीं मारना चाहिए। वह पूरे जिले का डंडाधिकारी होता है और उसके आदेश पर कार्यवाही होती है। अगर कोई हिंसा होती है तो कलेक्टर के पास लाठीचार्ज, यहां तक कि गोली चलाने का भी अधिकार है। लेकिन जब खुद कलेक्टर थपड़ मारने लगे तो यह चिंता का विषय है। गौरतलब है कि जब एक ब्यूरोक्रेट जिम्मेदारी-जवाबदेही का प्रशिक्षण पाता है, तो वह सम्मान, सहयोग, सत्यनिष्ठा से वचितों की सेवा का संकल्प भी लेता है। फिर ऐसा क्या होता है कि शैक्षणिक मूल्यों और मान्यताओं के साथ पढ़ा-पढ़ाया गया रूल ऑफ लॉ को जिम्मेदारी संभालते ही भुला दिया जाता है और अपने ही बनाए नियम-कायदे थोप दिए जाते हैं। राजगढ़ के ब्यावर कस्बे में कलेक्टर द्वारा भाजपा नेता को थपड़ मारना और डिप्टी कलेक्टर का भीड़ से भिड़ जाना, मैदान में उतरकर शौर्य प्रदर्शन करना अधिकारियों का सार्वजनिक आचरण क्या नियम-कानून के दायरे में था? जवाब है-बिल्कुल नहीं। तभी तो मामला कोर्ट की दहलीज तक पहुंच गया है। वहीं इस घटना की जांच करने वाले अफसर ने भी महोदया को दोषी माना है। वहीं अब इस मामले की जांच के लिए वरिष्ठ अधिकारियों की हाईपावर कमेटी गठित कर दी गई है। यह कमेटी जांच में जुट गई है। देर सवेर सरकार उन पर कार्यवाही कर सकती है। लेकिन सवाल यह उठता है कि अपने पद की प्रतिष्ठा और पावर में क्या वाकई ब्यूरोक्रेट्स की महत्वाकांक्षाएं इतनी बढ़ जाती हैं कि वह कानून तोड़ने में तनिक भी देर नहीं करते। कलेक्टर व्यक्ति नहीं, बल्कि प्रशासनिक ढांचे के शीर्ष प्रतीक होते हैं। इसलिए, उन्ससे मारपीट या अभद्रता पूरी टीम का मनोबल गिरा देती है और इसी दबाव में गलत निर्णय होते चले जाते हैं। इसलिए एक नौकरशाह को यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि वह जनता का नौकर है। उन्सका पद और उन्सकी नौकरी जनता की सेवा के लिए निर्मित है। ऐसे में अगर कभी स्थिति असंयमित भी होती है तो उन्स संयमित रहना चाहिए। अगर वह संयमित रहेगा तो किसी भी बड़े माँब को नियंत्रित किया जा सकता है। इसलिए बार-बार गुनाह न हो इसके लिए हर ब्यूरोक्रेट्स को सरदार वल्लभभाई पटेल की बात याद रखनी होगी।

-राजेन्द्र आगाल

आक्षर

वर्ष 18, अंक 10, 16 से 29 फरवरी, 2020

प्रकाशक एवं संपादक : राजेन्द्र आगाल

सम्पादकीय कार्यालय :

प्लॉट नम्बर 150, जौन-1 मनोरमा कॉम्प्लेक्स,

एफ-03, 04, प्रथम तल, एम.पी. नगर

भोपाल- 462011 (म.प्र.),

फोन नं. 0755-2557777, टेलीफेक्स - 0755-4017788

email : akshmagazine@gmail.com

Website : www.akshnews.com

RNI NO. HIN/2002/8718 MPBPL/642/2015-17

बूरो

मुंबई :- ऋतेन्द्र माथुर, कोलकाता:- इंद्रकुमार,

जयपुर:- आर.के. बिनानी, छत्तीसगढ़:- संजय

शुक्ला, मार्केण्डेय तिवारी, टी.पी. सिंह,

लखनऊ :- मधु आलोक निगम।

प्रदेश संवाददाता

094251 25096 (इंदौर) विकास दुबे

098276 18400 (जबलपुर) धर्मेन्द्र कथुरिया

094259 85070, (उज्जैन) श्यामसिंह सिकरवार

094259 85070, (मंदसौर) धर्मवीर रत्नावत

098934 77156, (विदिशा) ज्योत्सना अनूप यादव

देशीय कार्यालय

नई दिल्ली : ईसी 294 माया इन्डेलव मायापुरी-

फोन : 011 25495021, 011 25494676

मुंबई : बी-1, 41 शिव पावती चेंबर प्लॉट नंबर 106-110 सेक्टर-21

नेरूल, नवी मुंबई-400706 मो.-093211 54411

कोलकाता : 70/2 हजर रोड कोलकाता

फोन-033 24763787, मोबाइल: 09331 033446

जयपुर : सी-37, शांतिपथ, श्याम नगर (राजस्थान)

फोन- 0141 2295805, मोबाइल-09829 010331

रायपुर : एमआईजी 1 सेक्टर-3 शंकर नगर, फोन : 0771 2282517

भिलाई : नेहरू भवन के सामने, सुपेला, रामनगर, भिलाई,

मोबाइल 094241 08015

इंदौर : 39 बुध्ति सिल्टर निगानिया, इंदौर

मोबाइल - 094251 25096

स्वात्वाधिकारी, मुद्रक व प्रकाशक, राजेन्द्र आगाल द्वारा आगाल प्रिंटर्स, प्लॉट नं. 150, जौन-1, प्रथम तल, एफ-03, मनोरमा कॉम्प्लेक्स, एम.पी. नगर भोपाल 462011 (म.प्र.), से मुद्रित एवं प्रकाशित

इस अंक में प्रकाशित सामग्री लेखकों के अपने विचार हैं इनसे सम्पादक का सहमत होना अनिवार्य नहीं हैं समस्त विवादों के लिए न्याय क्षेत्र भोपाल होगा।



अपराध को मिलेगा बढ़ावा

मप्र सरकार प्रदेश में अच्छा काम कर रही है, लेकिन शराब की उपद्रुकों को रोकने की अनुमति देने का फैसला गलत है। शराब की उपद्रुकों को रोकने से अपराध को बढ़ावा मिलेगा। देश के ऐसे कई राज्य हैं, जिन्होंने शराब पर प्रतिबंध लगा रखा है।

● **सुरज यादव**, भोपाल (म.प्र.)



टेंशन में है भाजपा

प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने भाजपा को टेंशन में डाल दिया है। रामपथ गमन विकास योजना, गाओं के लिए गौशालाएं खोलकर पहले ही सरकार ने भाजपा को पहले ही झटका दे दिया था और अब श्रीलंका में बीताजी का मंदिर बनाने की घोषणा के बाद भाजपा और अधिक टेंशन में आ गई है। ऐसा नहीं कि कांग्रेस जनता के हाव-भाव को देखकर ही भक्ति भाव कर रही है, इससे पहले भी छिंदवाड़ा के खिमरिया में कमलनाथ हनुमानजी का मंदिर बनवा चुके हैं। उज्जैन में भी महाकाल के मंदिर को और अधिक भव्य और आकर्षक बनवाने की भी बात की जा रही है। इससे भाजपा से कांग्रेस ने हिंदुत्व का तमगा अपनी ओर कर लिया है।

● **शुधिका सोनी**, जबलपुर (म.प्र.)

कानून का मजाक उड़ा रहे अपराधी

देश की कानून व्यवस्था से लोगों का भरोसा उठ रहा है। निर्भया केस में दोषी जिस प्रकार कानून का सहारा लेकर याचिकाएं लगा रहे हैं, इससे लोगों की नजरों में कानून का मजाक उड़ा रहा है। जब ये बात साबित हो गई कि वह चारों दोषी हैं और उनकी फांसी होना तय है फिर याचिकाओं का गलत तरीके से प्रयोग क्यों किया जा रहा है? यहां तक कि उनकी वकालत करने वाले लोगों को पीड़ित माता-पिता पर भी दया नहीं आ रही है। तारीख पर तारीख लेकर भी दोषी फांसी पर चढ़ने से नहीं बच सकते।

● **गुलशन आहुजा**, नई दिल्ली

मिलावटखोरों पर दबिशा

प्रदेश में इन दिनों सरकार द्वारा शुद्ध के लिए युद्ध का नारा मिलावटखोरों को चेतावनी है। मप्र के कई जिलों में मिलावटखोरों को पकड़ा गया है। प्रदेश में मिलावटखोरों पर दबिशा करने के लिए सरकार को और कई कदम उठाने चाहिए।

● **आशीष श्रीवास्तव**, ग्वालियर (म.प्र.)

मोदी का जादू कम हो रहा है

2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में जिस तरह मोदी का जादू चला था वह अब राज्यों के विधानसभा चुनावों में फीका होता दिख रहा है। पहले मप्र, छग, राजस्थान और अब महाराष्ट्र और झारखंड जैसे राज्य भाजपा के हाथ से चले गए। लगता है मोदी का जादू फीका हो रहा है।

● **प्रिया वर्मा**, उज्जैन (म.प्र.)



निवेश से मिलेगा रोजगार

प्रदेश सरकार द्वारा रोजगार के लिए अच्छे कदम उठाए जा रहे हैं। हाल ही में मुख्यमंत्री दावोस भी गए थे, जहां उन्होंने कई उद्योगपतियों से मिलकर मध्यप्रदेश में निवेश करने का आमंत्रण दिया। सीएम भी कह चुके हैं कि प्रदेश के युवाओं के लिए रोजगार की व्यवस्था बड़े स्तर पर की जा रही है। इसके लिए गत वर्ष प्रदेश सरकार द्वारा मैग्नीफिसेंट एमपी का आयोजन भी किया गया था, जिसमें कई उद्योगपतियों ने मप्र में निवेश की इच्छा जताई थी।

● **रितेश नानकानी**, इंदौर (म.प्र.)

पाठकों से निवेदन

कृपया अपनी प्रतिक्रियाएं पक्ष या विपक्ष जो भी संभव हो इस पते पर भेजें

अक्स

150 जोन-1, मनोरमा काम्पलेक्स,
एफ-02, 03, एमपी नगर, भोपाल



क्या वाकई अंगूर खट्टे हैं...

साधु, संत या संन्यासी की भी मंशा होती है कि उन्हें ओहदे मिलें। खासकर जब ओहदा किसी धार्मिक कार्य से जुड़ा हो, तो मंशा और बलवती होती है। लेकिन जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गत दिनों संसद में श्रीरामजन्म भूमि तीर्थ क्षेत्र के ट्रस्ट के गठन का ऐलान किया, तो उसमें अपना नाम न पाकर कई संतों ने कहा अंगूर खट्टे हैं। पंद्रह सदस्यों वाला यही ट्रस्ट अयोध्या में श्रीराम मंदिर का निर्माण करेगा। के पाराशरण को अध्यक्ष बनाए जाने पर बहुतों को हैरानी हुई। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में अयोध्या विवाद की पैरवी मंदिर के पक्ष में उन्होंने ही प्रभावी तरीके से की। इस ट्रस्ट में शामिल होने के लिए कई साधु-संत मंशा पाले हुए थे। लेकिन अधिकांश को मायूसी हाथ लगी। मसलन, स्वामी रामदेव, स्वामी अवधेशानंद गिरि और महंत नरेंद्र गिरि को उम्मीद थी कि राष्ट्रीय महत्व के इस ट्रस्ट में उन्हें जगह मिलेगी। शांतिकुंज के प्रमुख प्रणव पंड्या ने पिछले दिनों राज्यसभा में नामित करने के भाजपा सरकार के प्रस्ताव को नकारा था। पर श्रीरामजन्म भूमि तीर्थ क्षेत्र के ट्रस्ट में जगह पाने की हसरत उनकी भी रही होगी। कॉलेज छात्रा के यौन शोषण के आरोप में जेल जाकर आरोपी नहीं हुए होते तो स्वामी चिन्मयानंद बेशक इस ट्रस्ट में जगह पा सकते थे। जो रह गए वे अब करीबियों को झांसा दे रहे हैं कि पेशकश तो मिली थी पर उन्होंने ठुकरा दी।

नौकरशाही से खफा गडकरी

केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी अपनी स्पष्टवादिता के लिए जाने जाते हैं। खुलकर अपनी बातें कहने वाले गडकरी इन दिनों केंद्र सरकार के नौकरशाहों की जमकर लानत-मलानत कर रहे हैं। पिछले दिनों उन्होंने एक के बाद एक तीखी बातें नौकरशाहों की बाबत कह मंत्रालय के बाबुओं की नींद उड़ा दी है। गडकरी ने चेताया कि यदि निर्णय लेने में विलंब हुआ तो वह दिन दूर नहीं जब वे ऐसे सुस्त बाबुओं को एक कमरे में बंद तब तक कर देंगे जब तक वे अपनी वर्किंग स्टाइल सुधारने का मार्ग न तलाश लें। खबर है कि गडकरी कामचोर बाबुओं की रिटायरमेंट उम्र 60 से घटा 55 बरस करने का प्रस्ताव प्रधानमंत्री को दे चुके हैं। गत सप्ताह ही मंत्री महोदय ने यह कहकर बाबुओं पर अपनी भड़ास निकाली कि यदि इतने ही योग्य होते तो आईएएस बनने के बजाय उद्योगपति बन जाते। जानकारों की मानें तो ट्रांसपोर्ट भवन में इन दिनों गडकरी का खौफ बाबुओं की काम करने की गति बढ़ा चुका है।



दुविधा में दोनों गए

जनता दल (यू.) में सब सामान्य नहीं है। होता तो पवन वर्मा और प्रशांत किशोर जैसे नीतीश भक्त बगावत पर न उतरते। दोनों को पार्टी से बाहर होना पड़ा। हालांकि इसकी भूमिका उन्होंने खुद ही लिखी थी। दोनों नीतीश कुमार पर हमला दर हमला बोल रहे थे। उन पर झूठ बोलने का आरोप भी जड़ दिया। फिर पार्टी में कैसे रह पाते। नीतीश कुमार की दुविधा अब साफ है। वे सत्ता का मोह भी नहीं छोड़ पा रहे और अपने सिद्धांतों की दुहाई भी देते रहते हैं। मसलन संसद में सीएए को पारित करा दिया लेकिन बिहार में विरोध के स्वर दिखे तो तपाक से पलटी मार गए कि एनआरसी लागू नहीं होने देंगे। एनपीआर के सवालियों में बदलाव के लिए भी कहेंगे। दरअसल लड़ाई पार्टी में दूसरे नंबर की हैसियत को लेकर है। रामचंद्र प्रसाद सिंह, राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह, पवन वर्मा और प्रशांत किशोर सभी में नीतीश का सबसे करीबी दिखने की जंग लंबे समय से चल रही थी। बेशक चारों में केवल ललन सिंह ही सियासी शख्सियत हैं। बाकी तीनों की पृष्ठभूमि तो गैर-राजनीतिक ठहरी। रामचंद्र प्रसाद सिंह आईएएस अफसर रहे हैं। कांडर बेशक यूपी था पर डेप्युटेशन लेकर बिहार में नीतीश कुमार के प्रमुख सचिव रहे। लोकलुभावन योजनाओं के आर्किटेक्ट के तौर पर पहचान उसी दौरान बनाई। नीतीश के बिरादरी भाई होने से अहमियत ज्यादा बढ़ी। पवन वर्मा विदेश सेवा के अफसर थे। जबकि प्रशांत किशोर को सभी जानते हैं कि वे चुनावी रणनीतिकार हैं।

कलह सतह पर

राजस्थान में भाजपाई कुनबे में अब कलह सतह पर दिखने लगी है। वैसे भी पुरानी कहावत है कि टोटा हो जाए तो लड़ाई स्वाभाविक होती है। हार के बाद पार्टी की सबसे कद्दावर मानी जाने वाली नेता वसुंधरा राजे की आलाकमान ने अनदेखी कर दी। लिहाजा वे आहत होकर बदला क्यों न लें। उनकी सलाह के बिना ही सूबे में आलाकमान ने नए नेतृत्व को उभारने की कवायद अलग शुरू कर डाली। फिर तो महारानी को समझ आ गया कि अब उनकी हैसियत दोगम दर्जे की हो जाएगी। जबकि मुख्यमंत्री रहते वे आलाकमान को ठेंगे पर रखती थीं। बहरहाल नए पार्टी अध्यक्ष नड्डा उतने कड़क नहीं हैं। रही पार्टी की कलह की बात तो विधानसभा सत्र में सबने देखा। राज्यपाल के भाषण का पार्टी ने बहिष्कार किया तो कैलाश मेघवाल सदन में ही जमे रहे। मेघवाल को वसुंधरा खेमे में गिना जाता है। मेघवाल के कंधे पर बंदूक रख परदे के पीछे से निशाना वसुंधरा ने ही लगाया है। इससे संकेत मिल रहे हैं कि आने वाले दिनों में पार्टी के भीतर तनातनी और बढ़ सकती है।

समरथ को नहीं दोष

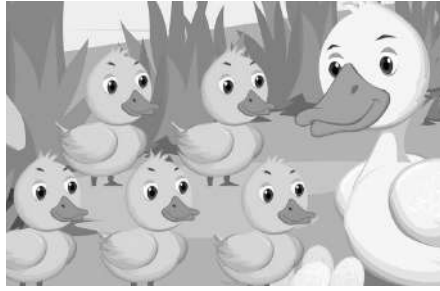
संघ परिवार की योजना अयोध्या में बनने वाले भव्य राममंदिर के लिए एक बार फिर बड़े पैमाने पर चंदा उगाने की है। यों राममंदिर के लिए चंदा देने वालों की देश में कोई कमी नहीं। बड़े-बड़े उद्योगपति ही कर सकते हैं इस जरूरत की पूर्ति। पर संघ परिवार इस बहाने व्यापक स्तर पर फिर हिंदू जागरण करने की रणनीति बना चुका है। उसी तर्ज पर जैसे 1989-90 में रामजन्म भूमि आंदोलन के दौर में बनाई थी। तब मोरोपंत पिंगले ने अच्छा आइडिया दिया था। राम शिला पूजन के बहाने अयोध्या आंदोलन को गति देने का। हर घर से मंदिर निर्माण के नाम पर सवा रुपए नकद और एक ईट के योगदान की दरकार थी। करोड़ों घरों से मिला था चंदा। पर उसका हिसाब-किताब लोगों के सामने कभी नहीं आया। न यह पता लग पाया कि पूजन की हुई शिलाओं का क्या हुआ? हां, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के वक्त आयकर विभाग के एक अफसर विश्व बंधु गुप्ता ने परिषद को आमदनी के ब्यौरे की बाबत नोटिस भेजने की जुर्रत जरूर की थी।

टूर्नामेंट की आड़ में वसूली

राजनीति में चंदाखोरी और वसूली के अपने-अपने तौर तरीके होते हैं। कोई भजन, कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम, कोई सामाजिक कार्यक्रम की आड़ में चंदा वसूलता है। इन आयोजनों में होने वाली चंदा वसूली से कई नेताओं की रोजी-रोटी भी चलती है। लेकिन प्रदेश की राजनीतिक और प्रशासनिक वीथिका में इन दिनों में एक मंत्री की वसूली चर्चा में है। वह भी ऐरे-गैरे नहीं बल्कि प्रदेश के सबसे कमाऊ विभाग के मंत्री ऐसा कर रहे हैं। जब इसकी पड़ताल की गई तो यह जानकारी सामने आई कि माननीय अपने पिताश्री के नाम पर एक टूर्नामेंट करवा रहे हैं। इस टूर्नामेंट को व्यापक रूप देने के लिए मंत्रीजी ने कई तौर तरीके अपनाए हैं। टूर्नामेंट की व्यापकता को देखते हुए अनुमान लगाया गया कि इसमें बड़ी राशि खर्च होगी। फिर क्या था, मंत्रीजी को भी उपाय सूझ गया और उन्होंने हर जिले को वसूली का टारगेट थमा दिया। गौरतलब है कि मंत्रीजी जिस विभाग के मंत्री हैं उस विभाग में अधिकारी-कर्मचारी से लेकर ठेकेदार तक लक्ष्मी के मद से मदहोश रहते हैं। यह बात मंत्रीजी भलीभांति जानते हैं। सो, उन्होंने सभी जिलों को वसूली का टारगेट थमाते हुए निर्देश भी दे दिया है कि इससे कम नहीं चलेगा। ऊपर जितना भी दोगे उतना अच्छा रहेगा। सूत्र बताते हैं कि मंत्रीजी के इस वसूली फॉर्मूले को कई छुटभैया नेता पसंद कर रहे हैं। शायद भविष्य में यह उनके काम आए।

अब कहां जाएंगी साहब की बतखें?

मप्र कैडर के एक आईएएस अधिकारी अपने तथाकथित पशु-पक्षी प्रेम के कारण सुर्खियों में बने हुए हैं। साहब का जहां भी ट्रांसफर होता है, वे उन्हें अपने साथ ले जाते हैं। लेकिन वर्तमान में साहब का ट्रांसफर मंत्रालय में हो गया है। ऐसे में लोगों के मन में यह जिज्ञासा है कि साहब की गायें, बतखें और अन्य पशु-पक्षी कहां जाएंगे। दरअसल, साहब वर्तमान में जिस विभाग में पदस्थ थे, वहां उनके पशु-पक्षियों को रखने के लिए पर्याप्त जगह मिल गई थी। इस कारण साहब ने कमाई की मंशा से कुछ गायें भी रख लीं। साहब के हाथ से अब उक्त विभाग निकलने के बाद उनके पशु-पक्षियों पर भी संकट के बादल मंडराने लगे हैं। गौरतलब है कि साहब जब प्रदेश के एक आदिवासी जिले में कलेक्टर थे, तो वहां उनके बंगले पर बड़ी संख्या में पशु-पक्षी थे। ये पशु-पक्षी कई कलेक्टरों का कार्यकाल देख चुके थे। लेकिन साहब का जैसे ही उक्त जिले से तबादला हुआ, तो वे पशु-पक्षियों को भी लेकर चलते बने। लेकिन अब वही पशु-पक्षी साहब के लिए परेशानी का सबब बन गए हैं। अब देखना यह है कि अपनी नई पदस्थापना के बाद साहब इन पशु-पक्षियों को कहां रखते हैं।



बड़े साहब के कमरे में बैठक का राज

प्रदेश की प्रशासनिक वीथिका में इन दिनों एक बड़े साहब के कमरे में होने वाली बैठकों की खूब चर्चा है। ये बड़े साहब एक विभाग में अपर मुख्य सचिव हैं। मंत्रालय स्थिति इनके कक्ष में पिछले कुछ दिनों से लगातार बैठकें हो रही हैं, जिसमें कुछ जाने और कुछ अनजाने चेहरे शामिल हो रहे हैं। इसको देखकर पूरे मंत्रालय में इस बात की चर्चा जोरों पर है कि आखिर बड़े साहब के कमरे में यह कैसी बैठकें हो रही हैं। साहब के कमरे में होने वाली बैठकों के बारे में जब पड़ताल की गई तो आश्चर्यजनक तथ्य सामने आए। सूत्र बताते हैं कि साहब इन दिनों एक राजनीतिक पार्टी के पदाधिकारी की तरह काम कर रहे हैं। वे पार्टी के फंड को जुटाने के काम में लगे हुए हैं। साहब को यह जिम्मेदारी किसने दी है, यह तो वे ही जानें। लेकिन बताया जाता है कि साहब के कक्ष में जो जाने-अनजाने चेहरे आ रहे हैं, वे प्रदेश के नामचीन ठेकेदार हैं। सूत्र बताते हैं कि साहब इन ठेकेदारों को मंत्रालय स्थित अपने कक्ष में आमंत्रित करते हैं, फिर उन्हें पार्टी के लिए फंड की मांग करते हैं। बताया जाता है कि प्रदेश के इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है जब अपर मुख्य सचिव स्तर का अधिकारी मंत्रालय में बुलाकर ठेकेदारों से पार्टी के लिए फंड जुटा रहा है। यहां यह बता दें कि बड़े साहब प्रदेश के एक बड़े कमाऊ विभाग की जिम्मेदारी संभाले हुए हैं। इसलिए साहब को उम्मीद है कि उनकी मांग को कोई भी ठेकेदार टालेगा नहीं और जल्द से जल्द पार्टी के लिए मोटा चंदा इकट्ठा हो जाएगा।

जितना मिला उतने से खुश

लक्ष्मी की अजब माया है। कोई बहुत पाकर भी खुश नहीं होता और कोई थोड़ा पाकर खुश हो जाता है। ऐसी स्थिति इन दिनों एक साहब की है। साहब को जितना मिलता है उतने में ही खुश हो जाते हैं। लेकिन साहब को इस संतुष्टि लोगों को पच नहीं रही है। दरअसल, साहब अभियोजन में हैं। वे अधिक की आस में थोड़े को छोड़ना नहीं चाहते हैं, इसलिए उनको जितना मिलता है उतने से ही अपने आपको संतुष्ट कर लेते हैं। साहब की इस संतुष्टि की पड़ताल की गई तो यह बात सामने आई कि साहब छोटे-छोटे अटैचमेंट कराने में लगे हुए हैं। इससे साहब को अच्छी खासी कमाई हो जाती है। ऐसे में साहब यह नहीं चाहते हैं कि वे बड़ी कमाई के लालच में फंसे। सो, साहब ने यह नीति अपना रखी है कि जितना मिले उतने से संतुष्ट रहो। पहले लोग समझते थे, साहब कितनी संतोषी प्रवृत्ति के हैं। लेकिन अब साहब की संतुष्टि के पीछे की वजह धीरे-धीरे सभी जान गए हैं। कुछ अफसर तो साहब के इस फार्मूले को अपनाने का मन बना चुके हैं।

इसे कहते हैं प्रशासनिक चूक

राजगढ़ जिले के ब्यावरा में एक राजनेता को प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा थप्पड़ मारने की घटना भले ही ठंडे बस्ते में चली गई है, लेकिन जिलाधिकारी द्वारा एक एसआई को थप्पड़ मारना शासन-प्रशासन के गले की फांस बन गया है। दरअसल, जब एसआई की शिकायत सामने आई तो पुलिस विभाग के मुखिया ने बिना सोचे-समझे जांच एक एसडीओपी को सौंप दी। यह एक बड़ी प्रशासनिक चूक थी। क्योंकि किसी की शिकायत पर एक बड़े अधिकारी की जांच छोटे अधिकारी से नहीं कराई जा सकती है। उन्हें पहले ही एडीजी को जांच सौंप देनी चाहिए थी। उधर, एसडीओपी ने अपनी जांच में जिलाधिकारी को दोषी करार कर दिया और पुलिस विभाग के मुखिया ने यहां भी गलती करते हुए जिलाधिकारी पर कार्यवाही करने का पत्र मुख्यमंत्री को लिख दिया। हालांकि इस मामले में सरकार ने अब दो अफसरों की एक हाईपावर कमेटी बनाई है, जिसमें एक प्रमुख सचिव और एक एडीजी शामिल हैं। यह तथ्य सर्वमान्य है कि जांच में थप्पड़ तो बदलेगा नहीं। फिर यह नासमझी क्यों की गई?

अक्स का आईना



राजनीति और भ्रष्टाचार का चोली-दामन का रिश्ता है। इसलिए भ्रष्ट हुए बिना पूर्णकालिक नेता रहा ही नहीं जा सकता। मुझे यह बात समझ में नहीं आती है, जो शख्स कल तक फटे कपड़ों में घूमता था राजनीति में आते ही आखिर चमचमाते कपड़े कैसे पहनने लगा।

● कुमार विश्वास



बढ़ती बेरोजगारी और घटते उपभोग की वजह से आज देश गरीब हो रहा है। अर्थव्यवस्था में मांग की कमी है और निवेश इसकी राह देख रहा है। मोदी सरकार ने जिस भी अनुभवी सक्षम डॉक्टर की पहचान की है, सभी देश छोड़कर चले गए। ऐसे में देश की अर्थव्यवस्था का इलाज अनाड़ी डॉक्टर कर रहे हैं। फिर अर्थव्यवस्था कैसे सुधरेगी?

● पी. चिदंबरम



अगर आपने इतने लंबे समय तक क्रिकेट नहीं खेला है तो मुझे नहीं लगता कि आप कहीं से भी वापसी कर सकते हैं। आईपीएल में महेंद्र सिंह धोनी का लय में होना काफी अहम होगा। उनके पास आईपीएल के जरिये मौका होगा, वहां उनकी लय काफी अहम होगी और चयनकर्ताओं को देखना होगा कि देश के लिए क्या सर्वश्रेष्ठ है।

● कपिल देव



भारत में बुर्के पर रोक लगनी चाहिए। जो लोग दैत्यों के वंशज हैं, वही लोग बुर्का पहन सकते हैं। इसलिए देश में बुर्का पहनने पर पूरी तरह प्रतिबंध लगना चाहिए। ऐसे ही लोग पीएम मोदी और योगी आदित्यनाथ के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं।

● रघुराज सिंह



मेरे माता-पिता 34 साल पहले ही अलग हो गए थे। ऐसे में जब मेरी शादी टूटने की बारी आई तो मैंने अपने आपसे कहा कि जब मैं साढ़े चार साल की उम्र में अपने माता-पिता के अलग होने का दर्द झेल सकती हूँ तो 37 की उम्र में अपने तलाक से कैसे नहीं उबर पाऊंगी। औरत और मर्द अक्सर ऐसे निर्णय लेने से बचते हैं क्योंकि उन्हें डर लगता है। आपके अंदर यह हिम्मत होनी चाहिए कि यह वक्त भी बीत जाएगा। हम हमारे परिवार-दोस्तों को उनके प्यार और साथ में मीडिया को उनके सपोर्ट के लिए थैंक यू कहना चाहेंगे और सबसे विनती करते हैं कि हमें हमारा समय दें। हम इस मामले में आगे कुछ और नहीं कहेंगे।

● दीया मिर्जा

वाक्युद्ध



आम तौर पर प्रधानमंत्री का एक विशेष दर्जा होता है। प्रधानमंत्री खास तरीके से बर्ताव करता है। उसका एक विशेष कद होता है। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री में ये चीजें नहीं हैं। वे प्रधानमंत्री जैसा बर्ताव नहीं करते हैं। प्रधानमंत्री की कोशिश हमेशा यह रहती है कि वह विपक्ष को नीचा दिखाएं।

● राहुल गांधी

कभी-कभी लोग मुझे डंडा मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन जिस मोदी को इतनी बड़ी मात्रा में माता-बहनों का सुरक्षा कवच मिला हो, उस पर कितने भी डंडे गिर जाएं, उसे कुछ नहीं हो सकता। देश विरोधी ताकतें लगातार मुझ पर निशाना लगा रही हैं, लेकिन जनता हमारे साथ है। इसलिए मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा।

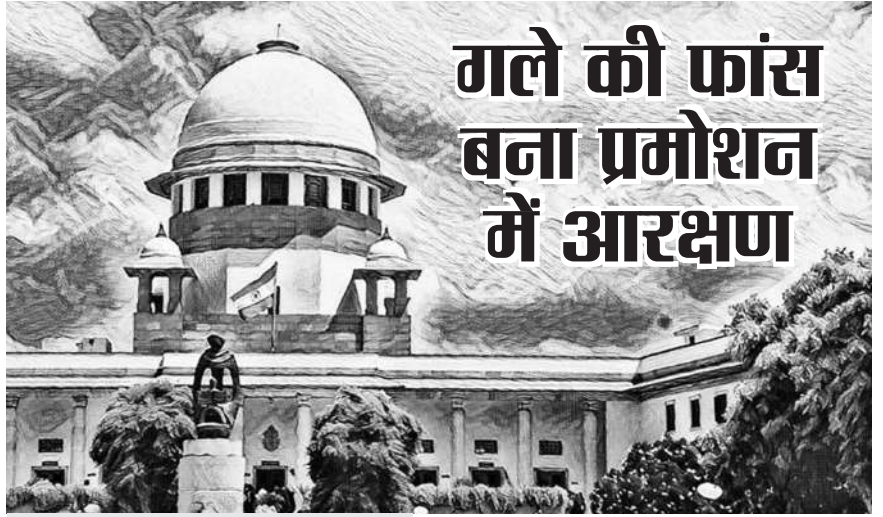
● नरेंद्र मोदी



पदोन्नति में आरक्षण केंद्र सरकार के साथ ही राज्य सरकारों के लिए गले की फांस बन गया है। दरअसल, गत दिनों सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पदोन्नति में आरक्षण मौलिक अधिकार नहीं है और इसे लागू करना या ना करना राज्यों पर निर्भर करता है। कोर्ट के इसी फैसले पर बवाल शुरू हो गया है और केंद्र सरकार पर इसके खिलाफ पुनर्विचार याचिका दायर करने का दबाव बनाया जा रहा है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने गत दिनों उत्तराखंड हाईकोर्ट के उस आदेश को खारिज कर दिया जिसमें पदोन्नति में आरक्षण देने के लिए राज्य सरकार के एससी और एसटी के आंकड़े जमा करने के निर्देश दिए गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि कोई भी राज्य सरकार प्रमोशन में आरक्षण देने के लिए बाध्य नहीं है।

गौरतलब है कि अप्रैल, 2016 में मप्र हाईकोर्ट ने प्रदेश में पदोन्नति में आरक्षण पर रोक लगाने आदेश दिया था। इसके विरोध में राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट चली गई। सुप्रीम कोर्ट में मामले की डबल बेंच सुनवाई कर रही थी। इसमें एम नागराज बनाम भारत संघ प्रकरण को आधार बनाकर सुनवाई की जा रही थी। इस बीच एम नागराज प्रकरण को चुनौती दी गई। जिससे डबल बेंच ने इस मामले को पांच सदस्यीय खंडपीठ में भेज दिया। जिस पर सुप्रीम कोर्ट की पांच सदस्यीय बेंच ने पिछले साल 26 सितंबर के निर्णय में कहा कि पदोन्नति में आरक्षण दिया जाना संवैधानिक बाध्यता नहीं है। राज्य चाहे तो आरक्षण दे सकता है। पीठ के इस फैसले के बाद एक बार फिर से मामला सुप्रीम कोर्ट की डबल बेंच में चला गया। हालांकि प्रमोशन में आरक्षण का विवाद नया नहीं है और समय-समय पर कोर्ट और राज्य सरकार इस बारे में अहम कदम उठा चुके हैं।

उल्लेखनीय है कि मप्र में भाजपा शासन के दौरान तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ऐलान किया था कि कोई भी माई का लाल आरक्षण खत्म नहीं कर सकता। लेकिन उनके शासनकाल में एक भी अधिकारी-कर्मचारी को पदोन्नति में आरक्षण का लाभ नहीं मिल सका। अब मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा है कि उनकी सरकार पदोन्नति में आरक्षण की पक्षधर है। मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड सरकार के सुप्रीम कोर्ट में रखे गए पक्ष के आधार पर पूरी भाजपा को



गले की फांस बना प्रमोशन में आरक्षण

कर्मचारियों को क्रमोन्नति देकर बनाया जाएगा प्रमारी

प्रदेश में करीब पौने चार साल से कर्मचारियों की पदोन्नति पर प्रतिबंध लगा होने से वे परेशान हैं। कर्मचारियों की पदोन्नति में आरक्षण का मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। अब कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति का समय जैसे-जैसे नजदीक आ रहा है, इसलिए राज्य सरकार पदोन्नति के विकल्प तलाश रही है। इनमें से एक विकल्प कर्मचारियों को क्रमोन्नति देकर वरिष्ठ पदों की जिम्मेदारी देना भी हो सकता है। मंत्रालय में गत दिनों हुई उच्च स्तरीय बैठक में मुख्यमंत्री कमलनाथ ने सामान्य प्रशासन मंत्री डॉ. गोविंद सिंह को इस सुझाव का परीक्षण कर रिपोर्ट सौंपने को कहा है। बैठक में कर्मचारियों को सशर्त पदोन्नति देने की बात भी उठी। प्रदेश में 31 मार्च से कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति शुरू हो जाएगी, जिसे देखते हुए मुख्यमंत्री ने बैठक बुलाई थी। सीएम ने सुप्रीम कोर्ट में जल्द सुनवाई के लिए पहल और मामले की मजबूती से पैरवी करने को कहा है। बैठक में मंत्री डॉ. सिंह ने सुप्रीम कोर्ट से सशर्त पदोन्नति करने की इजाजत नहीं मिलने और पदोन्नति में आरक्षण मामले का फैसला नहीं आने तक कर्मचारियों को क्रमोन्नति देकर बड़े पदों की जिम्मेदारी सौंपने का सुझाव दिया।

कटघरे में खड़ा किया है। मुख्यमंत्री ने आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा आरक्षण खत्म करना चाहती है। पदोन्नति में आरक्षण का मामला सुप्रीम कोर्ट में होने के कारण मध्य प्रदेश में तीन साल से पदोन्नतियां नहीं हो पा रही हैं। पिछली सरकार ने इसके चलते आयु सीमा 60 से बढ़ाकर 62 कर दी थी। मामला अब तक नहीं सुलझा। अब कांग्रेस सरकार भी आयु सीमा एक साल बढ़ाने पर विचार कर रही है। उधर, डेढ़ साल की राहत के बाद प्रदेश के अधिकारियों-कर्मचारियों का अप्रैल 2020 से सेवानिवृत्ति का सिलसिला एक बार फिर शुरू हो जाएगा। वर्ष 2020 खत्म होते-होते 12 हजार से ज्यादा कर्मचारी सेवानिवृत्त होंगे। जिससे मंत्रालय सहित विभाग प्रमुख कार्यालयों में कामकाज प्रभावित होने की आशंका जताई जाने लगी है। सेवानिवृत्त होने वालों में शीर्षस्थ कर्मचारियों की संख्या ज्यादा बताई जा रही है। जिनकी जिम्मेदारी अधीनस्थ कर्मचारियों को नहीं सौंपी जा सकती है। 12 हजार से अधिक कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति पर 3600 करोड़ से ज्यादा का भार आएगा। राज्य सरकार ने इस साल बनने वाली स्थिति से निपटने की तैयारी अब तक शुरू नहीं की है। न तो प्रदेश में पदोन्नति शुरू हो पाई है और न ही नई भर्तियां हो सकी हैं। ऐसे में कामकाज प्रभावित होना स्वभाविक है। प्रदेश में 4.62 लाख कर्मचारी और पिछले साल नियमित किए गए 1.78 लाख अध्यापक शामिल हैं।

● कुमार राजेन्द्र

पदोन्नति में आरक्षण मिला नहीं, खर्च हो गए 6 करोड़

मध्यप्रदेश के कर्मचारियों को पदोन्नति में आरक्षण देने की योजना सरकार पर भारी पड़ती नजर आ रही है। हालत यह है कि हजारों कर्मचारी बिना पदोन्नति पाए रिटायर हो गए और सरकार को चार साल में 6 करोड़ रुपए से ज्यादा की चपत लग गई। इस सप्ताह फिर सुप्रीम कोर्ट में मामले को लेकर सुनवाई के आसार हैं। इस पेशी में प्रदेश सरकार द्वारा कर्मचारियों को सशर्त पदोन्नति देने की अर्जी दाखिल करने की तैयारी की है। दरअसल अप्रैल 2016 में मप्र हाईकोर्ट ने प्रदेश में पदोन्नति में आरक्षण पर रोक लगाने का आदेश दिया था। इसके विरोध में राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट चली गई। सुप्रीम कोर्ट में मामले की डबल बेंच सुनवाई कर रही थी। इसमें एम नागराज बनाम भारत संघ प्रकरण को आधार बनाकर सुनवाई की जा रही थी। इसी बीच एम नागराज प्रकरण को चुनौती दी गई।

विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद मप्र भाजपा की परफॉर्मेंस से संघ संतुष्ट नहीं है। देश के सबसे बड़े प्रदेश में भाजपा की कमजोर होती पकड़ को मजबूत करने के लिए भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ ही अब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक भी मैदान में उतरेंगे। स्वयंसेवक घर-घर जाकर राष्ट्रवाद का अलख जगाएंगे। इस काम में किसी तरह की कोताही न हो, इसके लिए समन्वयकों की भी तैनाती की जा रही है। इसके लिए संघ ने पहले इंदौर, फिर गुना उसके बाद भोपाल में रणनीति बनाई।

मप्र में 2018 का विधानसभा चुनाव हारने के बाद भाजपा की मैदानी पकड़ कमजोर पड़ती जा रही है। अपने गढ़ में भाजपा की कमजोर होती ताकत को मजबूत करने के लिए संघ ने अपनी सक्रियता बढ़ा दी है। इसी कड़ी में पहले इंदौर फिर गुना, उसके बाद राजधानी भोपाल में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अहम बैठकें हुईं। इस दौरान संघ प्रमुख मोहन भागवत ने मप्र और छत्तीसगढ़ के भाजपा और संघ के आनुषांगिक संगठनों के पदाधिकारियों से चर्चा की। राजधानी में तीन दिवसीय बैठक में देश की वर्तमान स्थिति के साथ ही मप्र में भाजपा नेताओं पर छाई निष्क्रियता पर भी चिंता जताई गई। इस दौरान भागवत ने संगठन के पदाधिकारियों से संवाद भी किया। संघ प्रमुख ने आनुषांगिक संगठनों और भाजपा नेताओं से संगठन को मजबूत करने और आपसी तालमेल बनाकर काम करने की बात कही।

संघ प्रमुख मोहन भागवत ने भाजपा और आनुषांगिक संगठनों के बीते एक साल के कामकाज की भी समीक्षा की। साथ ही पिछली बैठक में दिए गए कार्यक्रमों की स्टेटस रिपोर्ट ली गई। बता दें कि, बैठक के तीसरे दिन आनुषांगिक संगठनों की बैठक में मध्य के सभी 34 आनुषांगिक संगठन के पदाधिकारी शामिल हुए। साथ ही, बैठक में मध्य प्रदेश भाजपा के तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह, संगठन महामंत्री सुहास भगत, केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद पटेल और फगन सिंह कुलस्ते, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रभात झा, राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय, पूर्व मंत्री नरोत्तम मिश्रा, नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव समेत कई बड़े और छोटे नेता शामिल हुए। जबकि छत्तीसगढ़ से भाजपा के रामविचार नेताम, सरोज पांडेय समेत कई बड़े नेता शामिल हुए। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम रमन सिंह भी एक बैठक में शामिल हुए। हालांकि, मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान दिल्ली चुनाव में व्यस्त होने के कारण बैठक में शामिल नहीं हो सके।

संघ प्रमुख मोहन भागवत ने एमपी और छत्तीसगढ़ के जिला और विभाग प्रचारकों के साथ मंथन किया। इसमें सीएए, राम मंदिर और गौसेवा समेत कई और अहम मुद्दों पर चर्चा की गई। संघ की ओर से मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में सीएए के समर्थन अभियान को चलाने के बाद सामने आए नतीजों की रिपोर्ट तलब की। रिपोर्ट पेश करते हुए भाजपा समेत आनुषांगिक संगठनों ने



कमजोर हो रही पकड़

संघ के स्वयंसेवक आदिवासियों के बीच डालेंगे डेरा

राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का पूरा फोकस अब 2021 में होने वाली जनगणना और सीएए पर है। उसका ध्यान आदिवासियों पर है कि कहीं वो इस अगली जनगणना में अपने नाम के साथ कोई अन्य धर्म ना लिख दें। संघ का मानना है कि पिछली जनगणना में ऐसा हुआ था इसलिए हिन्दू आबादी का प्रतिशत कम हो गया था। आदिवासियों को जागरूक करने के लिए स्वयंसेवकों को उन इलाकों में अभियान चलाने की जिम्मेदारी दी गई है। 2021 में होने जा रही जनगणना अब संघ का सबसे महत्वपूर्ण एजेंडा है। संघ ने भोपाल में हुई बैठक में नागरिकता संशोधन कानून के साथ ही 2021 की जनगणना को अपने एजेंडे में रखा है। बैठक में बताया गया कि ऐसी जानकारी मिल रही है कि आदिवासियों के बीच कुछ ऐसे संगठन काम कर रहे हैं जो जनगणना के समय आदिवासियों से हिन्दू की जगह अन्य जाति या धर्म लिखवाना चाहते हैं। बैठक में बताया गया कि 1991 की जनगणना में हिन्दुओं की संख्या 84 प्रतिशत थी जो 2011 में घटकर 69 प्रतिशत हो गई।

बताया कि जिलास्तर पर उनकी ओर से सीएए का समर्थन जुटाने के लिए क्या-क्या कार्यक्रम चलाए गए। इस दौरान उन विवादों पर भी चर्चा की गई, जो सीएए का समर्थन जुटाने के दौरान कुछ जिलों में हुए। सूत्रों के मुताबिक, संघ मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में सीएए के पक्ष में माहौल बनाने के काम करेगा। संघ प्रचारकों द्वारा सीएए पर जनसमर्थन जुटाने के लिए सभाएं और गांव स्तर तक संपर्क अभियान चलाने की भी बात कही।

सूत्रों के मुताबिक बैठक में संघ प्रमुख मोहन भागवत की आनुषांगिक संगठनों के कामकाज के साथ ज्वलंत मुद्दों जैसे जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाने, तीन तलाक और सीएए के बाद प्रमुख संगठनों की क्या और कैसी भूमिका होनी चाहिए, इस पर चर्चा हुई। समाज में सामाजिक समरसता बनी रहे, परिवार को जोड़कर रहने के लिए प्रेरित किया जाए, गौवंश की रक्षा और स्वच्छता अभियान पर काम किया जाए, इस विषय पर सरसंचालक डॉ. मोहन भागवत ने युवाओं और महिलाओं पर विशेष फोकस करने का निर्देश दिया।

संघ प्रमुख मोहन भागवत ने भाजपा और अन्य संगठनों से जुड़े लोगों के बीच चाल, चरित्र और चेहरे पर उठ रहे सवालियों पर चिंता जताई है। साथ ही हिदायत दी है कि वे अपने आचरण पर भी गौर करें। सूत्रों का कहना है कि पिछले दिनों हनीट्रैप मामले के सामने आने और कई अन्य मामलों में भाजपा नेताओं और प्रचारकों के जुड़े होने की तरफ इशारों-इशारों में उन्होंने यह बात

कही। सूत्रों के अनुसार, भागवत ने संगठनों से जुड़े प्रतिनिधियों को संघ की साख याद दिलाई। साथ ही कहा, समाज उनकी तरफ देखता है, अगर उनके आचरण में गिरावट आएगी, तो यह स्वीकार्य नहीं होगा। लिहाजा, सभी को अपने आचरण में बदलाव लाना होगा, अनुशासित रहना होगा।

संघ प्रमुख ने भाजपा नेताओं और अन्य संगठनों से जुड़े लोगों को संघ की सामाजिक प्रतिष्ठा याद दिलाई। साथ ही उन्हें अपने अतीत से सीख लेने पर जोर दिया। इतना ही नहीं, नेताओं की कार्यशैली और उन पर उठे सवालों पर सीधे तौर पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि संघ समाज के बीच जाकर समस्याओं और राष्ट्र की चुनौतियों के लिए लोगों को तैयार करता है, मगर राज्य के कई नेताओं के सवालों में घेरने से पूरे संगठन की छवि पर असर पड़ता है, इसे रोकने के प्रयास होने चाहिए।

सूत्रों के अनुसार, मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ में डेढ़ दशक तक भाजपा सत्ता में रही और बीते एक साल से सत्ता से बाहर है। इस एक वर्ष की अवधि में संगठनों ने क्या काम किया, इसका भी ब्यौरा संघ प्रमुख ने लिया। सर संघचालक भागवत ने प्रांत व जिले में काम कर रहे विभाग, जिला एवं प्रांत प्रचारकों से चर्चा करते हुए कहा कि धर्म संस्कृति एवं समाज के विकास को पूर्ण करने का दायित्व हमारा है। इसमें सभी स्वयंसेवकों को जुटना होगा। समस्याओं के समाधान के लिए ऐसे सामर्थ्यवान स्वयंसेवक खड़े करने हैं जो परिस्थिति के साथ स्वयं की भूमिका को तय करने के लिए तैयार रहें। भागवत ने ग्राम विकास के कार्यों पर चर्चा की एवं वर्तमान कार्यों की समीक्षा के साथ आगामी वर्ष के कार्यक्रमों को सामने रखा।

मध्यप्रदेश-छत्तीसगढ़ भाजपा व संघ और अन्य संगठन के नेताओं से भागवत ने कहा कि वैचारिक एवं सामाजिक नेतृत्व तैयार करने के लिए सभी अपने संगठनों में अनुशासित, धैर्यवान, सक्षम एवं स्वावलंबी कार्यकर्ताओं को जोड़ें। अपने कार्यों का विस्तार ग्रामीण स्तर तक करें, ताकि आने वाले समय में हम सामाजिक चुनौतियों एवं कुरीतियों का सामना करने में सक्षम और स्वावलंबी बन सकें। सभी संगठनों के कार्यकर्ता एक-दूसरे के पूरक बनकर स्वयंसेवक भाव से अपने कार्यों का विस्तार करें एवं संगठन को मजबूत बनाएं। उन्होंने कहा कि हमारे कार्य के प्रति समाज में विश्वास एवं

स्वीकार्यता बढ़ी है। उल्लेखनीय है कि इस दो दिवसीय समन्वय बैठक में विविध संगठनों के मध्यप्रदेश एवं छत्तीसगढ़ के प्रमुख कार्यकर्ता शामिल हुए।

ग्राम विकास के लिए चयनित गांवों को संघ ने दो भागों में विभाजित किया है। प्रभात ग्राम जिसमें सेवा कार्यों के बाद परिवर्तन दिखाई देने लगा है। उदय ग्राम, जहां काम अभी शुरू हुआ है। मालवा प्रांत में 193 उदय ग्राम एवं 120



सक्षम कार्यकर्ता होंगे तैनात

सीएए के मुद्दे पर देशभर में मंचे बवाल के बीच राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने अपना रोडमैप तैयार कर लिया है। संघ और उससे जुड़े भाजपा सहित 34 संगठन अब सीएए, राम मंदिर, एनआरसी के मुद्दों पर सरकार के पक्ष में माहौल बनाने के लिए गांव-गांव तक ऐसे सक्षम कार्यकर्ताओं की टीम खड़ी करेंगे जो विरोधियों के आरोपों का मुखरता से जवाब दे सकें। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मध्यक्षेत्र (मध्यप्रदेश-छत्तीसगढ़) की बैठक के अंतिम दिन प्रश्नोत्तर सत्र के दौरान संघ प्रमुख मोहन भागवत ने एक सवाल के जवाब में साफ कहा कि सीएए जैसे विषयों पर कुछ लोग यदि भ्रम का वातावरण बनाते हैं तो उसे समाप्त करना हमारा काम है। हमें इसके लिए गांव स्तर तक सक्षम कार्यकर्ताओं की टीम खड़ी करना चाहिए। बैठक के दौरान संघ के सभी आनुषांगिक संगठनों से पिछले एक साल में किए गए कार्यों का पूरा रिपोर्ट कार्ड लेने के साथ ही अगले साल की कार्ययोजना पर भी चर्चा हुई। संघ की इस बैठक में प्रभात-उदय ग्राम, परिवार इकाई को सशक्त करने और समाज को संगठित करने के लिए सभी संगठनों को नए कार्यक्रम दिए गए।

प्रभात ग्राम हैं। इसी प्रकार मध्य भारत, महाकौशल प्रांत एवं छत्तीसगढ़ में भी उदय ग्रामों एवं प्रभात ग्रामों की संख्या क्रमशः 21 एवं 8, 54 एवं 12 और 27 एवं 14 है।

सूत्रों के अनुसार अगामी नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव में पार्टी का जनाधार मजबूत करने के लिए संघ मोर्चा संभालेगा। बैठक में निर्णय लिया गया कि प्रदेश में भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ ही अब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक भी मैदान में उतरेंगे। इस दौरान गोष्ठी के साथ ही स्वयंसेवक घर-घर जाकर राष्ट्रवाद का अलख जगाएंगे। इस काम में किसी तरह की कोताही न हो, इसके लिए समन्वयकों की भी तैनाती की जा रही है।

संघ के सूत्रों के अनुसार लोकसभा चुनाव में स्वयंसेवकों ने जनता के बीच हजारों बैठकें की थीं। इस बार बैठकों की संख्या और अधिक करने का लक्ष्य रखा गया है ताकि समाज के सभी वर्गों तक अपनी बात पहुंचाई जा सके। दरअसल, इन दिनों सीएए को लेकर

फैलाए जा रहे दुष्प्रचार से संघ भी चिंतित है। संघ का मानना है कि वोट बैंक की राजनीति में भाजपा विरोधी पार्टियां सीएए को लेकर लोगों को गुमराह कर रही हैं। इसे ध्यान में रखकर लोकसभा की तुलना में ज्यादा बैठक करने के साथ ही जनसंपर्क अभियान चलाने का फैसला किया गया है। स्वयंसेवक लोगों से मिलकर उन्हें सीएए की सच्चाई बताएंगे। इसके साथ ही देश को कमजोर करने की चल रही साजिश के बारे में बताएंगे।

संघ की बैठक में स्वयंसेवकों को आदिवासियों को वास्तविकता से परिचित कराने का लक्ष्य दिया गया है। स्वयंसेवक अब आदिवासियों के बीच डेरा डालेंगे। उन्हें वर्तमान परिस्थितियों से रूबरू कराकर भ्रम दूर करेंगे। सीएए के साथ ही अब स्वयंसेवक जनगणना को लेकर भी घर-घर जाएंगे। नागरिकता संशोधन कानून को लेकर देशभर में विरोध देखने को मिला है। संघ का मानना है कि लोगों के बीच भ्रम है। नेताओं के बाद अब संघ के स्वयंसेवक मैदान में उतरेंगे, लोगों के बीच जाकर जनगणना के साथ ही नागरिकता संशोधन कानून की वास्तविकता बताएंगे। संघ ने मप्र-छत्तीसगढ़ के नेताओं से सीएए को लेकर चले जनजागरण अभियान की रिपोर्ट मांगी है।

● अरूण दीक्षित

मध्यप्रदेश में स्वच्छ भारत योजना में बड़ा घोटाला हुआ है। तस्वीरों और पेपर पर तो 4.5 लाख शौचालय दिख रहे हैं। लेकिन स्पॉट पर जाने पर एक भी नहीं दिखा है। ऐसे में सवाल है कि क्या वह वहां से पलायन कर गए या फिर कोई बड़ा घोटाला हुआ है। इसे बनाने में 540 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। जांच में यह बात सामने आई है कि जिन जगहों पर टॉयलेट निर्माण की बात कहीं जा रही है, वहां एक भी टॉयलेट नहीं मिले हैं। हालांकि प्रशासन के पास सभी टॉयलेट्स की जीपीएस-टैग की गई तस्वीरें हैं। पूरे खुलासे के बाद सरकार उन पर खर्च किए गए पैसे वसूलने की तैयारी कर रही है। दरअसल, यह घोटाला 2017 गुना में हुए शौचालय के दरवाजे के घोटाले की याद दिला रहा है। जहां 42,000 शौचालयों में दस किलो से भी कम वजन का दरवाजा लगवाया गया था। जिससे सरकार को करोड़ों का नुकसान हुआ था।

पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग की जांच में यह बात सामने आई है कि इन शौचालयों का निर्माण 2012-2018 के बीच हुआ है। अधिकारियों ने मानना है कि विभाग को जो तस्वीरें भेजी गई थीं, वह कहीं और से खींची गई थी। क्योंकि शौचालय के निर्माण के बाद विभाग को सबूत के तौर पर तस्वीर पेश करनी होती है। तस्वीर पेश कर अधिकारी और ठेकेदार निर्माण के पैसे निकाल लिए। इसका खुलासा तब हुआ जब बैतूल के लक्कड़जाम पंचायत के ग्रामीणों ने अधिकारियों के पास जाकर शिकायत की। चार लाभार्थियों चैतराम, राम किशोर, कंसराज और शंभुदयाल को पता ही नहीं था कि उनके नाम पर शौचालय का निर्माण हुआ है। लेकिन सरकारी रिकॉर्ड में वह शौचालय योजना के लाभार्थी हैं। यह ही नहीं शौचालय के साथ लाभार्थियों की तस्वीर भी थी। इनकी शिकायत पर जांच शुरू हुई तो पता चला कि ये तस्वीर पड़ोसी के घर की हैं। वहीं, जब लक्कड़जाम पंचायत में विस्तार से जांच की गई तो सभी शिकायतें सही मिलीं।

बैतूल पंचायत के सीईओ एमएल त्यागी ने बताया कि जिस आरोपी ने गड़बड़ी की है, उससे सात लाख रुपए की वसूली की जाएगी। उसने वसूली के खिलाफ अपील की है, लेकिन जुर्माना बरकरार रखा गया है। एक बार वसूली होने के बाद, हम आईपीसी के तहत कार्रवाई करेंगे। इस रिपोर्ट के बाद विभाग अलर्ट हो गया। उसके बाद पंचायत और ग्रामीण विभाग ने पूरे राज्य में 4.5 लाख पेपर टॉयलेट की पहचान की। जिनका निर्माण सिर्फ कागजों पर हुआ है। एक अधिकारी ने कहा कि एक तरीके से 540 करोड़ रुपए के शौचालय गायब हैं। मध्यप्रदेश में स्वच्छ भारत मिशन के उपनिदेशक



प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन के तहत देशभर में शौचालय निर्माण का अभियान शुरू करवाया था। उनकी पार्टी के कार्यकाल में मप्र में शौचालय के निर्माण का काम तेज गति से हुआ। लेकिन अब जब इसकी जांच हुई है तो यह बात सामने आई है कि 540 करोड़ रुपए के शौचालय केवल कागजों पर ही बना दिए गए।

कागज पर शौचालय

ये है पेमेंट की प्रक्रिया

मध्यप्रदेश में स्वच्छ भारत मिशन के उपनिदेशक अजीत तिवारी ने बताया कि शौचालय निर्माण में भुगतान करने की दो प्रक्रियाएं थीं। पंचायतों को घरों में शौचालय निर्माण पूरा करने पर पैसा दिया जाता था या फिर सरकार सीधे लाभार्थियों के खाते में शौचालय बनने के बाद सीधे 12,000 रुपए ट्रांसफर कर देती है। दोनों मामलों में यह स्पष्ट है कि पैसा कहां गया। इसलिए लापता शौचालयों के लिए जिम्मेदार लोगों को उन्हें वास्तविक निर्माण करना होगा, या फिर उन्हें मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने यह भी कहा कि हमारा एकमात्र उद्देश्य यह है कि 2012 में पहचाने गए लक्ष्य को 100 फीसदी पूरा करना है। वहीं, जब तिवारी से पूछा गया कि घोटालेबाजों ने तकनीक को कैसे हरा दिया। इस पर उन्होंने जवाब दिया कि जीपीएस लगभग छह मीटर तक ही सटीक है। ऐसा संभव है कि 2012 से पहले निर्मित शौचालयों के नाम पर छह मीटर के भीतर शौचालयों के चित्र अपलोड किए गए थे। दूसरी जांच पूरी होने के बाद चीजें अधिक स्पष्ट होंगी।

अजीत तिवारी ने कहा कि 2012 में प्रदेश में एक सर्वेक्षण किया गया था और राज्य में बिना शौचालय के 62 लाख से अधिक गरीबी रेखा वाले घरों की पहचान की गई थी। 2 अक्टूबर 2018 को, इन सभी शौचालयों का निर्माण पूरा हो गया था। लेकिन यह सुनिश्चित करने के लिए शौचालय वास्तव में मौजूद हैं और 100 फीसदी पूर्ण हैं, हमने 21,000 स्वयंसेवकों का उपयोग करके एक सर्वेक्षण और भौतिक सत्यापन किया। इस सर्वेक्षण के दौरान, लगभग 4.5 लाख शौचालय गायब पाए गए।

उन्होंने यह भी कहा कि इस रिपोर्ट के बाद अब दूसरी जांच भी जिला स्तर के अधिकारियों के द्वारा की जा रही है। हमें उम्मीद है कि यह कुछ महीनों में पूरी हो जाएगी। फिर हमारे पास स्वच्छ मिशन शौचालयों की संख्या का एक स्पष्ट चित्र होगा। हमारा मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सरकार द्वारा निर्मित शौचालय या संपत्ति वास्तव में मौजूद है कि नहीं। उल्लेखनीय है कि पूर्व कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव ने भी शौचालय निर्माण में हुए घोटाले की जांच के लिए मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है।

● राजेश बोरकर

मद्रास का प्रशासनिक ढांचा इन दिनों अनबैलेंस हो गया है। आलम यह है कि प्रदेश में एसीएस, प्रमुख सचिव, एडीजी और आईजी स्तर के अधिकारियों की भरमार हो गई है। इसका असर यह हो रहा है कि कई वरिष्ठ अधिकारी बिना काम और जिम्मेदारी के ही बैठे हैं।



**सिस्टम हुआ
अनबैलेंस**

मध्य प्रदेश में प्रमोशन के नियमों का पालन नहीं होने से प्रशासनिक ढांचा अनबैलेंस हो रहा है। सच कहा जाए तो एसीएस, प्रमुख सचिव, एडीजी और आईजी की संख्या में बाढ़ आने से प्रशासनिक पिरामिड सिस्टम बिगड़ गया है। जबकि दूसरे अधिकारियों के अधिकार में बेवजह का अतिक्रमण किया जा रहा है। बिगड़ते सिस्टम की वजह से कैबिन की संख्या तो लगातार बढ़ ही रही है, बल्कि मैदानी पुलिस की हालत भी कुछ ठीक नहीं है। उसके बाद भी आलम यह है कि आईएसएस अधिकारियों को सचिव से प्रमुख सचिव बनाया गया है, लेकिन यह आईएसएस अफसरों को सचिव से प्रमुख सचिव बनाने का समय आ गया था। अब ऐसे में प्रमुख सचिव की भरमार हो गई और अब वे पोस्टिंग का इंतजार कर रहे हैं। गौरतलब है कि हाल ही में 1996 बैच के 6 आईएसएस अधिकारियों को सचिव से प्रमोशन करके प्रमुख सचिव बनाया गया है। इनमें डीपी आहूजा, नीतीश कुमार व्यास, फैज अहमद किदवई, अमित राठौर, उमाकांत उमराव और कैरोलिन खुंगवार देशमुख शामिल हैं। इससे यह स्थिति निर्मित हो गई है कि प्रदेश में एसीएस और प्रमुख सचिव स्तर के अधिकारियों की भरमार हो गई है।

वहीं आईपीएस अधिकारियों में तो स्थिति यह है कि निचले पदों को समायोजित करके एडीजी के पद बढ़ाए गए हैं। मंत्रालय सूत्रों का कहना है कि आईएसएस अधिकारियों के लिए राज्य सरकार पूरे प्रयास कर रही है कि केंद्र सरकार से उसे

दिल्ली जाने वालों की कतार आने वाला कोई नहीं

प्रदेश में यह भी देखने को मिल रहा है कि बड़ी संख्या में अधिकारी दिल्ली जाने की तैयारी कर रहे हैं। वहीं कईयों को हाल ही में दिल्ली भेजा गया। 1994 बैच के आईएसएस हरिरंजन राव, 1991 बैच के प्रमोद अग्रवाल, 1992 बैच के वीएल कांतारव और नीलम शमी राव की केंद्रीय प्रतिनियुक्ति हुई है। वहीं कई अन्य अफसर हैं जो दिल्ली जाने की जुगाड़ लगा रहे हैं। वहीं 2 दर्जन से अधिक आईएसएस पहले से ही केंद्र में प्रतिनियुक्ति पर हैं। यही हाल आईपीएस अफसरों का भी है। हाल ही में कुछ अफसरों को प्रतिनियुक्ति पर दिल्ली भेजा गया है। वहीं मद्रास कैडर के 1987 बैच के आईपीएस संजीव कुमार सिंह सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) की केंद्रीय प्रतिनियुक्ति से कार्यमुक्त हो गए हैं। वे जल्द ही प्रदेश लौट रहे हैं और इसी महीने सेवानिवृत्त हो जाएंगे। उनके रिटायरमेंट से महानिदेशक पद पर पदोन्नति का इंतजार कर रहे 1987 बैच के उनके साथियों को फिलहाल कोई लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि उन्हें प्रोफार्मा पदोन्नति भी नहीं दी गई थी। वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी संजीव कुमार सिंह अक्टूबर 2018 में एडीजी नक्सल ऑपरेशन के पद से बीएसएफ में केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर गए थे। उनका 29 फरवरी 2020 को रिटायरमेंट होने की वजह से बीएसएफ ने उन्हें पिछले दिनों कार्यमुक्त कर दिया है।

अनुमति मिल जाए, लेकिन आईपीएस अफसरों के मामले में फिलहाल आईजी से एडीजी पद की डीपीसी रोक दी गई है। बताया जा रहा है कि पूर्व में एडीजी हो चुके पद रिक्त होने के बाद ही नए प्रमोशन की राह खुल सकेगी। हालांकि एडीजी के प्रमोशन के इंतजार में बैठे 1995 बैच ने 25 साल की सेवा पूर्ण कर ली है। आईएसएस अफसरों के मामले में ऐसा नहीं है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश पुलिस विभाग में इस वक्त एडीजी के 16 पद हैं, लेकिन अफसरों की संख्या 40 हो गई है।

16 अधिकारी तो किसी न किसी पद पर हैं, लेकिन बाकी अफसरों को एडजस्ट करने का काम किया गया। पीएचक्यू में इन अफसरों के लिए शाखाओं को बढ़ाया गया। हालांकि अब पुलिस मुख्यालय में भी एडीजी अफसरों को एडजस्ट करने की जरा भी गुंजाइश नहीं है। ऐसे में इन अफसरों को फोल्ड जैसी पोस्टिंग के पद पर सिर्फ बंद कैबिन देने का काम किया जा रहा है।

मध्यप्रदेश में अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों की पदोन्नति और प्रशासनिक सर्जरी करने में दीर्घकालिक सोच दिखाई नहीं दे रही है। इससे पदोन्नति-तबादलों से कई विसंगतियां पैदा हो गई हैं। पुलिस में प्रमोशन के द्वार पर खड़े अफसरों को आईजी बना दिया, जिससे वे आज जोन में एडीजी बनकर बैठ गए हैं तो जिलों में एसपी बने अधिकारी अपने सुपरविजन अधिकारी डीआईजी के समकक्ष हो गए हैं। लंबा समय हो जाने के बाद राज्य शासन इन विसंगतियों को दूर नहीं कर पा रहा है।

भारतीय पुलिस सेवा के 1994 बैच के अधिकारियों देवप्रकाश गुप्ता, राजा बाबू सिंह, आशुतोष रॉय को शासन ने 2019 में आईजी बनाकर भेजा था, जबकि उनका एडीजी पद पर प्रमोशन लंबित हो गया था। पदोन्नति के समय उन्हें जोन में एडीजी बना दिया गया, जबकि ग्वालियर, चंबल व होशंगाबाद पुलिस जोन आईजी के पद हैं। वहीं, इंदौर जैसे बड़े पुलिस जोन में राज्य शासन ने जनवरी 2020 में एडीजी को हटाकर आईजी की पदस्थापना की। जबकि इंदौर और भोपाल पुलिस जोन में एडीजी की भी पदस्थापना की जाती रही है। आईपीएस के 2006 के बैच को राज्य शासन ने डीआईजी पद पर पदोन्नति दे दी है, लेकिन इनमें से कुछ अधिकारियों को आज भी जिलों में ही पदस्थ कर रखा है। शासन ने प्रमोट हुए कुछ अफसरों को हटाकर दूसरे अधिकारियों की पदस्थापना भी की, मगर ज्यादातर को नहीं बदला। इससे एक समान रैंक के अधिकारियों के सुपरविजन व मातहत हो जाने की स्थिति बन गई है।

● सुनील सिंह



बेहतर पुलिसिंग कर प्रदेश की तरक्की में सहभागी बनें पुलिस अधिकारी: बच्चन

मध्यप्रदेश पुलिस अकादमी, भौरी के परेड मैदान में पुलिस के 41वें बैच के उप-पुलिस अधीक्षकों का भव्य दीक्षांत समारोह किया गया। स्वाभिमान से ऊंचा मस्तक, अनुशासित कदम, अदम्य साहस से भरा सीना और देशभक्ति के जज्बे के साथ जब आकर्षक दीक्षांत परेड आगे बढ़ी, तो सभी रोमांचित हो गए। गृहमंत्री बाला बच्चन ने दीक्षांत परेड की सलामी ली और परेड का निरीक्षण किया। पुलिस महानिदेशक विजय कुमार सिंह की मौजूदगी में परिवीक्षाधीन 37 उप-पुलिस अधीक्षक विधिवत रूप से मध्यप्रदेश पुलिस की मुख्य धारा में शामिल हो गए। इनमें 17 महिला उप पुलिस अधीक्षक शामिल हैं।

गृहमंत्री बाला बच्चन ने कहा कि दीक्षांत परेड में अधिकारियों के जोश और जज्बे को देखकर हमें भरोसा हो गया है कि जनता को

बेहतर सेवाएं देने में सफल होंगे। उन्होंने अधिकारियों का आवाहन किया कि बेहतर पुलिसिंग कर मध्यप्रदेश पुलिस का नाम रोशन करें। साथ ही, मध्यप्रदेश की तरक्की में सहभागी बनें।

दीक्षांत परेड का नेतृत्व उप-पुलिस अधीक्षक भावना दांगी ने किया। परेड टू आई सी की भूमिका गौरव पाटिल ने निभाई। मध्यप्रदेश पुलिस प्रशिक्षण अकादमी भोपाल में एक वर्ष के कठिन प्रशिक्षण में तपकर निकले कुल 37 उप-पुलिस अधीक्षकों ने दीक्षांत परेड में हिस्सा लिया। सभी उप-पुलिस अधीक्षक दीक्षांत परेड के बाद राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को साक्षी मानकर देश भक्ति एवं राष्ट्र सेवा की शपथ लेकर मध्यप्रदेश पुलिस का हिस्सा बन गए। अकादमी के पुलिस अधीक्षक संजय सिंह ने प्रशिक्षुओं को शपथ दिलाई।

रेत ठेकेदारों की समस्याओं का शीघ्र होगा निराकरण: जायसवाल

खनिज साधन मंत्री प्रदीप जायसवाल ने खनिज अधिकारियों एवं रेत ठेकेदारों की संयुक्त बैठक में कहा कि खदान संचालन के लिए समस्त कार्रवाई शीघ्र पूरी करें। उन्होंने कहा कि प्रदेश में रेत नियम-2019 के अंतर्गत निविदा की कार्रवाई पूर्ण हो चुकी है। सभी ठेकेदार एलओआई संबंधी समस्त औपचारिकाएं पूरी करें। मंत्री जायसवाल ने बताया कि वर्तमान में पंचायतों की खदानें नवीन ठेकेदारों के नाम जारी करने के लिए राज्य शासन द्वारा निर्देश जारी किए जा चुके हैं। उन्होंने बताया कि राज्य खनिज निगम के नाम पर उपलब्ध वैधानिक स्वीकृति की कार्यवाही पर्यावरण स्वीकृति के लिए सिया में प्रचलन में है। मंत्री जायसवाल ने रेत ठेकेदारों से अपेक्षा की कि वे अपने जिले के ठेके के संचालन तथा वैधानिक अनुमतियां प्राप्त करने तथा अनुबंध आदि के संबंध में समस्त सुझाव लिखित में दें। उन्होंने कहा कि यदि अत्यंत आवश्यक हो, तो रेत का अवैध परिवहन रोकने के लिए जिला प्रशासन के सहयोग से ऐसे दो-तीन स्थानों पर नाके अवश्य स्थापित करें।



ऋण माफी से किसान और सहकारी संस्थाएं दोनों मजबूत होंगी: शर्मा

जनसंपर्क, विधि एवं अध्यात्म मंत्री पीसी शर्मा ने कहा है कि सरकार के द्वारा ऋण माफी से किसान तथा सहकारी संस्थाएं दोनों मजबूत होंगी।

सहकारी बैंकों की आर्थिक स्थिति में भी सुधार होगा। मुख्यमंत्री कमलनाथ ने पदभार ग्रहण करने के 2 घंटे के भीतर प्रदेश के 55 लाख किसानों का फसल ऋण माफ करने के आदेश पर हस्ताक्षर किए। मंत्री शर्मा ने गत दिनों रीवा में कृष्णा राजकपूर आडिटोरियम में आयोजित विशाल सहकारिता सम्मेलन के शुभारंभ सत्र को संबोधित कर रहे थे। मंत्री शर्मा ने कहा कि रीवा में स्व. श्रीनिवास तिवारी ने सहकारिता से जन-जन को जोड़कर सशक्त सहकारिता का निर्माण किया। उन्होंने हर किसान को इससे जोड़ने का सफल प्रयास किया। शर्मा ने कहा कि हमारी सरकार किसानों के कल्याण के लिए लगातार प्रयास कर रही



है। प्रदेश के किसान मजबूत और समृद्ध होंगे तो पूरा प्रदेश समृद्ध होगा। मंत्री शर्मा ने सम्मेलन में पारित प्रस्ताव के बिन्दुओं पर कार्यवाही की जाएगी।

सम्मेलन में जनसंपर्क मंत्री ने कहा कि प्रदेश के कालेजों में 3 हजार पद मंजूर किए गए हैं। मुख्यमंत्री ने एक साल में आम जनता से किए गए 365 वचन पूरे किए हैं। मंत्री शर्मा ने शीघ्र ही राम वन पथ गमन के निर्माण कार्य प्रारंभ होने तथा श्रीलंका में सीता माता के मंदिर निर्माण की बात कही। उन्होंने कहा कि प्रस्ताव प्राप्त होने पर रीवा के चिरहुला मंदिर तथा लक्ष्मणबाग मंदिर परिसर के लिए राशि मंजूर कर दी जाएगी। समारोह की अध्यक्षता करते हुए सिद्धार्थ तिवारी ने सहकारिता के उद्देश्यों तथा रीवा में सहकारिता आंदोलन के संबंध में अपने विचार व्यक्त किए।

ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार मुहैया कराना राज्य शासन की प्राथमिकता: पटेल

पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री कमलेश्वर पटेल ने कहा है कि ग्रामीण आजीविका मिशन के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार मुहैया कराना राज्य शासन की प्राथमिकता है। इसके लिए मिशन का अमला अभियान चलाकर ग्रामीण महिलाओं को स्व-सहायता समूह के रूप में संगठित करें। पटेल ने राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन की राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक में यह निर्देश दिए। मंत्री पटेल ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में स्व-सहायता समूह रोजगार के सशक्त माध्यम हैं। आवश्यकता इन समूह में सदस्यों को कार्य-दक्षता प्रशिक्षण मुहैया कराने की है। उन्होंने कहा कि समूह द्वारा उत्पादित माल को बाजार उपलब्ध कराने के लिए मिशन प्रयास करें। पटेल ने कहा कि मिशन से जुड़े अधिकारी-कर्मचारी ग्रामीण



क्षेत्रों में जाएं, तो समूह सदस्यों के साथ अनिवार्य रूप से चर्चा करें तथा उनकी समस्याओं का त्वरित निराकरण सुनिश्चित करें। उन्होंने सभी जिला इकाइयों को स्व-सहायता समूह गठन और बैंक संबद्धता के लक्ष्य निर्धारित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जो जिले आवंटित लक्ष्य की पूर्ति नहीं कर पाएंगे, उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई

की जाएगी। पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री कमलेश्वर पटेल ने मंत्रालय में राज्य ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण (एमपीआरआरडीए) की कार्यकारिणी की 24वीं बैठक में निर्देश दिए कि ग्रामीण क्षेत्र की सड़कों का प्राथमिकता से संधारण कराएं। साथ ही, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में गारन्टी पीरियड की सड़कों का संधारण संबंधित ठेकेदार से कराया जाए।



सरकार की नीयत साफ, बिजली का बिल हाफ, किसानों का कर्जा माफ

आपकी सरकार-आपके द्वार कार्यक्रम को संबोधित करते हुए ऊर्जा मंत्री प्रियव्रत सिंह ने कहा कि राज्य सरकार ने वचन-पत्र में किए लगभग 50 फीसदी वायदों को एक साल में पूरा किया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री कमलनाथ के नेतृत्व में सरकार ने बिजली का बिल हाफ और किसानों का कर्जा माफ करके अपने वचन को एक वर्ष के भीतर ही पूरा किया है।

मंत्री सिंह ने कटनी में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के 19 लाख किसानों के बिजली के बिल आधे माफ कर दिए गए तथा ढाई लाख किसानों के अस्थाई कनेक्शन के शुल्क की दरें भी आधी की गई हैं। सिंह ने बताया कि कटनी जिले के कुल 2 लाख 39 हजार घरेलू बिजली उपभोक्ताओं में से एक लाख 84 हजार 685 उपभोक्ताओं से इंदिरा गृह ज्योति योजना का लाभ देकर मासिक बिल केवल 100 रुपए लिया जा रहा है। मंत्री सिंह ने कहा कि 'जय किसान फसल ऋण माफी' योजना के प्रथम चरण में 59 हजार से 2 लाख रुपए तक के ऋण 31 मार्च, 2020 के पहले तक माफ कर दिए जाएंगे।

एक वर्ष में बढ़ी है विकास कार्यों की गति : डॉ. विजयलक्ष्मी साधौ

चिकित्सा शिक्षा, आयुष एवं संस्कृति मंत्री डॉ. विजयलक्ष्मी साधौ ने खरगोन जिले के महेश्वर में 29.40 लाख रुपए की लागत के अत्याधुनिक सुविधा केंद्र का भूमिपूजन किया। डॉ. साधौ ने कहा कि सरकार के बीते एक वर्ष के कार्यों पर गौर करें, तो पता चलता है कि विकास की गति वास्तविक रूप से तेज हुई है। मंत्री डॉ. साधौ ने महेश्वर के विभिन्न गांवों में 5 करोड़ 99 लाख 89 हजार लाख से अधिक राशि के विभिन्न कार्यों का भूमिपूजन भी किया।

डॉ. साधौ ने बताया कि एक वर्ष में महेश्वर और मंडलेश्वर में 75 प्रतिशत विकास कार्य हुए हैं। शेष 25 प्रतिशत कार्य गांवों में प्राथमिकता पूर्वक किए गए हैं। डॉ. साधौ ने महेश्वर में अत्याधुनिक हस्तकरघा सुविधा केंद्र का भूमिपूजन भी किया।

संस्कृति मंत्री डॉ. साधौ आगामी दिनों में करही कृषि उपज मंडी में आयोजित होने वाले जय किसान फसल ऋण माफी योजनांतर्गत किसान सम्मेलन में शामिल होंगी। इस दौरान योजनांतर्गत 4503 पीए ऋणी कृषक और 1207

एनपीए ऋणी कृषकों के ऋण माफ किए जाएंगे। इस तरह द्वितीय चरण में 5710 किसानों के कुल 43.3 करोड़ का ऋण माफ किया जाएगा। इसके अलावा संस्कृति मंत्री डॉ. साधौ



ग्राम वणी के अजा मोहल्ले में सामुदायिक भवन का भूमिपूजन करेंगी। संस्कृति मंत्री डॉ. साधौ आगामी दिनों में ग्राम आशापुर तथा ग्राम गुलावड़ में मुख्यमंत्री मदद योजनांतर्गत बर्तन वितरण करेंगी। संस्कृति मंत्री मुख्यमंत्री मदद योजनांतर्गत 405 बर्तनों के सैट ग्राम पंचायतों में वितरित करेंगी। संस्कृति मंत्री डॉ. साधौ खरगोन के नवगृह मेले में आयोजित होने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रम में शामिल होंगी।

● अक्स टीम



उम्मीदों का बजट

मध्यप्रदेश सरकार का वर्ष 2020-21 का बजट प्रदेश के विकास के लिए मील का पत्थर साबित हो सकता है। मुख्यमंत्री कमलनाथ इस बजट को लेकर काफी संजीदा हैं और उनका साफ तौर पर मानना है कि इस बजट के माध्यम से आंकड़ों की बाजीगरी से परे विकास अब हकीकत में दिखना चाहिए। मुख्यमंत्री के निर्देशों के अनुपालन में उनके मुख्य सचिव सुधि रंजन मोहंती न केवल अर्थव्यवस्था की समीक्षा कर रहे हैं बल्कि हर विभाग की बारीक से बारीक स्कूटनी कर परिणाम मूलक योजनाओं को अंतिम रूप देने में तेजी से जुड़ गए हैं। दरअसल सबसे बड़ी चुनौती प्रदेश को वित्तीय बदहाली से उभारना और सीमित राजस्व संसाधनों के बल पर आगे की कार्ययोजना बनाना है। मौजूदा बजट 2 लाख 33 हजार करोड़ रुपए का है, जो पुनरीक्षित होकर 25 हजार करोड़ रुपए तक घट सकता है।

गौरतलब है कि कमलनाथ सरकार का दूसरा बजट 16 मार्च से शुरू होने वाले विधानसभा के बजट सत्र के अंतिम सप्ताह में पेश किया जा सकता है। इसको लेकर राज्य सरकार की तैयारियां तेज हो गई हैं। बजट का फोकस इस बार कांग्रेस के वचन पत्र और विजन-टू-डिलीवरी रोडमैप 2025 पर रहेगा। सरकार को नए बजट में किसानों की कर्ज माफी, बेरोजगारों का भत्ता, युवाओं को रोजगार का वादा पूरा करना है। माना जा रहा है कि इस पर बड़ी राशि का प्रावधान किया जा सकता है।

कर्मचारी कल्याण, अधोसंरचना और पर्यटन विकास के लिए भी विभागों को बड़ी राशि दी जाएगी। बजट को वचन पत्र और दृष्टिपत्र ध्यान में रखते हुए तैयार करने के लिए कहा है। इसके मद्देनजर वित्त विभाग की पहल पर सामान्य प्रशासन विभाग ने अपर मुख्य सचिवों के नेतृत्व में चार समूह बनाए हैं जो विभिन्न योजनाओं का आकलन करके उन्हें जारी रखने, बंद करने या दूसरी योजनाओं में मिलाने को लेकर सुझाव देंगे। इसके आधार पर विभाग के प्रस्तावों को अंतिम रूप दिया जाएगा।

उधर, केंद्रीय करों में 14 हजार 233 करोड़ रुपए की कटौती और अतिवर्षा व बाढ़ से खजाने पर पड़े साढ़े छह हजार करोड़ रुपए के अतिरिक्त वित्तीय भार का असर भी बजट पर नजर आएगा।

इधर, आम बजट 2020 में केंद्रीय करों से मिलने वाली राशि में बड़ी कटौती से प्रदेश का बजट अनुमान गड़बड़ा गया है। केंद्र सरकार ने 14 हजार 233 करोड़ रुपए की केंद्रीय करों में कटौती कर दी है। संभावना जताई जा रही है कि नए बजट में प्रदेश सरकार कुछ नए कर लगा सकती है और कई योजनाओं को बंद किया जा सकता है। वर्ष 2019-20 में एक लाख 79 हजार 353 करोड़ रुपए का राजस्व मिलने की संभावना जताई जा रही थी। अब इसमें लगभग 20 हजार करोड़ रुपए से ज्यादा की कमी होने के आसार हैं। प्रदेश में जो राजस्व आना चाहिए, वह भी लक्ष्य से 16 हजार करोड़ रुपए कम है। ऐसे हालात में 2020-21 का बजट पेश करने से पहले मौजूदा बजट को पुनरीक्षित किया जाएगा। पिछले बजट में वित्त मंत्री तरुण भनोत ने 2 लाख 33 हजार करोड़ रुपए का बजट प्रस्तुत किया था। इसमें 2 लाख 14 हजार करोड़ रुपए शुद्ध व्यय बताया गया था। सभी स्त्रोतों से आय एक लाख 79 हजार 353

करोड़ रुपए आंकी गई थी। इसमें 63 हजार 750 करोड़ रुपए केंद्रीय करों से प्राप्त होने थे। जुलाई 2019 में केंद्र सरकार ने इसमें कटौती कर राशि 61 हजार 73 करोड़ रुपए कर दी। एक फरवरी 2020 को प्रस्तुत बजट में यह राशि और कम कर 49 हजार 517 करोड़ रुपए कर दी गई। इस प्रकार राज्य को केंद्रीय करों में 14 हजार 233 करोड़ रुपए की कटौती हो गई। इसके अलावा केंद्र से मिलने वाले 36 हजार 360 करोड़ रुपए के सहायता अनुदान में भी कमी आई है। वहीं सरकार ने सस्ती बिजली देने के लिए 18 हजार करोड़ की सब्सिडी देकर अपने ऊपर भार बढ़ा लिया है।

सूत्रों का कहना है कि किसानों की कर्जमाफी के तीसरे और अंतिम चरण के लिए कृषि विभाग को लगभग साढ़े सात करोड़ रुपए की जरूरत होगी। यदि अप्रैल से इसे शुरू करना है तो बजट में प्रावधान करना होगा। इसी तरह किसानों को अतिवर्षा और बाढ़ से हुए फसल नुकसान की भरपाई के लिए भी राशि देनी होगी। बेरोजगार युवाओं को भत्ता देने का कांग्रेस ने वचन पत्र में वादा किया था। इसके लिए युवा स्वाभिमान योजना लागू की थी, लेकिन अपेक्षित नतीजे नहीं आए। अब इसे नए सिरे से लागू करने की तैयारी है। वहीं, नगरीय विकास के 40 हजार संविदा कर्मचारियों को नियमित करने सहित अन्य कर्मचारियों की सेवाओं को जारी रखने, सेवानिवृत्त कर्मचारियों की देनदारी अदा करने, महंगाई भत्ता बढ़ाने, अतिथि विद्वानों को फिर से सेवा में रखने, शहरों में ओवरब्रिज, सड़क, पुल-पुलिया, सिंचाई परियोजना का निर्माण आदि के लिए बजट प्रावधान किए जाएंगे। औद्योगिक केंद्र और पर्यटन क्षेत्रों के विकास पर सरकार का जोर है, इसके लिए अधिक बजट रखा जा सकता है।

उधर, उद्योग विभाग बजट सत्र में उद्योगों को दी जाने वाली स्वीकृतियों से जुड़ा विधेयक भी प्रस्तुत करेगा। बताया जा रहा है कि उद्योग को एक दिन से लेकर 21 दिन में विभिन्न तरह की अनुमतियां इस कानून के प्रभावी होने के बाद मिलेंगी। यदि किसी वजह से अनुमति नहीं मिल पाती है तो न सिर्फ संबंधित अधिकारी की जवाबदेही तय होगी, बल्कि डीमड अनुमति भी मिल जाएगी।

2170 योजनाएं होंगी बंद

चौदहवे वित्त आयोग का कार्यकाल 31 मार्च, 2020 को पूरा हो जाएगा। इसके साथ ही प्रदेश में संचालित सभी 2170 सरकारी योजनाएं बंद हो जाएंगी। इन सभी योजनाओं की वैधता 31 मार्च तक है। इसके बाद सरकार नए सिरे से तय करेगी कि इनमें से कौनसी योजनाएं बंद करना है और कौनसी नए रूप में चालू रखना है। सूत्रों का कहना है कि सरकार ने इनमें से बड़ी संख्या में अनुपयोगी योजनाओं को बंद करने की तैयारी कर ली है। योजनाओं को 31 मार्च के बाद चालू रखने के लिए कैबिनेट की मंजूरी लेना पड़ेगी। दरअसल, कैबिनेट की मंजूरी के बाद लागू होने वाली हर योजना की वैधता पांच साल की होती है। 31 मार्च को योजनाओं की वैधता खत्म होने के बाद सरकार तय करेगी कि कौनसी योजनाएं अपने मूल स्वरूप में चलेगी, कौनसी योजनाओं में बदलाव किया जाएगा और कौनसी बंद की जाएगी। यही वजह है कि योजनाओं का रि-असिस्मेंट किया जा रहा है, उनकी रि-स्ट्रक्चरिंग की जा रही है। इसके लिए सरकार ने वरिष्ठ अधिकारियों की कमेटी बनाई है।

मद्र में खेती-किसानी की आड़ में एक ऐसा गोरखधंधा चल रहा है जिसमें दलाल जमकर कमाई कर रहे हैं और स्वामियाजा मजदूर और किसानों को भुगतना पड़ रहा है। धार जिले के मनावर के बोरलाई गांव में हुई मौब लिविंग की घटना इसका प्रमाण है।



जानलेवा गोरखधंधा!

प्रदेशभर में मनावर की घटना के बाद सियासी सरगर्मी चरम पर है। सत्ता पक्ष और विपक्ष में आरोप-प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। लेकिन प्रदेश में खेती-किसानी की आड़ में जिस तरह का गोरखधंधा चल रहा है उससे मनावर जैसी घटना प्रदेश के किसी भी गांव में कभी भी हो सकती है। क्योंकि किसानों से लाखों रुपए एडवांस लेकर भी खेती का काम नहीं किया जाता। यही रकम वापस मांगने पर विवाद होता है, जो कई बार हिंसक टकराव में बदल जाता है। फसल कटाई और बुआई के लिए किसानों को मजदूरों की जरूरत पड़ती है। इसके लिए मजदूरों से संपर्क करने पर वह एडवांस मांगते हैं, जो कि किसानों को देना ही पड़ते हैं। इसके बाद मजदूर आएंगे या नहीं और आएंगे भी तो पूरा काम करेंगे ही, इसकी गारंटी नहीं होती। इसके बाद किसान बकाया रकम के लिए चक्कर काटते रहते हैं।

जानकारी के अनुसार प्रदेश में सबसे उपजाऊ क्षेत्र मालवा में खेती का काम करने वाले मजदूरों की संख्या लगातार घटती जा रही है। ऐसे में किसानों की आवश्यकता की पूर्ति के लिए मजदूर सप्लायर निमाड़ से मजदूर लाने के नाम पर किसानों से मोटी रकम लेते हैं। मजदूर सप्लायर का यह गोरखधंधा वर्षों से चल रहा है। कई बार ऐसी स्थिति सामने आई है कि सप्लायर किसान से पैसा लेकर गायब हो जाते हैं और किसान मजदूर की आस में बैठे रह जाते हैं।

मनावर के बोरलाई में जघन्य हत्याकांड की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। बताया जा रहा है कि सुनील व ऊंकार सहित अन्य पांच मजदूरों से किसानों को पैसा लेना था। वे पैसा लेकर गुजरात चले गए थे। किसानों को सूचना मिली कि खिरकिया गांव में शादी कार्यक्रम में वे लोग आए हैं तो पैसा उनसे मिल जाएगा। हालांकि पैसों को लेकर वे पहले भी ग्रामीणों से बात कर चुके थे। पैसों को लेकर 5 फरवरी का दिन तय हुआ था। किसान गांव पहुंचे तो सुनील से 35 हजार लेना था। सुनील ने किसानों से कहा कि पिता से पैसों को लेकर बात कर लो। इस दौरान किसानों व ग्रामीणों के बीच में विवाद हो गया। किसान सुनील को कार में बैठाकर ले जाने लगे। ग्रामीणों ने अफवाह फैला दी कार में बच्चा चोर है। धीरे-धीरे भीड़ जुटती गई। जूनूपानी से ज्यादा लोग

कारों के पीछे लग गए। ग्रामीणों ने सुनील को कार में बैठा देखा था, लेकिन बोरलाई से करीब 12 किमी पहले कार रुकने पर किसान नीचे उतरे तो सुनील वहां से गायब हो गया। इसके बाद किसान कारों से भागे, लेकिन बोरलाई में कार में मजदूर नहीं होने के बावजूद भीड़ ने किसानों पर हमला कर दिया।

जानकारों का कहना है कि मालवा क्षेत्र में रोजगार नहीं होने के कारण बड़ी संख्या में मजदूरों ने पलायन किया है। मालवा के मजदूरों द्वारा दूसरे राज्यों में मजदूरी करने जाने से वहां के किसानों के सामने मजदूरों का टोटा पड़ गया है। ऐसे में यहां के किसान या तो स्वयं या फिर मजदूर सप्लायर के माध्यम से निमाड़ के खंडवा, धार, बड़वानी, खरगोन आदि जिलों से मजदूर लाते हैं। अपने खेतों में काम कराने के लिए किसानों को मजदूरों को पहले ही एडवांस में रकम दी जाती है। बताया जाता है कि एकमुश्त रकम मिलने के बाद मजदूर शराबखोरी आदि दुर्व्यसन में लिप्त हो जाते हैं और पैसा खत्म होते ही गांव छोड़ देते हैं। ऐसे में किसान मजदूरों के यहां छापामार कार्यवाही करते हैं।

कुछ दिन पहले सांवर के किसान 80 हजार रुपए नहीं देने पर मुकेश नाम के मजदूर को लेकर गए थे। जिसे गांव के कुछ लोग बाइक लेकर छुड़ाने गए थे। वे 50 हजार रुपए लेकर गए। जिस पर किसानों ने मुकेश को तो वापस भेज दिया था, लेकिन उनकी बाइक रख ली। इस बार भी किसानों को लगा था कि वह मजदूर को लेकर जाएंगे तो पैसा वापस मिल जाएगा, लेकिन इस बार लोगों ने विवाद के बाद घटना को अंजाम दिया। इसने इतना बड़ा रूप ले लिया कि इस बात का किसानों को भी अंदाजा नहीं होगा।

रायसेन जिले के गैरतगंज तहसील के आलमपुर निवासी आनंद पटेल ने धान कटाई के 80 हजार एडवांस में दिए, इसमें से 12 हजार का काम नहीं किया गया। बाकी राशि भी नहीं मिली। अब फिर से एडवांस मांगा जा रहा है। इसी तरह उज्जैन जिले के मुंजाखेड़ी गांव के किसान शिवनारायण ने फसल कटाई के लिए 5 लाख रुपए दिए, लेकिन मजदूर नहीं आए। पैसे वापस मांगे तो केस में फंसाने की धमकी मिली। तबसे वह यहां-वहां भटक रहा है।

● बृजेश साहू

तीन दिन पहले ही बन गई थी योजना

घायल रवि पटेल के भाई विक्रम पटेल ने बताया कि पीड़ितों ने खेतों में काम करने के लिए मजदूरों को 50-50 हजार रुपए दिए थे। कुल तीन लाख रुपए एडवांस दिए थे। इन्हें छह महीने काम करना था, लेकिन तीन-चार दिन में वापस चले गए। बार-बार तकादे के बाद भी नहीं आए। एक दिन मजदूरों ने खुद फोन लगाकर कहा कि गांव आकर पैसे वापस ले जाओ। भाई घर से निकले। साथ में विनोद मुकाती थे। रवि और विनोद रिश्ते में साला-बहनौई हैं और कुम्हारखेड़ा के रहने वाले हैं। बाकी लोग लिंबापिल्ल्या के थे। हमें 11 बजे के लगभग फोन आया। वे बहुत घबराए हुए थे। ऐसा लग रहा था कि वे भाग रहे हैं। बोले- ये लोग हमें मार डालेंगे, हम नहीं बचेंगे। कुछ हो तो व्यवस्था करो। हमने तुरंत थाने फोन किया। 100 नंबर पर भी लगाया। इसके बाद आसपास के गांवों में रहने वाले परिचितों को कॉल किया कि जल्दी वहां पहुंचो, कुछ गड़बड़ हो गई है।

देश की सबसे स्वच्छ राजधानी का तमगा हासिल करने वाले भोपाल को इस बार स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में नंबर-1 बनाने के लिए नगर निगम ने कमर कस ली है। निगम के दावों के अनुसार शहर में स्वच्छता के पूरे इंतजाम किए गए हैं।

लेकिन वर्तमान समय में शहर में ऐसा कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। जनवरी माह में जहां शहर में सुबह से लेकर शाम तक सफाईकर्मी सड़कों पर झाड़ू लगाते दिखते थे, वे अब कभी-कभार ही नजर आते हैं। शहर में जहां-तहां कचरे के ढेर देखे जा सकते हैं। इन दृश्यों को देखकर लोग कह रहे हैं कि केवल सर्वे के लिए सफाई व्यवस्था की गई थी।

31 जनवरी को केंद्र की 7 स्टार रेटिंग टीम का निरीक्षण खत्म होने के बाद अब निगम की लापरवाही आम है। सुबह 7 बजे से तीन घंटे तक जिन अफसरों को निगरानी करनी है, वे फरवरी में एक दिन भी घर से नहीं निकले। सफाई का जिम्मा कामगारों, दरोगाओं और सेनेटरी सुपरवाइजर्स के भरोसे छोड़ दिया गया है। कुल मिलाकर शहर की सफाई केंद्रीय टीम का निरीक्षण खत्म होते ही अपने पुराने ढर्रे पर लौट आई है। बाजार हों या रिहायशी इलाके सब जगह सफाई बंद है। न्यू मार्केट, रविशंकर मार्केट, बिट्टन मार्केट में कई दिनों से रात्रिकालीन सफाई नहीं हुई है। व्यापारियों का कहना है कि पहले रोजाना सफाई और धुलाई हो रही थी। स्वच्छता सर्वेक्षण में रात्रिकालीन सफाई के अलग अंक हैं। आवासीय क्षेत्रों में सुबह और दोपहर में झाड़ू लगाने वाले सफाई कामगार भी नहीं आ रहे हैं। आवासीय क्षेत्रों में दिन में दो बार सफाई अनिवार्य है, लेकिन ये फिलहाल ठप हो गई है।

डोर-टू-डोर कचरा कलेक्शन 2013 से हो रहा है, जिसे 2015 में वाडों तक किया गया। शहर के स्लम एरिया समेत अंदरूनी 550 क्षेत्रों को छोड़ दें तो बाकी में यह काम सर्वेक्षण खत्म होने के बाद भी पहले की तरह जारी है। 10 कचरा ट्रांसफर स्टेशन बनाकर गाड़ी से गाड़ी में कचरा ट्रांसफर करने पक्के निर्माण हुए, लेकिन ये फिलहाल कारगर नहीं। स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ने 150 क्षेत्रों में स्मार्ट डस्टबिन लगावाए। इनके भरने पर अलार्म बजते ही खाली करने हुकलोडर आना था। कई जगह इनके ढक्कन ही बंद नहीं हो रहे।

स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में अत्तल आने के लिए भोपाल नगर निगम बड़े-बड़े दावे कर रहा है। इसके लिए शहर में निरंतर सफाई करने के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन सर्वे टीम के लौटने के बाद से अचानक सफाईकर्मी सड़कों से गायब हो गए हैं।

सर्वे खत्म सफाई बंद!



यादगार-ए-शाहजहांनी पार्क में बायोकंपोस्ट सेंटर बनाया था। इससे दीनदयाल रसोई को रसोई गैस देनी थी। गीला कचरा लाने वालों को खाद बनाकर देनी थी, योजना लागू नहीं हो पाई। घर पर ही गीले कचरे से कंपोस्ट बनाने कंपोस्ट यूनिट बांटे गए, लेकिन ये बेकाम साबित हो रहे हैं। लोग इन्हें डस्टबिन की तरह उपयोग कर रहे हैं। पारस कॉलोनी फेस-2, विश्वकर्मा नगर हाउसिंग बोर्ड करोंद में रहने अतुल बेलवंशी ने सीवेज चैंबर चोक होने की शिकायत 5 फरवरी को नगर निगम के सीवेज प्रकोष्ठ में दर्ज कराई, लेकिन समस्या हल नहीं हुई। सर्वे के दौरान शिकायतों पर तत्काल कार्रवाई ठप हो गई है। जिन मोहल्लों, कॉलोनियों और बस्तियों में दिनभर कचरा गाड़ियां गश्त करती थीं, वहां अब ये गाड़ियां नजर नहीं आ रहीं। शहर के कई

इलाके ऐसे हैं जहां सर्वे खत्म होने के बाद से आज तक झाड़ू नहीं लगी। नतीजा कचरे के ढेर लगते जा रहे हैं। राजधानी में स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 खत्म होते ही नगर निगम के कर्मचारियों की मनमानी सामने आने लगी है। शहर में सफाई कर्मचारी कॉलोनियों से कचरा उठाने के नाम पर अवैध वसूली पर उतारू हैं। नगर निगम में ऐसे मामलों पर पहले भी कई शिकायतें दर्ज कराई जा चुकी हैं। दरअसल, निजी कॉलोनियों में कर्मचारी सफाई व्यवस्थाओं के नाम पर वसूली करते हैं। यदि कर्मचारियों की बात नहीं मानी जाती तो दो-दो दिन तक कचरा कलेक्शन ही नहीं किया जाता। निगम अधिकारी भी मामले को लेकर गंभीर नजर नहीं आते। ऐसे में राजधानी भोपाल स्वच्छता में नंबर-1 कैसे बन पाएगा।

● नवीन रघुवंशी

कबाड़ के कारण बढ़ रही गंदगी

नगर निगम के सफाई कर्मचारी अपनी कमाई के लिए सफाई व्यवस्था को पलीता लगा रहे हैं। इस चक्कर में सफाई कर्मियों ने शह देकर कुछ स्थानों पर कबाड़ी की दुकानें लगवाई हैं, जहां रोजाना कचरा उठाकर लाने वाली गाड़ियां आकर रुकती हैं। सफाईकर्मी कचरे को ट्रांसफर स्टेशन पर नहीं ले जाकर, कचरे से निकालकर काफी कबाड़ यहां बेचते हैं। इससे सफाई की जगह गंदगी बढ़ रही है और अनजान तत्वों का जमावड़ा भी लगा रहता है। कोलार रोड से लेकर नए भोपाल तक में कई स्थानों पर कबाड़ खरीदने वाले बैठा दिए गए हैं। ये कबाड़ी वहां बैठे हैं, जहां पर कचरा कंटेनर या अंडरग्राउंड स्मार्ट बिन लगाए गए थे। सफाईकर्मी कॉलोनियों से इकट्ठा कचरा ट्रांसफर स्टेशन पर देकर आदमपुर खंती भेजने की जगह इन स्थानों पर ही पटक देते हैं, इससे हालात और भी खराब हो गए हैं।

भा जपा शासन में नर्मदा किनारे एक ही दिन में 6 करोड़ पौधे लगाने में बड़े स्तर पर फर्जीवाड़ा किया गया था। वर्तमान सरकार ने इस फर्जीवाड़े की जांच कराकर दोषियों को सजा दिलाने का वादा किया था। लेकिन एक साल से अधिक का अरसा बीत जाने के बाद भी इस मामले में अभी तक सिर्फ जांच पर जांच चल रही है। वनमंत्री उमंग सिंघार का कहना है कि इस मामले में एक और जांच चल रही है। जल्द ही फर्जीवाड़े में शामिल दोषियों के नाम सामने आ जाएंगे।

जानकारी के अनुसार इससे पहले वन विभाग इस फर्जीवाड़े की आधा दर्जन जांच करवा चुका है। दरअसल, वनमंत्री उमंग सिंघार ने इस पूरे मामले में तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, तत्कालीन वनमंत्री गौरीशंकर शेजवार सहित वन मुख्यालय के अफसरों को दोषी मानते हुए इस मामले को ईओडब्ल्यू को सौंपने की अनुशंसा की थी। लेकिन विभाग के अपर मुख्य सचिव ने ईओडब्ल्यू से जांच कराने के प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। उसके बाद पौधरोपण घोटाले में आईएफएस अफसरों को फंसते देख विभाग ने इस मामले की फाइल मुख्यमंत्री कमलनाथ को भेजी थी। उच्च स्तर पर चर्चा के बाद तय हुआ है कि इस मामले की सूक्ष्म स्तर पर जांच कराई जाए। इसमें प्रदेश की सभी नर्सरियों के पौधे तैयार करने की क्षमता की जांच भी कराई जाए जिससे ये पता चल सके कि उन्होंने जितने पौधे बेचना बताए हैं क्या वाकई सही हैं। उल्लेखनीय है कि कांग्रेस ने सरकार में आते ही दो जुलाई 2017 को नर्मदा के किनारे रोपे गए पौधों के घोटाले की बात कही थी।

योजना एवं आर्थिक सांख्यिकी विभाग ने वन, कृषि, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, उद्यानिकी विभाग से सात बिंदुओं पर जानकारी मांगी है। विभाग ने पूछा है कि पौधे कहां से खरीदे गए थे। किस मूल्य पर पौधे खरीदे गए। पौधे प्रदाय करने वाले वन विभाग की नर्सरियों की क्षमता तथा उसमें पांच वर्षों तक तैयार किए गए पौधों की जानकारी मांगी है। सांख्यिकी विभाग ने यह भी पूछा है कि जिन क्षेत्रों में पौधे रोपे गए थे उसकी भौगोलिक स्थिति क्या है, उसके खसरा नंबर तथा मैप भी उपलब्ध कराएं। साथ ही वर्तमान में पौधों के जीवितता की जानकारी एक सप्ताह के अंदर बुलाई गई है। विभागों द्वारा उपलब्ध कराई गई रिपोर्ट वित्तमंत्री की अध्यक्षता में पौधरोपण की जांच के लिए मंत्री समूह समिति के समक्ष पेश की जाएगी।

वनमंत्री उमंग सिंघार ने पौधरोपण की जांच ईओडब्ल्यू से कराने की घोषणा 11 अक्टूबर 2019 को की थी। पौधरोपण के दौरान हुई वित्तीय अनियमितताओं के संबंध नोटशीट और



जांच पर जांच

इस तरह से कराई जांच

इस मामले में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की याचिका पर एनजीटी ने 25 सितम्बर 2017 तक सरकार से रिपोर्ट बुलाई। वन विभाग ने एनजीटी में रिपोर्ट पेश करते हुए बताया कि 95 फीसदी पौधे जीवित हैं। फिर विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा सरकार के आखिरी विधानसभा सत्र के दौरान कांग्रेस ने सवाल उठाया था कि भाजपा सरकार द्वारा वाहवाही लूटने के चक्कर में बिना तैयारी के नर्मदा के किनारे सवा 6 करोड़ पौधे रोपे गए हैं, लेकिन हकीकत कुछ और ही है। पौधरोपण की जांच कराई जाए। वन विभाग ने विधानसभा को पेश किए गए आंकड़ों में बताया था कि 85 फीसदी पौधे जीवित हैं। उसके बाद कांग्रेस सरकार के आने के बाद कराई गई। इस जांच रिपोर्ट में अधिकारियों ने बताया कि 80 फीसदी से अधिक पौधे जीवित हैं। बाद में पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने यह दावा किया कि उन्होंने पदयात्रा के दौरान खुद यह देखा है कि नर्मदा के किनारे रोपे गए पौधे सूख गए हैं। कई जगह सिर्फ गड्डे खोदे गए थे, पौधे नहीं लगाए गए। भाजपा सरकार ने पौधरोपण के फर्जी आंकड़े पेश किए हैं। फिर वनमंत्री उमंग सिंघार ने खुद जांच कराई। जिसमें यह बात सामने आई कि करीब 75 फीसदी से अधिक पौधे जीवित हैं। इसके बाद उन्होंने खुद बैतूल सहित अन्य जिलों में औचक निरीक्षण कर देखा तो पाया मात्र 20 फीसदी ही पौधे जीवित पाए गए, जितने गड्डे खोदे गए थे, उसमें से मात्र 15 फीसदी ही रोपे गए। इसके चलते उन्होंने पूरी रिपोर्ट को खरिज कर दिया। उसके बाद मंत्री ने फिर जांच कराई। इसमें एक क्षेत्र के अधिकारी को दूसरे क्षेत्र में पौधरोपण के जांच की जिम्मेदारी दी गई, इसमें जांच में कुछ निजी एजेंसियों को भी शामिल किया गया था।

कुछ दस्तावेज भी मीडिया और सरकार को दिए थे। उन्होंने तत्कालीन भाजपा सरकार पर ये भी आरोप लगाए थे कि वन विभाग के अधिकारियों के साथ सरकार भी इस घोटाले में शामिल है। हालांकि कमलनाथ सरकार ने पौधरोपण की जांच कराने के संबंध में कोई निर्णय नहीं लिए हैं।

जानकारी के अनुसार इस मामले में वन विभाग के आला अधिकारी लीपापोती की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि घोटाले के केंद्र में वन विभाग के ही अधिकारी हैं। रिपोर्ट कुछ इस तरह से बनाई जा रही है कि 100 पौधे लगाए थे, 20 जीवित हैं। यानी 80 मुरझा गए हैं। जबकि घोटाला का मुद्दा ही यह है कि दस्तावेजों में 100 पौधे दर्ज किए, असल में 20 ही खरीदे, 80 पौधे अफसर खा गए। वन विभाग के सूत्रों के अनुसार जांच में यह बात सामने आई है कि इंदौर में 45 से 50 फीसदी पौधे खराब हो गए। इसी प्रकार सीहोर के एक परिक्षेत्र में 50 फीसदी, जबकि दूसरे परिक्षेत्र में 20 फीसदी। सिवनी, बालाघाट, अनूपपुर, मंडला, जबलपुर वन मंडल में 10 से 33 फीसदी। भोपाल वन मंडल ने एक साल पहले एनजीटी को 80 फीसदी पौधे जीवित होना बताया था, लेकिन रिपोर्ट बदल गई है और नए सर्वे के हिसाब से 70 फीसदी पौधे ही शेष बचे हैं। यानी यहां 30 प्रतिशत का घोटाला जांच की जद में होना चाहिए। वनमंत्री उमंग सिंघार का कहना है कि नर्मदा किनारे पौधरोपण में ढेरों गड़बड़ियां हुई हैं। पौधों का एक मैदानी सर्वे कराया है। इसकी जांच रिपोर्ट में देखा जा रहा है कि कहां क्या स्थिति है? जल्दी ही इस पर कार्यवाही करेंगे। अब देखना यह है कि भाजपा शासनकाल में हुए इस घोटाले की तह तक सरकार पहुंच पाती है या नहीं।

● विशाल गर्ग

वर्तमान समय में मप्र सरकार पर 2,10,510 करोड़ रुपए का कर्ज है। उधर, केंद्र सरकार प्रदेश के साथ उपेक्षापूर्ण रवैया अपनाए हुए है। ऐसे में सरकार की आर्थिक स्थिति दिन पर दिन कमजोर होती

जा रही है। अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए सरकार अपने कमाऊ विभागों पर विशेष ध्यान दे रही है। इसी कड़ी में सरकार आबकारी नीति में बदलाव कर अपने खाली खजाने को भरने की तैयारी कर रही है।

गौरतलब है कि आम बजट में मध्यप्रदेश का कोटा कम किए जाने के बाद सरकार की आर्थिक दिक्कतें और बढ़ गई हैं। प्रदेश सरकार पहले से ही आर्थिक तंगी से जूझ रही थी। अब सरकार ने आय बढ़ाने शराब की दुकानों को जरिया बनाया है। कहा जा रहा है कि केंद्र की तरफ से राहत न मिलने के कारण सरकार अपने पास उपलब्ध संसाधनों से अधिक से अधिक राजस्व जुटाने के प्रयास कर रही है। यही वजह है कि आबकारी विभाग से अधिकतम राजस्व जुटाने के लिए नई आबकारी नीति में शराब दुकानों की नीलामी की प्रक्रिया में संशोधन किया गया है। इससे पहले तक पिछले साल के अपसेट प्राइस से 15 प्रतिशत राशि बढ़ाकर शराब दुकान रिन्यू कर दी जाती थीं। अधिकतर शराब ठेकेदार 15 प्रतिशत ज्यादा राशि देकर दुकानें रिन्यू करा लेते थे। इससे सरकार के राजस्व में अधिकतम 15 प्रतिशत की ही बढ़ोतरी हो पाती थी। लेकिन अब अपसेट प्राइस में 20 से 25 प्रतिशत की बढ़ोतरी होने और उसके बाद बोली लगाए जाने की प्रक्रिया से सरकार के राजस्व में अच्छी खासी बढ़ोतरी के आसार हैं।

राज्य सरकार इस साल नई आबकारी नीति में शराब दुकानों की नीलामी प्रक्रिया में बड़ा बदलाव करने जा रही है। इसका मकसद राजस्व में बढ़ोतरी करना है। इस साल शराब ठेकेदार शराब दुकानों को रिन्यू नहीं करा पाएंगे। इस बार शराब दुकानों की नीलामी के लिए ई-टेंडर निकाले जाएंगे। टेंडर खोलने के बाद एक बार फिर निविदाकर्ताओं को नीलामी की राशि बढ़ाने का मौका दिया जाएगा। इसके बाद शराब ठेकों की नीलामी शुरू की जाएगी और सबसे ज्यादा बोली लगाने वाले को शराब की दुकान आवंटित कर दी जाएगी। पिछले साल के मुकाबले इस बार शराब दुकानों की अपसेट प्राइस 20 से 25 प्रतिशत ज्यादा रखी जाएगी।

शराब दुकानों की नीलामी प्रक्रिया में बदलाव से सरकार को 4 हजार करोड़ अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होने का अनुमान है। प्रदेश में शराब की करीब 3600 दुकानें हैं। इनमें 1060 विदेशी शराब दुकानें और करीब 2544 देशी शराब



शराब से भरेगा खजाना

उप दुकानें खोलने का निर्णय पहले ले चुकी है सरकार

इससे पहले राज्य सरकार प्रदेश में शराब की उपदुकानें खोलने का फैसला कर चुकी है। उप दुकान खोलने के लिए शराब दुकान संचालक को सालाना शराब ठेके के अतिरिक्त राशि देना होगी। शहरी क्षेत्र में 5 किलोमीटर की परिधि में शराब की दुकान नहीं होने पर, जबकि ग्रामीण क्षेत्र में 10 किलोमीटर की परिधि में शराब दुकान नहीं होने पर उपदुकान खोलने की मंजूरी दी जाएगी। शराब दुकान के लाइसेंस शुल्क के आधार पर उपदुकानों के अतिरिक्त शुल्क का स्लैब तैयार किया गया है। इस फैसले से प्रदेश में करीब 500 उपदुकानें खुलने का अनुमान है।

दुकानें हैं। वाणिज्यिक कर विभाग के प्रस्ताव को मंत्री बृजेन्द्र सिंह ने अनुमोदन कर दिया है। अब प्रस्ताव वित्त विभाग को भेजा जाएगा। वित्त विभाग की अनुमति के बाद मुख्य सचिव के माध्यम से प्रस्ताव कैबिनेट में लाया जाएगा। वर्तमान में देश में सबसे महंगी शराब मप्र में है। सरकार इससे पहले प्रदेश में उपदुकानें खोलने का फैसला कर चुकी है। उपदुकान खोलने के लिए शराब दुकान संचालक को सालाना शराब ठेके के अतिरिक्त राशि देनी होगी। शहरी क्षेत्र में 5 किलोमीटर की परिधि में शराब की दुकान नहीं होने पर, जबकि ग्रामीण क्षेत्र में 10 किलोमीटर की परिधि में शराब दुकान नहीं होने पर उपदुकान खोलने की मंजूरी दी जाएगी। शराब दुकान के लाइसेंस शुल्क के आधार पर उपदुकानों के अतिरिक्त शुल्क का स्लैब तैयार किया गया है।

नई शराब नीति में कई बदलाव किए जा रहे हैं। अभी तक शराब की दुकानों का ठेका अलग-अलग ठेकेदारों को दिया जाता था, परंतु आप पूरे जिले या एक साथ कई जिलों का ठेका एक ही

शराब कारोबारी को दे दिया जाएगा। याद दिला दें कि 15 साल पहले दिग्विजय सिंह शासनकाल में भी ऐसा ही होता था। आने वाले दिनों में जब शराब के ठेकों की नीलामी होगी तो वह दुकान के हिसाब से नहीं बल्कि जिलों के हिसाब से होगी। ठेका सिंडिकेट को दिया जाएगा। इतना ही नहीं, एक साल का लाइसेंस देने और अगले साल टेंडर करने की व्यवस्था को भी बदलकर दो साल का लाइसेंस दिया जा सकता है।

आबकारी विभाग के आला अधिकारियों के साथ शराब कारोबारियों की चर्चा हो चुकी है। बताया जा रहा है कि कारोबारियों की मंशा के अनुरूप इस तरह के बदलाव की तैयारी है। 16 साल पहले दिग्विजय सिंह के मुख्यमंत्री रहते शराब का कारोबार समूहों के ही हाथ में था। इसके बाद भाजपा के सत्ता में आने पर यह नीति बदल दी गई थी। दिग्विजय सरकार के समय मप्र में नौ लोगों के हाथों में ही शराब का काम था। फिर भाजपा शासन में आबकारी आयुक्त रहे ओपी रावत ने नीति बदली और 3000 शराब दुकानों की नीलामी की गई। इसके बाद दिग्विजय सरकार में सक्रिय रहे नौ लोगों के पास सिर्फ 5 से 7 प्रतिशत ही दुकानें बची थीं।

अब राज्य सरकार पुरानी व्यवस्था में जाने वाली है। एक अप्रैल से पहले शराब दुकानों की नए सिरे से नीलामी प्रस्तावित है। इसलिए प्रयास किया जा रहा है कि नीति में जल्द से जल्द बदलाव कर दिया जाए। लंबे समय से शराब कारोबारियों का लाइसेंस नवीनीकरण ही क्रिया जाता रहा। दस साल में आखिरी बार नीलामी 2015-16 में हुई। अब वित्तीय वर्ष 2020-21 और 2021-22 के लिए नीलामी प्रस्तावित है। आबकारी विभाग को उम्मीद है कि इससे राजस्व बढ़ जाएगा। वर्ष 2018-19 में करीब 9000 करोड़ रेवेन्यू था, जिसे 2019-20 में बढ़ाकर 11500 करोड़ रुपए कर दिया गया। अब इस लक्ष्य से भी आगे बढ़ना है।

● कुमार विनोद

कुपोषित बच्चों को कुपोषण से बाहर निकालने के लिए शासन ने प्रत्येक ब्लॉक में पोषण पुनर्वास केंद्र स्थापित किए हैं, परंतु इन केंद्रों के बहुत अच्छे रिजल्ट सामने नहीं आने के बाद अब शासन ने गांव में ही कम्युनिटी एनआरसी स्टार्ट करने की योजना तैयार की है, ताकि कुपोषण को जड़ से मिटाया जा सके। उल्लेखनीय है कि अतिकुपोषित बच्चों को कुपोषण से बाहर निकालने के लिए शासन ने ऐसे बच्चों को एक ही छत के नीचे हेल्थी भोजन और उपचार की सुविधा उपलब्ध कराने एनआरसी (पोषण पुनर्वास केंद्र) शुरू किए। एनआरसी जब शुरू हुई तब तो जिले में कुछ हद तक अच्छे रिजल्ट सामने आए, क्योंकि कुपोषित बच्चे को भोजन व उपचार के अलावा एनआरसी में उसके साथ रहने वाली उसकी मां को प्रोत्साहन राशि उपलब्ध कराई जाती है। कुछ समय बाद धीरे-धीरे कुपोषित बच्चों के परिजनों का मोह खत्म हो गया और उन्होंने एनआरसी आना बंद कर

दिया। जब जिम्मेदार अधिकारियों ने कुपोषित बच्चों के एनआरसी न आने के कारणों की पड़ताल शुरू की तो पता चला कि कई परिवारों में तीन-तीन बच्चे हैं जिनमें से एक **अतिकुपोषित** है तो मां अन्य बच्चों की देखभाल के कारण एनआरसी नहीं आ पाती अथवा उसे मजदूरी पर जाना होता है इसलिए भी वह एनआरसी नहीं आती। परिणाम स्वरूप न तो कुपोषण कम हुआ और न ही कुपोषण से होने वाली मौतें।

पोषण पुनर्वास केंद्रों की असफलता के चलते शासन ने प्रदेश के नौ जिलों में कम्युनिटी एनआरसी खोलकर कुपोषण को कम करने का प्रयास किया तो इसके अच्छे रिजल्ट सामने आए। इन परिणामों से उत्साहित होकर सरकार ने अब पूरे प्रदेश में गांवों में कम्युनिटी एनआरसी खोलने का मन बनाया है। प्रदेश में कम्युनिटी एनआरसी की दिशा में जोर-शोर से काम चल रहा है। इसके तहत अतिकम वजन के बच्चों को आंगनबाड़ी केंद्र पर ही पांच दिन तक विशेष केयर में रखकर पोषण आहार व दवा खिलाई जाएगी। इस दौरान बच्चे की मां की

मग्न में कुपोषण को खत्म करने के लिए सरकार तरह-तरह के प्रयोग कर रही है। इसी कड़ी में अब गांवों में ही कम्युनिटी एनआरसी बनाने की तैयारी की जा रही है।

कम्युनिटी एनआरसी



प्रदेश को मातृ वंदना योजना में तीन राष्ट्रीय पुरस्कार

मध्यप्रदेश को प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में उल्लेखनीय कार्य के लिए तीन श्रेणियों में राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। योजना में जिला स्तरीय श्रेणी में प्रदेश के इंदौर जिले को राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना सप्ताह के क्रियान्वयन के लिए प्रदेश को देश में तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। प्रदेश में यह सप्ताह 2 से 8 दिसम्बर 2019 तक मनाया गया था। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में प्रदेश में अब तक कुल 14 लाख 55 हजार 501 हितग्राहियों को पंजीकृत किया गया है। लगभग 13 लाख 40 हजार 224 हितग्राहियों को पहली किशत, 12 लाख 60 हजार 304 हितग्राहियों को दूसरी और 8 लाख 80 हजार 517 हितग्राहियों को तीसरी किशत का भुगतान किया गया है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं एवं माताओं को 6 हजार रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। यह सहायता राशि उनके खाते में सीधे जमा कराई जाती है। योजना का मुख्य उद्देश्य गर्भावस्था, प्रसव और स्तनपान के दौरान महिलाओं को जागरूक करना और जच्चा-बच्चा देखभाल तथा संस्थागत सेवा के उपयोग को बढ़ावा देना है।

भी काउंसलिंग की जाएगी, फिलहाल यह कार्यक्रम नौ जिलों में चल रहा था, अब इसे पूरे प्रदेश में लागू किया जा रहा है।

कम्युनिटी एनआरसी में गांव में ही अतिकुपोषित बच्चे को पांच दिन तक दिनभर आंगनबाड़ी केंद्र पर ही रखा जाएगा। इस दौरान बच्चे को चार बार पौष्टिक भोजन कराया जाएगा। इसके अलावा बच्चे की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए उसे एनएम के माध्यम से अमोक्सीसिल्लिन नामक एंटीबायोटिक दवा भी पिलाई जाएगी। शाम को बच्चा अपने घर चला जाएगा। इस दौरान कुपोषित बच्चे की मां को आंगनबाड़ी केंद्र पर या घर पर जाकर पौष्टिक आहार के संबंध में भी जानकारी दी जाएगी। अधिकारियों का मानना है कि टीएचआर (टेक होम राशन) तो हम अभी भी बच्चों को देते हैं परंतु वह बच्चा नहीं खाता है, इसी कारण कुपोषण की दिशा में सफलता नहीं मिल पा रही। कम्युनिटी एनआरसी में यह सब बच्चे को केंद्र पर ही खिलाया जाएगा, जिससे उसका वजन बढ़ेगा।

विभाग के अधिकारियों के अनुसार हर जिले में बच्चों का वजन तौला जाएगा। इस सर्वे में जब **अतिकम वजन** के बच्चों की संख्या सामने आएगी तो उसके आधार पर फर्स्ट फेज में ऐसी आंगनबाड़ियों पर कम्युनिटी एनआरसी शुरू की जाएगी जहां कम से कम तीन अतिकम वजन के बच्चे होंगे। इसके अलावा अगर एक गांव में एक से अधिक एनआरसी हैं तो सभी एनआरसी में से किसी एक आंगनबाड़ी पर एनआरसी शुरू की जाएगी और वहां गांव की सभी आंगनबाड़ियों के अतिकम वजन के बच्चों को लाया जाएगा।

प्रमुख सचिव अनुपम राजन ने बताया कि प्रदेश में **3 हजार से ज्यादा डे-केयर सेंटर** खोले जा रहे हैं। बच्चों को ज्यादा से ज्यादा पोषक आहार दिया जा रहा है। साथ ही, अभिभावकों को पोषण आहार से संबंधित जानकारी भी दी जा रही है। राजन ने बताया कि सभी जिलों, ब्लाक एवं गांव में कुपोषित बच्चों को चिन्हित कर योजना का अधिक से अधिक लाभ पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है।

● श्याम सिंह सिकरवार

मप्र को मैग्नीफिसेंट (शानदार) बनाने के लिए मुख्यमंत्री कमलनाथ और उनकी सरकार नए-नए प्रयोग कर रही है। मुख्यमंत्री की कोशिश है कि प्रदेश में अधिक से अधिक निवेश आए ताकि बेरोजगारी दूर हो सके। वहीं वे प्रदेश को पर्यटन के नक्शे पर भी मैग्नीफिसेंट बनाना चाहते हैं। इसके लिए उन्होंने प्रदेश की राजधानी भोपाल और व्यावसायिक राजधानी इंदौर में इंटरनेशनल इंडियन फिल्म अकादमी अवार्ड (आईफा) का आयोजन करने का निर्णय लिया है। सरकार की मंशा है कि आईफा के आयोजन से मप्र में पर्यटन का द्वार खुलेगा।

सरकार के अनुसार भोपाल-इंदौर में होने वाले आईफा अवार्ड से प्रदेश की ख्याति अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहुंचेगी। प्रदेश में आर्थिक गतिविधियां बढ़ेंगी। पर्यटन, उद्योग, व्यावसाय और व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। प्रदेश में नया निवेश आएगा। आईफा का इक्कीसवां आयोजन पहली बार मुंबई के बाहर मध्यप्रदेश में आयोजित हो रहा है। आईफा अवार्ड का रंगारंग आयोजन एक दिन भोपाल और दो दिन इंदौर में होगा। गत दिनों मिंटो हाल में मुख्यमंत्री कमलनाथ की उपस्थिति में सुप्रसिद्ध फिल्म कलाकार सलमान खान और जैकलीन फर्नांडिस ने आयोजन के करटेन रेजर कार्यक्रम में आईफा अवार्ड के आयोजन तारीखों की घोषणा की। भोपाल के मिंटो हॉल में 21 मार्च को और इंदौर में 27 एवं 29 मार्च को इसका आयोजन होगा। संगीत, मनोरंजन और फिल्म निर्माण की विभिन्न विधाओं के समागम से जुड़े आईफा अवार्ड के आयोजन को सलमान खान के साथ रितेश देशमुख, जैकलीन और कटरीना कैफ होस्ट करेंगे।

मध्य प्रदेश में आईफा अवार्ड समारोह की तारीखों का ऐलान किए जाने के साथ ही राज्य की सियासत गरमा गई है। भाजपा इस आयोजन को जहां फिजूलखर्ची बता रही है, वहीं कांग्रेस ने इस आयोजन को देश और दुनिया में राज्य को पहचान दिलाने वाला आयोजन करार दिया है। आईफा अवार्ड समारोह आयोजन पर विपक्षी दल भाजपा के नेता और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव का कहना है, राज्य की धरती पर दलितों और आदिवासियों पर अत्याचार हो रहे हैं, किसान कर्जमाफी के इंतजार में आत्महत्या कर रहे हैं। बेरोजगार युवा हताशा और अवसाद का शिकार हो रहे हैं। कन्याएं अपनी गृहस्थी बसाने के लिए उपहार राशि का इंतजार कर रही हैं। संबल योजना के हितग्राही कफन सहायता, मृत्यु सहायता की आशा में रोज बैंकों से खाली हाथ लौट रहे हैं।

भार्गव ने कई योजनाओं को बंद किए जाने का आरोप लगाते हुए कहा, खाली खजाने का हवाला देकर कमलनाथ सरकार गरीबों की



मध्यप्रदेश में आईफा क्यों ?

मध्यप्रदेश में आईफा के आयोजन पर सवाल उठ रहे हैं। सवाल उठाने वालों को मुख्यमंत्री कमलनाथ ने जवाब देते हुए कहा है कि आईफा एक नई उम्मीद की किरण है। निश्चित ही यह मध्यप्रदेश के लिए भी बड़ा अवसर है। जिस समारोह में मुंबई सिने दुनिया से 5 हजार सितारे शामिल होने वाले हों उसके विशाल स्वरूप का अंदाजा सहज लगाया जा सकता है। इस दौरान होटल, ट्रेवल और दूर इंडस्ट्री को अच्छा खासा बूस्टअप मिलने वाला है। मुंबई से जब सितारे जुटेंगे तो इंदौर में देश-दुनिया के टीवी और मनोरंजन चैनलों के रिपोर्टर और कैमरामैन भी आएंगे। ऐसे में टाइगर स्टेट कहलाने वाले अपने मध्यप्रदेश की धुआधार ब्रांडिंग होना तय है। आईफा समारोह के आयोजन के दौरान इवेंट मैनेजमेंट से लेकर पर्यटन, संस्कृति, सिक्वोरिटी से जुड़े हजारों लोग आयोजन का हिस्सा बनेंगे। कलाकारों के इस महाकुंभ के प्रति मध्यप्रदेश के टीवी, सिने कलाकारों से लेकर सिने दुनिया का सपना देखने वाले भी आशान्वित होंगे। बाहर के नामी सिने और टीवी जगत के कलाकार आए तो उन्हें भी कुछ न कुछ मौका इन कलाकारों से मिलने-जुलने से लेकर संवाद का अवसर मिले ये अपेक्षा करेंगे। मध्यप्रदेश सरकार जिस भी रूप में आयोजन से जुड़े उसे स्थानीय कलाकारों और स्थानीय आशाओं और अपेक्षाओं का पूरा ख्याल करना चाहिए और उनके लिए उचित अवसर का मंच तैयार रखना चाहिए।

योजनाओं को बंद कर रही है। वहीं दूसरी ओर आईफा अवार्ड के नाम पर सरकार अपनी वाहवाही में लगी हुई है। वहीं राज्य की संस्कृति मंत्री डॉ. विजय लक्ष्मी साधु का कहना है, आईफा अवार्ड आयोजन प्रदेश को देश और दुनिया में नई पहचान दिलाने वाला होगा। भाजपा के नेताओं का काम है आरोप लगाना और वे वही कर रहे हैं। इस आयोजन से राज्य में व्यावसायिक गतिविधियां भी बढ़ेंगी, इसका लाभ तो प्रदेश और प्रदेशवासियों को ही होगा। उन्होंने कहा, मध्य प्रदेश देश के मध्य में स्थित है। यहां प्राकृतिक सौंदर्य है, वाइल्ड लाइफ है, धरोहर है। इस आयोजन के जरिए लोग इसे करीब से जान सकेंगे। जब कोई भी बड़ा आयोजन किसी स्थान पर होता है तो उसका लाभ उस क्षेत्र और वहां के लोगों को होता है। आईफा के आयोजन से देश और दुनिया के लोगों का यहां आना होगा और वे मध्य प्रदेश को करीब से जान सकेंगे।

राज्य की कमलनाथ सरकार द्वारा आर्थिक सुधार लाने की दिशा में किए जा रहे प्रयासों का हवाला देते हुए डॉ. साधु ने कहा, इस आयोजन से राज्य को आर्थिक लाभ होगा। पर्यटन को बढ़ावा देने के प्रयास चल रहे हैं, उस दिशा में आईफा मददगार साबित होगा। मुंबई सिने जगत इंदौर आए, अपने मध्यप्रदेश के घर कलाकार और युवा चेहरे कुछ नया अवसर पाएं तो इससे बड़ी क्या खुशी होगी। हमारा प्रदेश, हमारे शहर, हमारी कला संस्कृति, पर्यटन का आईफा के जरिए देश दुनिया में प्रचार-प्रसार हो इससे भला हम प्रदेशवासियों के लिए क्या होगा।

● विकास दुबे

आदिवासियों के साथ बाजीगरी



बजट में बड़ी कटौती

नीति आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुसार इन 41 मंत्रालयों का कुल फंड निर्धारण अनुसूचित जाति समुदायों के लिए 1,39,172 करोड़ रुपए 323 स्कीमों के तहत होना चाहिए। पर अनुसूचित समुदायों के लिए वास्तविक आवंटन सिर्फ 83,257 करोड़ रुपए ही है। इसी प्रकार अनुसूचित जनजाति के लिए कुल फंड आवंटन 77,034 करोड़ रुपए होना चाहिए पर वास्तविक आवंटन सिर्फ 53, 653 करोड़ रुपए है। अनुसूचित जाति की 323 कुल स्कीमों में से सिर्फ 52 लक्षित स्कीमों हैं और 271 गैर-लक्षित स्कीमों हैं। जिनके अंतर्गत आवंटित धनराशि क्रमशः 16,174 करोड़ और 67,083 करोड़ रुपए है। इसी प्रकार अनुसूचित जनजाति की 331 स्कीमों में से सिर्फ 42 लक्षित स्कीमों हैं और 289 गैर-लक्षित स्कीमों हैं। और इनके लिए आवंटित धनराशि क्रमशः 19, 428 करोड़ रुपए और 34, 225 करोड़ रुपए है।

पिछले वर्ष की तुलना में पोस्ट मैट्रिक स्कूलरशिप में मामूली वृद्धि की गई है। अनुसूचित जाति का बजट 2987 करोड़ रुपए है वहीं अनुसूचित जनजाति का बजट 1900 करोड़ रुपए है। यह देखा जाए कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के बड़ी संख्या में छात्र अपनी उच्च शिक्षा के लिए इस स्कीम पर निर्भर होते हैं। दुखद है कि अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति की कुछ महत्वपूर्ण विकास योजनाओं को उनकी आवश्यकता के अनुसार बजट आवंटित नहीं किया गया है।

शिक्षा के क्षेत्र में देखें तो सामाजिक-आर्थिक समस्याएं और भेदभाव के अनुभव मौजूद होने के बावजूद दलित और आदिवासी

छात्र उच्च शिक्षा में अच्छे अंक प्राप्त कर आगे बढ़ रहे हैं। उच्च शिक्षा के ऑल इंडिया सर्वे बताते हैं कि पिछले पांच सालों में छात्रों के अनुक्रमांक और प्रतिशत बढ़ा है। शैक्षिक वर्ष 2014-15 अनुसूचित जाति के छात्रों की उच्च शिक्षा में प्रतिशत कुल छात्रों की तुलना में 13.47 प्रतिशत था। अकादमिक वर्ष 2018-19 में यह बढ़कर 14.89 प्रतिशत हो गया यानी उनकी संख्या 55,67,078 हो गई। इसी प्रकार आदिवासी छात्रों का प्रतिशत 4.80 प्रतिशत था, वह बढ़कर 5.53 प्रतिशत हो गया यानी उनकी संख्या 20,67,748 हो गई।

इसी प्रकार अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति की कुछ प्रमुख स्कीमों जो उच्च शिक्षा प्रदान करती हैं जैसे पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप कम आवंटन की चुनौतियों का सामना कर रही हैं। इसके अलावा सरकार के सुस्त सिस्टम के कारण पोस्ट मैट्रिक की धनराशि तब मिलती है जब सत्र खत्म होने को होता है। इससे अजा एवं अजजा के छात्रों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। इस स्कॉलरशिप को प्राप्त करने के लिए सरकार की जटिल प्रक्रिया के कारण भी छात्रा-छात्राओं को बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं- यह अलग कहानी है। इस बजट पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए राईट-टू-एजुकेशन फोरम के राष्ट्रीय संयोजक अम्बरीष राय कहते हैं कि- 'बच्चों के संविधान प्रदत्त मौलिक अधिकार, शिक्षा का अधिकार कानून-2009 को लगभग 10 साल पूरे हो गए और पिछले पांच सालों से बन रही राष्ट्रीय शिक्षा नीति के परिप्रेक्ष्य में पेश मौजूदा बजट फिर से घोर निराशाजनक साबित हुआ है। सकल घरेलू उत्पाद का 6 प्रतिशत बजट आवंटन पर शिक्षा पर खर्च करने की मांग लंबे समय से की जा रही है। पर सरकार इसमें विफल रही है।

● धर्मेन्द्र सिंह कथूरिया

दलित और आदिवासियों के उत्थान की बात करने वाली भाजपा की केंद्र सरकार ने इस बार बजट में ऐसी बाजीगरी की है कि दलितों और आदिवासियों के हाथ निराशा लगी है। आमजन भी यह कहते सुने गए कि महंगाई और बढ़ती कीमतों पर कोई नियंत्रण नहीं तो बजट का कोई मतलब नहीं। नेशनल कंफेडरेशन आफ दलित एंड आदिवासी आर्गनाइजेशंस (नैकडोर) ने 'जन-जन के बजट' 2020 की समीक्षा की है। बजट में अनुसूचित जातियों की 16.6 प्रतिशत आबादी के विकास के लिए केवल 2.74 प्रतिशत आवंटन किया गया है। दरअसल बजट आंकड़ों की बाजीगरी का अखाड़ा बनता जा रहा है। यह बजट दलितों और आदिवासियों के लिए हाथी के दांत की तरह है। यह दिखता बड़ा है पर असल में दलितों और आदिवासियों को देता बहुत कम है। आइए इस हकीकत को समझें।

राष्ट्रीय मानव अधिकार अभियान-दलित आर्थिक अधिकार आंदोलन के अनुसार केंद्र सरकार 'सबका साथ सबका विकास' की बात करती है। और आश्चर्य करती है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति तथा बाकी आबादी के बीच जो विकास की खाई है उसको पाटने के लिए विकास के फासले को समाप्त किया जाएगा। लेकिन जब हम इनके दिए गए आंकड़ों का विश्लेषण करते हैं तो इनकी कथनी और करनी का फर्क शीशे की तरह साफ हो जाता है। इनका विश्लेषण तीन प्रकार से किया जाता है। 1. आवंटन के आधार पर 2. उन लक्षित स्कीमों के औसत के आधार पर जो अनुसूचित और अनुसूचित को सीधे-सीधे लाभ पहुंचाती हैं और 3. बजट की विश्वसनीयता जो कि इस खाई को पाटने के उपाय करती है। यानी स्कीमों के लिए कितना बजट आवंटित किया जाता है और कितना बजट उपयोग किया जाता है।

इस वर्ष अनुसूचित जाति कल्याण आवंटन के तहत 323 स्कीमों के लिए 83, 257 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। इसी प्रकार अनुसूचित जनजाति के कल्याण आवंटन के तहत 331 स्कीमों के लिए 53,653 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। यानी सरकार अनुसूचित एवं अनुसूचित जनजाति की बाकी आबादी के बीच की खाई पाटने का दावा कर रही थी लेकिन बजट 2020-21 में वह परिलक्षित नहीं रहा। क्योंकि अनुसूचित जनजाति बजट के तहत लक्षित योजनाओं के लिए सिर्फ 19.43 प्रतिशत और अनुसूचित जनजाति के लिए 36.2 प्रतिशत आवंटित किए गए हैं। बाकी सामान्य योजनाओं को अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति का मुखौटा पहना दिया गया है। यानी नाम यह कि यह बजट अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आवंटित किया गया है पर लाभ मिलेगा सामान्य आबादी को!

अबकी बार दिल्ली में जय हनुमान



दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी की जीत कोई साधारण जीत नहीं है। क्योंकि भय और जहर से भरपूर उच्चस्तरीय और फिजूल खर्ची के अभियान के बावजूद विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी भाजपा, उसकी विचारधारा और नीतियों पर हुए जनमत संग्रह में बुरी तरह से हार गई है। दिल्ली की जनता ने यह दिखा दिया कि वह भावनाओं में बहने वाली नहीं है। उसने विकास पर मुहर लगाई है।

● राजेंद्र आगाल

म हाभारत काल में इन्द्रप्रस्थ के नाम से ख्यात दिल्ली में संपन्न हुए विधानसभा चुनाव में इस बार कुरुक्षेत्र जैसा नजारा देखने को मिला। दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार को हराने के लिए भगवान श्रीराम के नाम पर राजनीति करने वाली भाजपा ने साम-दाम-

दण्ड-भेद सबका प्रयोग किया, लेकिन अरविंद केजरीवाल की हनुमान भक्ति के सामने उनकी एक नहीं चली। और दिल्ली में 'अबकी बार जय हनुमान' का नारा बुलंद हो गया।

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी ने 70 सदस्यीय विधानसभा में 62 सीटें हासिल की हैं, जिससे

भाजपा के खाते में 8 सीटें आई हैं। पिछली विधानसभा (2015) में भाजपा के पास तीन जबकि 'आप' के पास 67 सीटें थीं। 'आप' को कुल मिलाकर 53.6 प्रतिशत वोट मिले हैं, जो पिछली बार के 54.3 प्रतिशत के बराबर ही हैं। भाजपा अपने दो सहयोगियों के साथ मिलकर लड़ी और लगभग 40 प्रतिशत वोट हासिल किए हैं, जो

पिछली बार के मिले 32.7 प्रतिशत मत के मुकाबले उल्लेखनीय वृद्धि है। तीसरी बड़ी पार्टी, कांग्रेस का तो सफाया ही हो गया है क्योंकि उसका वोट शेयर 2015 के 9.3 प्रतिशत से घटकर केवल 4.4 प्रतिशत रह गया है। यह एक ऐसी पार्टी थी जो एक दशक पहले राजधानी शहर में 40 प्रतिशत से अधिक वोट पाती थी।

सबसे भड़काऊ अभियान

दिल्ली ने अब तक के हुए चुनाव अभियानों में से इस अभियान को सबसे भड़काऊ अभियान माना है। जिसे नरेंद्र मोदी मंत्रिमंडल और भाजपा के 240 संसद सदस्यों ने चलाया। जिसका संचालन व्यक्तिगत रूप से गृहमंत्री अमित शाह ने किया था। इस अभियान से जो नतीजे निकले उसका संदेश काफी स्पष्ट और चौंकाने वाला है। वह यह कि दिल्लीवालों ने नफरत की राजनीति



को स्वीकार नहीं किया। इस बार भाजपा ने बड़े ही उग्र तरीके से चुनाव लड़ा। इसने तीन प्रमुख मुद्दों को उठाया, जो सभी हिंदुत्व के एजेंडे का प्रतिनिधित्व करते थे जिनमें मुख्य है- अनुच्छेद 370, नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) और राम मंदिर मुद्दे का समाधान। लेकिन यह अभियान का सिर्फ एक ढांचा था। जमीनी अभियान में इसने मुसलमानों के खिलाफ नफरत का खुला और चौंकाने वाला विस्फोट किया था, जिसमें उन्होंने आरएसएस के झूठ और विकृतियों का इस्तेमाल किया था। यह कोई गुप्त तरीके से चलने वाला कानाफूसी का अभियान नहीं था, इसके लिए दहाड़ने और गर्जन करने वाले नेता चुने गए, भीड़ को उकसाया गया, नारे लगाए गए और खुली धमकी दी गई।

नफरत बनाम विकास

दिल्ली विधानसभा चुनाव में जिस तरह के नजारे देखने को मिले उससे इस चुनाव को भाजपा की नफरत बनाम अरविंद केजरीवाल के विकास का चुनाव माना गया। भाजपा ने जिस तरह आक्रामक तरीके से चुनावी ताल ठोकी और अरविंद केजरीवाल को आतंकवादी तक करार दिया उसके इस तरह के अभियान से दिल्ली के मतदाता चिंतित और परेशान हो गए थे। इस तरह के घृणित विचारों और भावनाओं की चकाचौंध में शहर आहत हुआ और आगबबूला भी हो गया था। भाजपा की बुरे ख्वाबों की दृष्टि भयावह थी और उसने कई लोगों को भ्रमित कर दिया था।

दूसरी ओर, 'आप' पार्टी पिछले पांच वर्षों में किए गए कामों के बारे में बात करने के अपने निर्धारित ट्रैक पर अटकी रही। जिसमें उन्होंने सस्ती और अच्छी शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा, बिजली और पीने के पानी की दरों में कमी, आदि में सरकार की भूमिका और उपलब्धियों का उचित दावा पेश किया। इस कल्याणकारी दृष्टिकोण ने 'आप' को बहुत लोकप्रिय बना दिया था, क्योंकि इसने दिल्ली के संघर्षरत आम आदमी को आवश्यक राहत प्रदान

की थी; जो बढ़ती बेरोजगारी, स्थिर आय और बुनियादी भोजन और अन्य आवश्यकता की सामग्री की आसमान छूती महंगाई का सामना कर रहे थे। दरअसल, यह दो तरह की राजनीति की लड़ाई थी। एक, सांप्रदायिक की चोट करना, हिंसा का डर फैलाना, सबसे अपमानजनक झूठ, गाली और जहरीला प्रचार करना। दूसरा एक खास किस्म का विकासात्मक प्रकार का एजेंडा था, जिसमें विभिन्न वर्गों को अपील गई थी, जो कि दृष्टिकोण और

स्वच्छता और ईमानदारी के साथ धर्मनिरपेक्षता का वादा करता था। शाह ने खुद इसे दो विचारधाराओं के बीच की लड़ाई करार दिया, हालांकि उन्होंने 'आप' की विचारधारा को गद्दारों की विचारधारा कहा। इस पृष्ठभूमि में दिल्ली के मतदाताओं की पसंद न केवल स्पष्ट और दो टूक है। बल्कि यह आरएसएस की राजनीति की जानबूझकर की गई अस्वीकृति है, जिस

राजनीति को भाजपा ने दिल्ली में प्रसारित किया था।

यह अमित शाह की हार

दिल्ली चुनाव में जीते तो केजरीवाल हैं, लेकिन हारा कौन? निश्चित तौर पर भाजपा। लेकिन भाजपा में भी कौन? वही जिसके नाम पर पूरा चुनाव लड़ा गया और वह एक नाम है अमित शाह। जी हां, आप इस गलतफहमी में मत रहना कि इस चुनाव में प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी या नए नवेले राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की हार हुई है। या फिर किसी और उम्मीदवार की हार हुई है। जिस तरह अब गोदी मीडिया साबित करना चाहता है। जिसने अपने बीजी-स्टिंग में नरेंद्र मोदी और अमित शाह के चेहरे की बजाय मनोज तिवारी और जेपी नड्डा का चेहरा लगाना शुरू कर दिया। जबकि इससे पहले वही मीडिया अमित शाह को चुनाव का चाणक्य और न जाने क्या-क्या नाम से पुकार रहा था। इस चुनाव में वही चाणक्य धड़म से गिर गए। दिल्ली का पूरा चुनाव भाजपा ने व्यक्ति के तौर पर अमित शाह के नाम पर लड़ा और राजनीति के तौर पर नफरत की राजनीति के सहारे लड़ा, लेकिन इन दोनों की ही इस चुनाव में हार हुई है। वास्तव में अगर इस चुनाव में भाजपा जीतती तो उसका सारा श्रेय अमित शाह और उनकी रणनीति को ही जाता। यह पहली बार था कि देश के किसी भी राज्य के चुनाव की तरह पोस्टर पर चेहरा तो दिल्ली में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दिया गया लेकिन चुनाव वास्तव में गृहमंत्री अमित शाह लड़ रहे थे।

वोट शेयर के समीकरण

अब परिणामों पर कुछ नज़र डालते हैं। जैसा कि उल्लेख किया गया है, 'आप' ने अपना वोट शेयर बरकरार रखा है जबकि भाजपा ने अपने शेयर में सात प्रतिशत से अधिक का इजाफा किया है। इस बीच, कांग्रेस को लगभग पांच प्रतिशत वोटों का नुकसान हुआ है, जबकि अन्य सभी - बहुजन समाज पार्टी नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, आदि के साथ-साथ निर्दलीय उम्मीदवारों को पूरी तरह से अस्वीकार कर दिया गया है। स्पष्ट रूप से यह 'आप' और भाजपा के बीच सीधा मुकाबला था, कांग्रेस के पुनरुत्थान का मिथक का बुलबुला भी इसी के साथ फूट गया। क्या इसका मतलब यह है कि कांग्रेस के मतदाताओं ने भाजपा को समर्थन कर दिया है, क्योंकि कुछ इस पर विश्वास करेंगे? नहीं, यह एक त्रुटिपूर्ण रूप से गलत धारणा होगी- और आलसी विश्लेषण होगा। पिछली बार (2015 में), कांग्रेस के वोटों का बड़ा हिस्सा मुस्लिम बहुल सीटों और निम्न मध्यम वर्ग या मजदूर वर्ग के इलाकों में था। ऐसा नहीं है कि उन्हें बहुत कुछ मिला, लेकिन जो कुछ भी था, इन वर्गों से मिला था, जिसमें कुछ समर्थन पारंपरिक मध्यम वर्ग से भी हासिल हुआ था। इस बार, मुस्लिम और श्रमिक वर्ग से जुड़े मतदाता 'आप' की तरफ हो लिए। यह मुख्य रूप से 'आप' की कल्याणकारी नीतियों का नतीजा था और सीएए का विरोध। इसलिए 'आप' के उम्मीदवार सबसे आगे थे।



भाजपा के 'जय श्रीराम' को आप का जवाब 'जय हनुमान'

दिल्ली विधानसभा चुनाव परिणाम के साथ ही अरविंद केजरीवाल की हनुमान भक्ति ने भाजपा की परेशानी बढ़ा दी है। दिल्ली चुनाव में भारी जीत का श्रेय भी केजरीवाल ने हनुमानजी को दिया। मंत्र के आम आदमी पार्टी के नेताओं का कहना है कि खुद को 'कट्टर हनुमान भक्त' के तौर पर पेश करने का निर्णय केजरीवाल ने अनायास नहीं लिया है। दशकों से 'जय श्रीराम' का नारा लगाकर खुद को हिंदुत्व का पैरोकार बताने वाली भाजपा को अब आप 'जय बजरंग बली' या 'जय हनुमान' के नारे से जवाब दे सकती है। केजरीवाल के एक सहयोगी ने बताया कि पार्टी हनुमानजी के शुभंकर को उसी तरह अपनाने के बारे में गंभीरता से विचार कर रही है जैसे भाजपा पिछले तीन दशकों से भगवान श्रीराम का इस्तेमाल करती रही है। भाजपा आप को हिंदू विरोधी या राष्ट्र विरोधी नहीं बता सकेगी। हमारे नेता खुद को हनुमानजी के भक्त के रूप में बताते हैं क्योंकि हनुमानजी ही भगवान श्रीराम के परम भक्त हैं जिनके इर्द-गिर्द भाजपा अपनी राजनीति चलाती है।

भाजपा का सांप्रदायिक सूट

भाजपा ने अपना वोट कहां से बढ़ाया? यह वह केंद्र बिन्दु है जहां भाजपा के वीभत्स अभियान की खतरनाक विरासत निहित है। यह इस अभियान का ही एक परिणाम था जिसने उन लोगों के एक वर्ग को आकर्षित किया, जिन्होंने पिछली बार 'आप' को वोट दिया था, लेकिन इस बार सांप्रदायिक बयानबाजी से प्रभावित हुए हैं। बड़ी बात यह है कि यह हिस्सा बहुत बड़ा नहीं है। लेकिन यह संभावित रूप से एक परेशान करने वाला तथ्य है, क्योंकि भाजपा ने सांप्रदायिक घृणा के बीज बोए हैं, वे संकीर्ण चुनावी लाभ के लिए हैं और ये आने वाले समय में जहरीले फलों का उत्पादन करेंगे, यदि उनका मुकाबला समय रहते नहीं किया गया।

भाजपा को यह सोचने की जरूरत है कि वह भारत और उसके लोगों को कैसे देखती है। पिछले एक साल में, मई 2019 में लोकसभा चुनाव जीतने के बावजूद पार्टी कई राज्यों में चुनाव हार चुकी है। विनाशकारी आर्थिक नीतियों के कारण इसका समर्थन तेजी से घट रहा है। भगवा पार्टी ने केंद्रीय स्तर पर विश्वसनीयता बनाए रखी है, वह केवल इसलिए कि उसमें लोगों को यह समझने की क्षमता है कि वह अकेले देश की सबसे समर्पित रक्षक है, और नफरत की अपनी राजनीति के माध्यम से ज्वलंत मुद्दों से ध्यान हटाने में कामयाब है। वामपंथ को छोड़कर, सभी राजनीतिक दलों की अक्षमता के कारण उन्हें जमीन पर अपनी कहानी

के समर्थन में मदद मिली है। लेकिन, यह समर्थन लंबे समय तक नहीं रहेगा। जैसा कि आर्थिक संकट बढ़ रहा है, और भाजपा-आरएसएस के मध्ययुगीन सपने उजागर हो रहे हैं जो कि अपने आप में काफी डरावने सपने हैं, यह तिलस्म टूटना निश्चित है।

जनकल्याणकारी कार्यों पर मुहर

जरा सोचिए कि क्या तब कोई दल जनकल्याण के मुद्दों को खारिज कर चुनावों में संकुचित एवं गैर जरूरी मसलों के सहारे वोट बटोरने का साहस करेगा जब समाज को जाति, मजहब, क्षेत्र जैसे मसले प्रभावित न करते हों? दिल्ली विधानसभा के चुनाव नतीजे देश के करीब 90 करोड़ मतदाताओं को यही संदेश दे रहे हैं कि ऐसा हो सकता है। वास्तव में आम आदमी पार्टी की ओर से जनकल्याण के मुद्दों पर कहीं अधिक ध्यान केंद्रित करने के कारण ही दिल्ली के मतदाताओं ने उसे फिर से सत्ता सौंपी है।

दिल्ली में ऐसे वक्त चुनाव हो रहे थे जब नागरिकता संशोधन कानून को लेकर मुस्लिम समाज में नाराजगी व्याप्त थी और वह उसे खुलकर व्यक्त भी कर रहा था। दिल्ली के शाहीन बाग इलाके में इस कानून के खिलाफ धरना भी जारी था। यह अभी भी जारी है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस धरने को जनता को बांटने वाला आंदोलन करार देते हुए एक संयोग नहीं, प्रयोग बताया। कुल मिलाकर भाजपा की ओर से शाहीन बाग धरने को चुनावी मुद्दा बनाने की

इसलिए जीती आप

भाजपा के चुनाव प्रचार पर स्थानीय मुद्दों की बजाय राष्ट्रवाद और राष्ट्रीय मुद्दों का ही जिक्र मिला। जबकि आप केवल दिल्ली की बात करती रही। वहीं इस बार भाजपा केजरीवाल के खिलाफ कोई चेहरा खड़ा नहीं कर पाई। केजरीवाल बार-बार चुनौती देते रहे अगर भाजपा में हिम्मत है, तो सीएम उम्मीदवार घोषित करके दिखाए। इसके जवाब में भाजपा ने कहा- 'दिल्ली की जनता उसका चेहरा है।' वहां दिल्ली चुनाव में कांग्रेस कहीं दिखाई नहीं दी। उसके उम्मीदवार और स्टार प्रचारकों ने भी प्रचार पर ज्यादा जोर नहीं दिया। अगर कांग्रेस दमखम से लड़ती तो उसे एंटी-भाजपा और एंटी-आप वोट मिलने की संभावना थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसका सीधा फायदा आप को हुआ। चुनाव प्रचार के दौरान मोदी और अमित शाह शाहीन बाग में चल रहे प्रदर्शन के लिए आप को जिम्मेदार ठहराते रहे। लेकिन केजरीवाल ने भी यह कह दिया कि अगर दिल्ली पुलिस उनके हाथ में होती, तो दो घंटों में शाहीन बाग का रास्ता खुलवा देता। इस चुनाव में केजरीवाल का सॉफ्ट हिंदुत्व भी देखने को मिला। केजरीवाल ने खुद को हनुमान का भक्त बताया, जिस पर भाजपा ने सवाल किया कि क्या उन्हें हनुमान चालीसा भी आती है। इसके बाद केजरीवाल ने हनुमान चालीसा भी गाकर सुनाई। वोटिंग से एक दिन पहले भी केजरीवाल हनुमान मंदिर गए थे। आप की जीत की सबसे बड़ी वजह रही सरकार की विकासवादी नीतियां। आप की सरकार आते ही एक तरफ सरकार ने प्राइवेट स्कूलों को मनमानी फीस बढ़ाने से रोका तो दूसरी तरफ सरकारी स्कूलों पर भी फोकस किया। लोगों को सस्ता और अच्छा इलाज मुहैया करने के मकसद से केजरीवाल सरकार ने 400 से ज्यादा मोहल्ला क्लीनिक खोलीं। केजरीवाल सरकार ने 6 महीने पहले ही 200 यूनिट तक की बिजली फ्री देने की घोषणा की थी। जबकि 201 से 400 यूनिट तक की बिजली इस्तेमाल करने वालों को 50 प्रतिशत सब्सिडी देने का ऐलान किया। सरकार ने हर महीने लोगों को 20 हजार लीटर पानी फ्री देने का ऐलान किया। सरकार के मुताबिक, इससे 14 लाख लोगों को लाभ हुआ। चुनाव से तीन महीने पहले आप सरकार ने डीटीसी बसों और मेट्रो में महिलाओं के सफर को फ्री किया। आप के रिपोर्ट कार्ड के मुताबिक, सरकार महिला सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए 1.4 लाख सीसीटीवी कैमरे लगा चुकी है, जबकि 2 लाख स्ट्रीट लाइट लगाए गए हैं। महिला सुरक्षा के अलावा केजरीवाल सरकार ने कच्ची कॉलोनियों के निर्माण पर भी ध्यान दिया। रिपोर्ट कार्ड में दावा किया कि सरकार ने 5 साल में 1,797 में से 1,281 कॉलोनियों में सड़कें बनाईं, जबकि 1130 कॉलोनियों में सीवर लाइनें बिछाईं।

चुनाव दर चुनाव सिकुड़ती भाजपा

2014 से 2020 इन 6 सालों में अगर भाजपा का सफर देखें तो चुनाव दर चुनाव, राज्य दर राज्य भाजपा सिकुड़ती जा रही है। सिमटती जा रही है। 2018 में राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ गंवाने के बाद 2019 में भाजपा ने महाराष्ट्र भी गंवा दिया और हरियाणा बामुश्किल बचाया अब 2020 की शुरुआत में भी झारखंड गंवाने के बाद दिल्ली भी हासिल नहीं हो सका। भाजपा के नेतृत्व वाला एनडीए पिछले दो साल में सात राज्यों में सत्ता गंवा चुका है। दूसरी बार मोदी सरकार बनने के बाद 4 राज्यों में चुनाव हुए, जिसमें से तीन चुनाव भाजपा हार गई। पिछली बार दिल्ली में महज 3 सीटें जीतने वाली भाजपा को इस बार बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद थी। दिल्ली के प्रदेश भाजपा अध्यक्ष मनोज तिवारी ने 48 सीटों पर जीत के अनुमान के साथ सत्ता में आने की उम्मीद जताई थी। हालांकि, ये अनुमान गलत साबित हुए। इसी के साथ भाजपा के लिए देश का सियासी नक्शा भी नहीं बदला। दिल्ली समेत 12 राज्यों में अभी भी भाजपा विरोधी दलों की सरकारें हैं। एनडीए के पास 16 राज्यों में ही सरकार है। इन राज्यों में 42 प्रतिशत आबादी रहती है। कांग्रेस खुद के बूते या गठबंधन के जरिए महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़, पंजाब, पुडुचेरी में सत्ता में है। दिसंबर में हुए चुनाव में झारखंड में सरकार बनने के बाद कांग्रेस की 7 राज्यों में सरकार है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी लगातार तीसरी बार जीती है। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस, केरल में माकपा के नेतृत्व वाला गठबंधन, आंध्र प्रदेश में वाईएसआर कांग्रेस, ओडिशा में बीजद और तेलंगाना में टीआरएस सत्ता में है। एक और राज्य तमिलनाडु है, जहां भाजपा ने अन्नाद्रमुक के साथ लोकसभा चुनाव तो लड़ा था, लेकिन राज्य में उसका एक भी विधायक नहीं है। इसलिए वह सत्ता में भागीदार नहीं है। दिसंबर 2017 में एनडीए बेहतर स्थिति में था। भाजपा और उसके सहयोगी दलों के पास 19 राज्य थे। एक साल बाद भाजपा ने तीन राज्यों मध्यप्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में सत्ता गंवा दी। यहां अब कांग्रेस की सरकारें हैं। चौथा राज्य आंध्र प्रदेश है, जहां भाजपा-तेदेपा गठबंधन की सरकार थी। मार्च 2018 में तेदेपा ने भाजपा से गठबंधन तोड़ लिया। 2019 में हुए विधानसभा चुनाव में यहां वाईएसआर कांग्रेस ने सरकार बनाई। पांचवां राज्य महाराष्ट्र है, जहां चुनाव के बाद शिवसेना ने एनडीए का साथ छोड़ा और हाल ही में कांग्रेस-राकांपा के साथ मिलकर सरकार बना ली। इसके बाद झारखंड में भी भाजपा सत्ता गंवा चुकी है, वहां अब कांग्रेस-झामुमो गठबंधन की सरकार है।



हरसंभव कोशिश की गई। इसमें उसके कुछ नेताओं ने आपत्तिजनक बयान भी दिए। केजरीवाल को आतंकवादी कहा गया। इस पर एक केंद्रीय मंत्री ने कहा कि केजरीवाल तो खुद को अराजकतावादी कहते हैं और आतंकवादी एवं अराजकतावादी में ज्यादा अंतर नहीं होता।

जनता आप पर हुई मेहरबान

अगर इस सबके बावजूद आम आदमी पार्टी को जनता ने चुना तो क्या यह शाहीन बाग आंदोलन पर मतदाताओं की मुहर है? नहीं। यह संदेश है कि जो असल में हमारे स्वास्थ्य, शिक्षा और हमारे कल्याण के लिए बिजली और पानी मुफ्त देगा वही हमारी पसंद भी होगा। आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार के खिलाफ अन्ना आंदोलन के दौरान उपजे राष्ट्रव्यापी जनानंदोलन की पैदाइश है। आंदोलन के अस्थाई स्वरूप के कारण देश की जनता फिर वापस जाति, संप्रदाय और अन्य संकीर्ण भावनाओं में बहने लगी।

शिक्षा पर दिखाया बड़ा दिल

चूंकि दिल्ली में सरकार के पास बहुत ही सीमित शक्तियां हैं, लिहाजा 2015 में 70 में से 67 सीटों के साथ सत्ता में आने के बावजूद आप सरकार को पग-पग पर बाधाएं मिलीं, लेकिन उसने अपने पहले बजट में एक तिहाई राशि शिक्षा के लिए और एक बड़ा

अंश स्वास्थ्य के लिए आवंटित किया। करीब 2.10 करोड़ की दिल्ली की कुल आबादी के लिए 2019 में आप सरकार का बजट 60 हजार करोड़ रुपए का हो गया। इसमें से 25 प्रतिशत यानी लगभग 15,000 करोड़ रुपए शिक्षा के लिए आवंटित किए और लगभग साढ़े सात हजार करोड़ रुपए यानी 12.5 प्रतिशत स्वास्थ्य के लिए। दिल्ली सरकार हर परिवार पर रोजाना 50 रुपए खर्च करती है, जबकि केंद्र साढ़े छह रुपए खर्च करती है। अगर उत्तर प्रदेश सरीखे राज्य को देखें तो 2019-20 में योगी सरकार ने 23,488 करोड़ रुपए यानी प्रति परिवार 12 रुपए का आवंटन किया। केंद्र का अंशदान मिला दें तो यह राशि लगभग 18.50 रुपए पहुंचती है। फिर इसमें 75 प्रतिशत हिस्सा प्रशासनिक खर्च में चला जाता है और शेष भाग का बड़ा हिस्सा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है।

‘मुफ्त बिजली’ का मास्टर स्ट्रोक

‘मुफ्त बिजली’ मुख्यमंत्री का मास्टर स्ट्रोक रहा। दिल्ली के निम्न एवं मध्यम वर्ग जिसकी औसत आय 18,000 रुपए से कम है, उसके लिए अच्छी शिक्षा, मुफ्त चिकित्सा, मुफ्त बिजली-पानी अकल्पनीय राहत थी। मोहल्ला क्लिनिक से लेकर गरीब बच्चों के लिए सस्ती और सुलभ शिक्षा उपलब्ध होना दिल्ली की गरीब जनता के लिए दिवास्वप्न के साकार होने जैसा था। दिल्ली में अमीर-गरीब की खाई काफी चौड़ी है।

कांग्रेस की इतनी दुर्गति क्यों?

दिल्ली विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को एक बार फिर से शून्य का स्वाद चखना पड़ा है। दिवंगत शीला दीक्षित के नेतृत्व में 15 साल तक दिल्ली की सत्ता पर राज करने वाली कांग्रेस पार्टी का लगातार दूसरी बार दिल्ली विधानसभा चुनाव में खाता तक नहीं खुला। इतना ही नहीं इस बार के चुनाव में पार्टी का वोट शेयर भी गिरकर आधा हो गया है। साल 2015 के मुकाबले कांग्रेस को इस बार 4.40 फीसदी वोट मिला है, पिछले चुनाव में यह आंकड़ा 10 फीसदी था। नतीजे साफ बता रहे हैं कि कांग्रेस उम्मीदवारों की स्थिति निर्दलीय उम्मीदवारों जैसी हो गई है। यह ठीक है कि दिल्ली के चुनावी दंगल में सीधी जंग भाजपा और अरविंद केजरीवाल के बीच हुई। कांग्रेस शुरू से न तो मुकाबले में दिखाई दी और न ही बेहतर स्थिति में थी। फिर भी ऐसी उम्मीद नहीं थी कि कांग्रेस का पिछली बार की तरह इस बार भी खाता नहीं खुलेगा। अहम बात यह भी कि मई 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस 70 में से 65 सीटों पर दूसरे नंबर पर रही थी, जबकि इस बार वह अपनी यह स्थिति भी बरकरार नहीं रख सकी। कांग्रेस के लिए निश्चित ही यह आत्ममंथन का समय है। कांग्रेस को मिली करारी हार के लिए आला नेतृत्व पूरी तरह से जिम्मेदार है।



यहां साक्षरता दर लगभग 90 प्रतिशत है और प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय औसत का तीन गुना और बिहार के मुकाबले सात गुना है। इस चुनाव परिणाम का संदेश यह भी है कि जैसे-जैसे प्रति व्यक्ति आय और साक्षरता दर बढ़ेगी, वैसे-वैसे जातिवाद और सांप्रदायवाद का बोलबाला भी कम होगा और जनता राजनीतिक दलों को जनकल्याण पर अधिक ध्यान देने के लिए मजबूर करेगी।

जातिवादी राजनीति बेअसर

2014 तक सपा और बसपा सरीखे दलों ने दिल्ली में अपनी पैठ बनाने की कोशिश की, लेकिन उनकी दाल नहीं गली। इस चुनाव में वे कहीं भी नहीं हैं तो इसी कारण कि दिल्ली में जातिवादी राजनीति नाम मात्र की है। दिल्ली में जातिवादी राजनीति के बेअसर रहने का कारण यही है कि यहां की बड़ी आबादी बाहरी लोगों की है और वह इसकी परवाह कम ही करती है कि कौन किस जाति का है? दिल्ली के नतीजे राजनीतिक दलों के लिए एक सीख है। यह उल्लेखनीय है कि केजरीवाल सरकार ने मुफ्त सुविधाएं देने के बावजूद अपने राजस्व को बढ़ाया। यह इसीलिए संभव हुआ, क्योंकि दिल्ली सरकार ने टैक्स का जो भी जरिया उपलब्ध था उसमें भ्रष्टाचार पर लगाम लगाई। इसी कारण उसका राजस्व बढ़ा। क्या अन्य राज्य सरकारें इसे अपनाकर अपने सीमित साधनों से राजस्व बढ़ाने और साथ ही जनता को मुफ्त बिजली-पानी देने का संकल्प ले सकती हैं? जनता अगर चाहे तो मुद्दा आरक्षण पर सस्ती सियासत न होकर सड़क, शिक्षा, अस्पताल और अन्य जन सुविधाएं हो सकती हैं।

काम नहीं आया मप्र के नेताओं का प्रयास

दिल्ली विधानसभा चुनाव में 70 सीटों पर जीत के लिए मप्र के नेताओं ने भी चुनाव प्रचार-प्रसार में पूरी ताकत झोंकी थी। मप्र के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, आधा दर्जन पूर्व मंत्री और सभी 28 सांसदों को दिल्ली में चुनाव प्रबंधन और प्रचार में पार्टी ने लगाया गया था। दिल्ली चुनाव में मप्र के कई नेताओं की इयूटी अलग-अलग विधानसभा सीट पर लगाई गई थी। पूर्व मंत्री नरोत्तम मिश्रा, उमाशंकर गुप्ता, विधायक अरविंद भदौरिया, रामेश्वर शर्मा, मोहन यादव, कृष्णा गौर, पूर्व विधायक ध्रुवनारायण सिंह, सांसद वीडी शर्मा, सांसद सुधीर गुप्ता सहित कई नेताओं को जनवरी के आखिरी सप्ताह में ही दिल्ली भेज दिया गया था। इन नेताओं ने जमकर प्रचार किया। लेकिन इनकी मेहनत काम नहीं आई। वहीं मप्र कांग्रेस के कुछ नेताओं ने भी चुनाव प्रचार किया था। व्यस्त होने के कारण सीएम कमलनाथ नहीं पहुंचे थे। लेकिन पूर्व सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, राजस्व मंत्री गोविंद सिंह राजपूत और उच्च शिक्षा एवं खेल मंत्री जीतू पटवारी, विधायक कुणाल चौधरी दिल्ली के रण में स्टार प्रचारक थे। दिल्ली विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का सूपड़ा लगभग साफ होने और भाजपा की सीटों का आंकड़ा बहुत ज्यादा नहीं बढ़ने से मप्र के नेता भी खुश हैं। कांग्रेस यह कह कर खुश है कि दिल्ली की जनता ने भाजपा को पूरी तरह से नकार दिया है। वहीं, पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान का कहना है कि भाजपा का वोट शेर दिल्ली में बढ़ा है। कांग्रेस का तो दिल्ली में सूपड़ा साफ हो चुका है।

यह तभी होगा जब जनता संकीर्ण भावनाओं से परे उठकर अपनी सोच को जनकल्याण के मुद्दों की ओर ले जाएगी। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सत्ता में वापसी के मूल कारणों पर इसलिए गौर किया जाना चाहिए, क्योंकि वे राजनीतिक दलों के साथ ही देश की जनता को भी संदेश दे रहे हैं।

गुटबाजी के कारण हारी भाजपा

दिल्ली में भाजपा का वनवास और बढ़ गया है। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के चुनाव प्रबंधन को संभालने और शाहीन बाग को चुनावी मुद्दा बनाने से भाजपा के वोट तो बढ़े, लेकिन सीटों में अपेक्षित बढ़ोतरी नहीं हुई। भाजपा मात्र आठ सीटों पर ठिठक गई। पार्टी की इस दुर्गति का सबसे बड़ा कारण दिल्ली में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के मुकाबले मजबूत स्थानीय चेहरे का न होना माना जा रहा है। दिल्ली भाजपा स्थानीय नेतृत्व को मजबूत करने के बजाय पूरी तरह से केंद्रीय नेतृत्व पर निर्भर रही, जिसका खामियाजा उसे भुगतना पड़ा। दिल्ली में भाजपा पहली बार मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किए बिना चुनाव मैदान में उतरी थी और यह प्रयोग सफल नहीं रहा। चेहरा घोषित नहीं करने के पीछे दिल्ली में भाजपा नेताओं की गुटबाजी बताई जा रही है। पार्टी के पास कोई ऐसा सर्वमान्य नेता नहीं था, जो सभी को साथ लेकर चल सके। प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी के साथ ही केंद्रीय मंत्री डॉ. हर्षवर्धन, राज्यसभा सदस्य विजय गोयल, सांसद प्रवेश वर्मा सहित कई नेता मुख्यमंत्री पद की दौड़ में शामिल थे, जिससे पार्टी में गुटबाजी बढ़ती चली गई।

मुफ्त योजना के खिलाफ नहीं हुआ काम

भाजपा नेतृत्व को उम्मीद थी कि आप की मुफ्त बिजली-पानी व महिलाओं की मुफ्त बस यात्रा योजना के जवाब में उनका राष्ट्रवादी और सांप्रदायिक दांव कारगर साबित होगा, लेकिन दिल्ली के नेता इसे भुनाने में असफल रहे। इस स्थिति को देखते हुए केंद्रीय नेतृत्व ने पूरे चुनाव अभियान को अपने हाथ में ले लिया। अमित शाह ने खुद धुआंधार चुनाव प्रचार किया। इसके साथ ही भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा भी लगभग सभी विधानसभा क्षेत्रों में पहुंचे। बूथ प्रबंधन के लिए भी पार्टी ने दूसरे राज्यों के नेताओं को दिल्ली बुलाया और देशभर से लगभग तीन सौ सांसदों को मैदान में उतार दिया।

कई 'किंतु-परंतु' से भाजपा की हार टंकने की कोशिश

दिल्ली के विधानसभा चुनाव में भाजपा की हार को कई तरह के किंतु-परंतु और लेकिन के माध्यम से टंकने की कोशिश की जा रही है। भाजपा की हार के मूल मुद्दों और कारणों को सामने आने से बचाने का एक संगठित प्रयास हो रहा है। ऐसा करने के पीछे अपने-अपने निहित स्वार्थ हैं। ये भाजपा के नेतृत्व को किसी और असहज स्थिति में नहीं डालना चाहते हैं और कुछ ऐसी छोटी-छोटी चीजों पर लोगों का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे शीर्ष नेतृत्व की बदनीयती छुपी रहे। आखिर ऐसा क्या कारण है कि लोकसभा चुनाव में 56 प्रतिशत मत हासिल करने वाली और पिछले 15 साल से दिल्ली के सभी नगर-निगमों में बहुमत हासिल कर रही भाजपा को विधानसभा में केवल 8 सीटों से संतोष करना पड़ा है।

क्या शापित है विधानसभा ?



40 दिन के अंतराल में मध्य प्रदेश के दो विधायकों का निधन हो गया है। 21 दिसंबर 2019 को मुरैना जिले के जौरा विधानसभा सीट से कांग्रेस विधायक बनवारी लाल शर्मा की मौत हुई थी। 30 जनवरी को आगर-मालवा से भाजपा विधायक मनोहर ऊंटवाल का भी असमय निधन हो गया। प्रदेश में बीते 15 साल में 33 विधायकों का निधन हो चुका है। बीते 3 विधानसभा कार्यकाल में एक साल भी ऐसा नहीं रहा जब सदन में विधायकों की संख्या पूरी रही हो। 230 सदस्यीय विधानसभा में 2 विधायकों की मौत के बाद सदस्य संख्या 228 हो गई है। 40 दिन में दो विधायकों की मौत के बाद एक बार फिर विधानसभा में वास्तुदोष की चर्चा शुरू हो गई है।

हाल ही में संपन्न हुए विधानसभा के शीतकालीन सत्र में विधायक बनवारी लाल शर्मा को श्रद्धांजलि देने के दौरान विधानसभा में वास्तुदोष पर चर्चा हुई थी। बनवारी लाल शर्मा को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव ने कहा था कि हर विधानसभा में सदस्यों के निधन होने की संख्या आठ-दस तक पहुँच जाती है। तत्कालीन विधानसभा अध्यक्षों श्रीनिवास तिवारी और ईश्वरदास रोहणी तथा अन्य ने भी इस संबंध में चिंता की थी। इस भवन में कई अनुष्ठान भी किए गए, जिन्हें कई लोगों ने माना। कई लोगों ने इसकी हंसी भी उड़ाई।

दरअसल, जबसे नई विधानसभा शुरू हुई है तभी से कुछ ना कुछ अनहोनी हो रही है। इसके शुभारंभ के कुछ दिन बाद ही इसके मुख्य दरवाजे की छत का प्लास्टर गिर गया था। दिग्विजय सिंह सरकार के कार्यकाल के दौरान 10 साल विधानसभा अध्यक्ष रहे कांग्रेस नेता श्रीनिवास तिवारी और भाजपा सरकार के कार्यकाल में अध्यक्ष रहे ईश्वरदास रोहणी के कार्यकाल में जब विधायकों की असमय मौत

हुई थी तब भी विधानसभा में वास्तुदोष का मुद्दा सदन और सदन के बाहर काफी गर्माया था। श्रीनिवास तिवारी ने वास्तु विशेषज्ञों की सलाह पर विधानसभा में अनुष्ठान भी कराया था और विधानसभा की बैठक व्यवस्था में कुछ परिवर्तन भी कराए थे। विधानसभा भवन को विख्यात आर्किटेक्ट चार्ल्स कोरिया ने डिजाइन किया था। इस भवन को उत्कृष्ट वास्तु के लिए विख्यात आगा खां अवॉर्ड भी मिल चुका है। इसके पहले 1956 से अगस्त 1996 तक विधानसभा का संचालन मिंटो हॉल में होता रहा। मिंटो हॉल के बाद अगस्त 1996 में विधानसभा नए भवन में शिफ्ट हुई थी। विधानसभा भवन का उद्घाटन 1996 में तत्कालीन राष्ट्रपति डॉ. शंकरदयाल शर्मा ने किया था। इस भवन में विधानसभा आने के तत्काल बाद तत्कालीन वन एवं परिवहन मंत्री लिखीराम कांवरे की नक्सलियों ने गला रेंटकर हत्या कर दी थी।

भोपाल के ज्योतिषाचार्य और वास्तुविद पंडित धर्मेन्द्र शास्त्री ने विधानसभा भवन के कुछ वास्तुदोष पर अध्ययन कर इसके तीन कारण बताए हैं। विधानसभा भवन का गोलाकार चारों कोने कटे हुए है और नाभि स्थल ब्रह्म स्थान सबसे नीचा है इस कारण उसके सदस्यों की हानि होती है। दक्षिण-पश्चिम दिशा के द्वार से आने वाली सड़क में भी वास्तुदोष है। भवन के पास में स्थित छोटा तालाब भी वास्तुदोष का कारण है। पंडित धर्मेन्द्र शास्त्री के अनुसार विधानसभा भवन के अंदर चारों कोणों को ठीक करवाने का काम किया जाए। चारों कोणों में दर्पण लगवाकर वास्तुदोष समाप्त किया जा सकता है। विधानसभा भवन की चारों दिशाओं में अभिमंत्रित वास्तुदोष निवारक यंत्र विधि-विधान से स्थापित करवाकर भी वास्तुदोष समाप्त किया जा सकता है। विधानसभा भवन में वास्तु मंत्र के पाँच लाख जाप करवाकर विधिवत वास्तुदोष शांति पूजा अनुष्ठान करवाने से वास्तुदोष निवारण होगा।

● सिद्धार्थ पांडे

अब तक 33...

नई विधानसभा में सबसे विधानसभा सत्र आयोजित किए जा रहे हैं तबसे लेकर अभी तक 33 विधायकों का निधन हो चुका है। कोई इसे विधानसभा का वास्तु दोष मान रहा है, तो कोई विधायकों के निधन को स्वभाविक मान रहा है। लेकिन 11वीं विधानसभा से लेकर 15वीं विधानसभा तक विधायकों का लगातार हो रहा निधन वाकई चिंता का विषय है। हालांकि प्रदेश के अधिकांश विधायक विधानसभा में वास्तु दोष की बात नहीं मानते। गौरतलब है कि वास्तु दोष के कारण विधानसभा में विधायकों के प्रवेश की व्यवस्था भी बदल दी गई है। फिर भी विधायकों के निधन का सिलसिला थमा नहीं है।

15वीं विधानसभा में

2020- आगर-मालवा विधायक मनोहर ऊंटवाल

2019- जौरा विधायक बनवारी लाल शर्मा

14वीं विधानसभा में

2014- बहोरीबंद विधायक - प्रभात पांडेय

2015- गरोट विधायक - राजेश यादव

2015 - देवास विधायक - तुकोजी पवार

2016 - घोड़ाडोंगरी विधायक - सज्जन सिंह उइके

2016- नेपानगर विधायक - राजेंद्र श्यामलाल

2016- अटेर विधायक - सत्यदेव कटारे

2017- चित्रकूट विधायक - प्रेम सिंह

2017- मुंगावली विधायक - महेंद्र सिंह कालुखेड़ा

2017- कोलारस विधायक - रामसिंह यादव

13वीं विधानसभा

2009- गोहद विधायक - माखनलाल जाटव

2010- कुक्षी विधायक - जमुनादेवी

2011- जबरा विधायक - रत्नेश सॉलोमन

2013- नीमच विधायक - खुमान सिंह शिवाजी

2013- केवलारी विधायक - हरवंश सिंह

2013- जबलपुर विधायक - ईश्वरदास रोहणी

12वीं विधानसभा

2006- पंधाना विधायक - किशोरीलाल वर्मा

2007- लांजी विधायक - दिलीप भट्टे

2007- सांवेर विधायक - प्रकाश सोनकर

2008- सारंगपुर विधायक - अमर सिंह कोटार

2008- ब्यौहारी विधायक - लवकेश सिंह

2008- इंदौर विधायक - लक्ष्मण सिंह गौड़

2008- जतारा विधायक - सुनील नायक

11वीं विधानसभा

1999- जबलपुर विधायक - आंकर प्रसाद तिवारी

1999- सोहागपुर विधायक - कृष्णपाल सिंह

1999- मनावर विधायक - दरियाव सिंह सोलंकी

1999- अलीराजपुर विधायक- मगन सिंह पटेल

1999- किरानपुर विधायक - लिखीराम कावरे

1999- गुना विधायक - शिवप्रताप सिंह

2000- लखनादोन विधायक - रणधीर सिंह

2003- भीकनगांव विधायक - लालसिंह पटेल

2003- अलीराजपुर विधायक - वेस्ता पटेल

कहने को तो संघ एक सामाजिक संगठन है, लेकिन इसकी महत्वकांक्षाएं किसी सियासी दल से कम नहीं। संघ भाजपा का मुखौटा लगाकर शासन करना चाहता है। हालत यह है कि भाजपा अपने मुख्यालय 11, अशोक रोड की बजाय नागपुर या इडेवालान से संचालित होती है। संघ की मर्जी के बिना भाजपा में एक पता तक नहीं हिलता। इसका प्रभाव है कि मोदी सरकार में भाजपा के 53 मंत्रियों में से 38 संघ की पृष्ठभूमि से हैं। यह कुल मंत्रियों का 71 प्रतिशत है। दरअसल भाजपा हमेशा संघ के पदचिन्ह पर चलती है।
भाजपा संगठन का गठन हो या फिर सरकार संघ की उसमें महत्वपूर्ण भूमिका रहती है।

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) से जुड़े भाजपा के पांच सांसदों में से एक को 2019 में नरेंद्र मोदी की कैबिनेट में मंत्री के रूप में शामिल किया गया था। लेकिन, संघ की पृष्ठभूमि से न आने वाले सांसदों का अनुपात 1:14 है। सीधे शब्दों में कहें तो आरएसएस की पृष्ठभूमि से आने वाले सांसदों के पास दूसरों की तुलना में तीन गुना बेहतर मंत्री बनने की संभावनाएं थीं, यह एक तथ्य है जिसे आकांक्षी मंत्रियों को टीम मोदी के संभावित कैबिनेट विस्तार के बारे में अटकलों के बीच ध्यान में रखना चाहिए। हालांकि, यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद आरएसएस के पूर्व प्रचारक हैं। सरकार में नंबर दो गृहमंत्री और भाजपा के पूर्व अध्यक्ष अमित शाह आरएसएस की छात्र शाखा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) से भी जुड़े थे। यह सरकार की नीतियों पर संघ के विचारधारा के प्रभाव को भी जाहिर करता है।

मोदी सरकार में भाजपा के 53 मंत्रियों में से 38 संघ की पृष्ठभूमि से हैं। यह कुल मंत्रियों का 71 प्रतिशत है। यह आंकड़ा मोदी के पहले कार्यकाल में 62 प्रतिशत था, जब 2014 में शपथ लेने वाले 66 भाजपा मंत्रियों में से 41 आरएसएस से थे। हालांकि, प्रधानमंत्री ने ऐसे मंत्रियों को कई महत्वपूर्ण विभाग सौंपा है, जिनकी आरएसएस की पृष्ठभूमि नहीं है। इनमें वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण, विदेश मंत्री एस जयशंकर, आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी और ऊर्जा मंत्री आरके सिंह हैं।

भाजपा के एक वरिष्ठ नेता ने इसे ज्यादा महत्व नहीं दिया। भाजपा नेता ने कहा, आरएसएस से संबंध मंत्री बनने की कसौटी नहीं है। पीएम और वरिष्ठ नेतृत्व इस पर निर्णय करते हैं। यह कहना कि किसी को केवल इसलिए पदोन्नत किया जा रहा है क्योंकि उनके आरएसएस से संबंध हैं तो उचित टिप्पणी नहीं है। यह विचार आरएसएस के पदाधिकारी से बार-बार सुनने को मिला। आरएसएस के पदाधिकारी ने कहा, पार्टी के लिए टिकट या पोर्टफोलियो तय करने में आरएसएस की कोई भूमिका नहीं होती है। आरएसएस केवल दो चीजों में विश्वास करता है ऐसे लोग, जो पहले

संघ का पदचिन्ह



भाजपा का 'राम- कार्ड'

ये तो पहले से जाहिर है कि भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव में अपना सारा दांव झाँक रखा है। ऐसा लगता है कि गृहमंत्री अमित शाह ने अपनी छवि को यहां दांव पर लगा दिया है। ऐसे में कोई हैरत नहीं कि चुनाव प्रचार का अंत आते-आते केंद्र सरकार ने राम मंदिर कार्ड भी खेल दिया। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर आगे बढ़ते हुए अयोध्या में राम मंदिर बनाने के लिए ट्रस्ट का गठन कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद संसद में अपनी सरकार के इस फैसले का ऐलान किया। उन्होंने बताया कि राम की जन्मभूमि में भव्य और दिव्य मंदिर बनेगा। इसके लिए उन्होंने अपनी सरकार का विस्तृत प्लान सामने रखा। मोदी सरकार के ट्रस्ट गठन के फैसले के बाद तुरंत उत्तर प्रदेश सरकार के प्रवक्ता का बयान आया। बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के मुताबिक उप सरकार सुन्नी वक्फ बोर्ड को पांच एकड़ जमीन देने का प्रस्ताव पास कर चुकी है। अगर सरकार चुनाव आचार संहिता का ख्याल करती तो यह ऐलान चार दिन टाल सकती थी। लेकिन उसने संसद के पटल का सहारा लेकर मंदिर से जुड़ा संदेश मतदाताओं को भेज दिया है।

से ही हमारे साथ हैं और जिन्हें अभी हमारे साथ आना बाकी है।

आरएसएस के पदाधिकारी ने यह भी बताया कि जहां तक भाजपा नेताओं का सवाल है। सुषमा स्वराज की कोई आरएसएस की पृष्ठभूमि नहीं थी, लेकिन उनके पास महत्वपूर्ण पद थे और यहां तक कि जसवंत सिंह भी नहीं थे। इसलिए ये वर्गीकरण सही नहीं है। इस तरह के विरोध के बावजूद मोदी सरकार पर संघ के निशान स्पष्ट रूप से हैं। लोकसभा के 303 भाजपा सांसदों में से 146 या 48 प्रतिशत सांसदों का आरएसएस से जुड़ाव है। राज्यसभा में 82 सांसदों में से भाजपा के 34 सांसदों का संघ से लिंक है। इस तरह के लिंक सरकार के निर्णय लेने में भी तेजी से दिखाई दे रहे हैं।

उदाहरण के लिए मोदी 2.0 में एक अलग पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन मंत्रालय बनाया गया था, यह सुझाव मुख्य रूप से विश्व हिंदू परिषद (वीएचपी) की तरफ से सामने आया है। इसके अलावा राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) भी संघ से जुड़े संगठनों से मसौदा नीति में कई सुझावों को तबज्जो दिया गया है। पिछले साल लोकसभा चुनावों से पहले



आरएसएस और वीएचपी द्वारा दबाव डाले जाने के बाद भाजपा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से अयोध्या शीर्षक विवाद मामले में तेजी लाने के लिए कहा था। लेखक नीलांजन मुखर्जी ने कहा कि यह सरकार वैचारिक अखंडता रखने वालों को बढ़ावा देना चाहती है। पिछली अटल बिहारी वाजपेयी सरकार की तुलना में जिसे पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं था मोदी ने यह स्पष्ट कर दिया है कि यह ऐसी सरकार है, जिसके पास संघ के एजेंडे को आगे बढ़ाने में कोई हिचक नहीं है।

गौरतलब है कि पीएम, गृहमंत्री और रक्षामंत्री, सभी की आरएसएस पृष्ठभूमि है। तथ्य यह भी है कि आरएसएस की पृष्ठभूमि के और भी मंत्री हैं क्योंकि यह सरकार का संघ परिवार को बेहतर तरीके से एकीकृत करने का तरीका है, ताकि कोई विभाजन न हो सके। सावित्रीबाई फुले पुणे विश्वविद्यालय में राजनीति विज्ञान पढ़ाने वाले सुहास पलशीकर ने कहा कि वाजपेयी सरकार के समय स्थिति बहुत अलग थी, क्योंकि उस समय गठबंधन था। पलशीकर ने कहा, 'मेरा मानना है कि अगर हम वाजपेयी सरकार के साथ इसकी तुलना करते हैं तो शायद स्थिति अलग हो सकती है, क्योंकि वह गठबंधन सरकार थी। जहां तक मोदी सरकार का संबंध है, हम आरएसएस के साथ बहुत विशिष्ट संबंध देखते हैं और उनका एजेंडा सरकार द्वारा लिया जाता है।

उन्होंने यह भी कहा, जहां तक मंत्रियों का संबंध है तो कोई भी देख सकता है कि आरएसएस की पृष्ठभूमि से आने वाले लोग महत्वपूर्ण विभागों को संभाल रहे हैं। यह एक संगठन और एक पार्टी के बीच की अनोखी स्थिति है, जहां यह कहना मुश्किल है कि कौन किससे नियंत्रित कर रहा है। लेकिन उनके एजेंडे निश्चित रूप से एक दूसरे के पूरक हैं और इसलिए उनकी राजनीतिक परियोजनाएं भी हैं।

इशारों में नहीं, अब खुली लड़ाई

चुनाव प्रचार में भड़काऊ भाषण या विभाजनकारी बातें, जो इशारों में होती थी वह अब खुलकर होने लगी हैं। पहले प्रतीकों के सहारे बात कही जाती थी। पाकिस्तान एक प्रतीक था। तभी भारतीय जनता पार्टी ने समूचे विपक्ष को पाकिस्तान का समर्थक घोषित किया हुआ था और तभी अमित शाह ने बिहार के चुनाव प्रचार में कहा था कि भाजपा हारी तो पाकिस्तान में पटाखे फूटेंगे। पाकिस्तान के प्रतीक का ही इस्तेमाल 2017 के गुजरात विधानसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद किया। उन्होंने प्रचार के दौरान कांग्रेस नेताओं और पाकिस्तान के कुछ नेताओं की बैठक का जिक्र किया और दावा किया कि उसमें भाजपा को हराने की योजना पर चर्चा हुई। हालांकि वह पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के साथ पाकिस्तान के नेताओं की औपचारिक मुलाकात थी। ध्यान रहे खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पाकिस्तान जाकर वहां के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ से मिले थे। पर कांग्रेस नेताओं की मुलाकात को भाजपा विरोध और इस तरह से देश का विरोध बताया गया। ऐसे ही एक प्रतीक उतर प्रदेश के चुनाव में चुना गया था। प्रधानमंत्री ने श्मशान बनाम कब्रिस्तान की बात कही। उन्होंने कहा कि सरकार अगर कब्रिस्तान बनाने के लिए पैसा देती है तो श्मशान बनाने के लिए भी देना चाहिए। अब उनका ताजा प्रतीक पहनावा है। उन्होंने पिछले दिनों एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि संशोधित नागरिकता कानून का विरोध करने वालों की पहचान उनके पहनावे से हो जाती है। उनका स्पष्ट तौर पर इशारा मुस्लिम पहनावे की ओर था। ध्यान रहे बहुत पहले संभवतः 2012-13 में नरेंद्र मोदी ने अपने एक सद्भावना कार्यक्रम में एक मौलाना के हाथों नमाजी टोपी पहनने से इनकार कर दिया था। पाकिस्तान के साथ-साथ एक प्रतीक कश्मीर भी था। अनुच्छेद 370 को दशकों से भाजपा ने विपक्षी पार्टियों की मुस्लिमपरस्त नीतियों का प्रतीक बनाया हुआ था। महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड के चुनाव में उस प्रतीक का भी खूब इस्तेमाल किया गया।

मोदी कैबिनेट में सबसे महत्वपूर्ण पैनाल, सुरक्षा पर कैबिनेट समिति (सीसीएस) पर संघ का प्रभुत्व है, लेकिन इसमें दो गैर-आरएसएस सदस्य हैं- वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और विदेश मंत्री एस जयशंकर। समिति की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हैं और संघ परिवार से गृहमंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ भी हैं। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए), दूसरा सबसे महत्वपूर्ण मंत्रिस्तरीय पैनाल, जिसमें आरएसएस की पृष्ठभूमि वाले लोग भी शामिल हैं। समिति में राजनाथ सिंह, शाह, नितिन गडकरी, डीवी सदानंद गौड़ा, नरेंद्र सिंह तोमर, रविशंकर प्रसाद, पीयूष गोयल और धर्मेन्द्र प्रधान, जिन सभी के संबंध आरएसएस से हैं। इसमें सीतारमण और जयशंकर अपवाद हैं। आरएसएस का शिक्षा, संस्कृति और श्रम के मूल हितों में लिंक देखा जा सकता है। इन सभी विभागों को संगठन से नजदीकी संबंध रखने वाले नेताओं द्वारा संभाला जाता है। इन विभागों को रमेश पोखरियाल, प्रह्लाद सिंह पटेल और संतोष गंगवार संभाल रहे हैं।

कहने को तो संघ एक सामाजिक संगठन है, लेकिन इसकी महत्वकांक्षाएं किसी सियासी दल से कम नहीं। संघ भाजपा का मुखौटा लगाकर शासन करना चाहता है। हालत यह है कि भाजपा अपने मुख्यालय 11, अशोक रोड की बजाय नागपुर या झंडेवालान से संचालित होती है। संघ की मर्जी के बिना भाजपा में एक पत्ता तक नहीं हिलता। संघ एक राष्ट्रव्यापी संगठन है और इसकी शाखाएं देशभर में फैली हैं, जिनमें विश्व हिन्दू परिषद, बजरंग दल, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, हिन्दू स्वयंसेवक संघ, स्वदेशी जागरण मंच, भारतीय मजदूर संघ, अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद, इंडियन मेडिकोज ऑर्गेनाइजेशन, भारत विकास परिषद, सेवा भारती, विद्या-भारती, संस्कृत भारती, विज्ञान भारती, भारत विकास परिषद, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग परिषद, विश्व संवाद केंद्र, सहकार भारती, अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत परिषद, राष्ट्रीय सिख संगत, वनवासी कल्याण आश्रम, लघु उद्योग भारती, दीनदयाल शोध संस्थान, विवेकानंद केंद्र, बालगोकुलम, राष्ट्रीय सेविका समिति और दुर्गा वाहिनी आदि शामिल हैं। संघ के आदेश पर इन संगठनों के कार्यकर्ता भाजपा के लिए दिन-रात एक किए रहते हैं। इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता कि संघ ने अपने लक्ष्य की पूर्ति के लिए भाजपा को पैदल सिपाहियों की फौज मुहैया कराई। भाजपा आज देश की सबसे बड़ी पार्टी है और भाजपा की इस कामयाबी में संघ के करीब साढ़े पांच करोड़ स्वयंसेवकों का महत्वपूर्ण योगदान भी शामिल है।

● दिल्ली से रेणु आगाल

6

क्या कांग्रेस का कुछ नहीं हो सकता? ऐसा नहीं है। उम्मीद पर दुनिया कायम है, पर असल मुद्दा तो यह है कि क्या कांग्रेस के लोगों को उम्मीद है? यह तय मानिए कि जैसा चल रहा है वैसा चलता नहीं रह सकता और चलता रहा तो कांग्रेस का कुछ नहीं हो सकता। तो फिर इसकी शुरुआत कैसे हो? जिन्हें भविष्य में भी कांग्रेस में रहकर राजनीति करना है उन्हें पार्टी के अतीत की ओर देखना चाहिए और कुछ घटनाओं की ओर भी। कांग्रेसजन सीताराम केसरी को भूले नहीं होंगे। कांग्रेस के समर्पित नेता-कार्यकर्ता थे। कभी निजी हित को पार्टीहित पर तरजीह नहीं दी, पर उन्हें अध्यक्ष पद से किस तरह हटाया गया? क्या पार्टी के युवा नेताओं में परिवार के किसी नेता को इस तरह पद से हटाने की हिम्मत है? कहने का यह अर्थ नहीं कि वैसा ही करना जरूरी है, लेकिन यदि यह झरादा भी जाहिर कर दिया कि ऐसा कर सकते हैं तो बदलाव आ जाएगा।



पुराने सियासी नुरखों का मोह

कहते हैं कि आपकी हार उस समय नहीं होती जब आप हारते हैं। हार उस समय होती है जब लड़ने का जज्बा खत्म हो जाता है। चुनाव दर चुनाव कांग्रेस पार्टी और उसका

नेतृत्व इसी बात के प्रमाण दे रहा है कि जीतना तो छोड़िए, उसमें लड़ने का ही माद्दा खत्म हो गया है। कांग्रेस अपने विरोधी, भाजपा की एक आंख फोड़ने के लिए अपनी दोनों आंखें फोड़ने को तैयार है। चिकित्सा विज्ञान कहता है कि कैंसर जैसे रोग से भी व्यक्ति लड़ सकता है अगर उसमें जिजीविषा यानी जीने की इच्छा हो।

यदि कांग्रेस को देश का मुख्य विपक्षी दल बने रहना है तो दो चीजों से छुटकारा पाना होगा। पहला, पराजय की मानसिकता से, क्योंकि इस मानसिकता से ग्रस्त व्यक्ति किसी भी बिंदु पर स्वयं सोच-विचार करने में असमर्थ होता है। इसके साथ ही कांग्रेसियों को इस वास्तविकता को स्वीकार करना होगा कि नेहरू-गांधी परिवार उसका अतीत था। यह मान लेने में भी हर्ज नहीं कि अतीत सुनहरा था, पर अब यह परिवार उसका भविष्य नहीं है। यह भूत बेताल के कंधे से उतर जाए, इसी में कांग्रेस की भलाई है।

उत्तर प्रदेश में सपा, बसपा और कांग्रेस के बीच इस सवाल पर रस्साकसी शुरू हो गई है कि 2022 विधानसभा चुनाव में भाजपा का मुकाबला कौन करेगा। चुनाव अभी कम से कम दो साल दूर है, पर खाली बैठे विपक्षी दल

करें भी क्या? योगी सरकार उन्हें कोई मौका भी नहीं दे रही। वैसे भी अखिलेश यादव अपने पारिवारिक झगड़े निपटाने में व्यस्त रहते हैं। चाचा आए दिन

उनके लिए नई-नई मुसीबतें खड़ी करते रहते हैं।

सपा के एक जिला अध्यक्ष ने बताया कि अखिलेश से तो मुलाकात खैर दूर की बात है, अब तो गजेंद्र (अखिलेश के कोई करीबी सहयोगी हैं) से मिलने के लिए भी पर्ची लगानी पड़ती है। चार-पांच जनाधारविहीन नेताओं की चौकड़ी उनके इर्द-गिर्द मंडराती रहती है ताकि कोई पुराना कार्यकर्ता उनके नजदीक न भटकने पाए।

यह चौकड़ी उन्हें आश्वस्त रखती है कि 2022 में उनका दोबारा राजतिलक पक्का है। मायावती का कभी भी धरना-प्रदर्शन या आंदोलन की राजनीति में विश्वास नहीं रहा। उनका सबसे प्रिय कार्य टिकट वितरण है जो लगातार चलता रहता है। कांग्रेस को सड़क पर उतरकर हो-हल्ला करने में बेशक मजा आता है, पर उसके पास कार्यकर्ता नहीं हैं। ऐसे में भाजपा विपक्ष के खाली पड़े हाफ में घुसकर दनादन गोल मार रही है। भाजपा खेमा 2022 चुनाव को लेकर चिंतित नहीं दिखता। पार्टी के रणनीतिकार सिर्फ यह चाहते हैं कि सपा, बसपा और कांग्रेस अलग-अलग ही रहें, कोई गठबंधन न बनने पाए। फिलहाल इसके आसार दिखते भी नहीं।

लोकसभा चुनाव में बसपा से गठबंधन करके बुरे फंसे

पार्टी के युवा नेताओं में जोखिम लेने का साहस नहीं

कांग्रेस के युवा नेताओं में जोखिम लेने का साहस नहीं है। ये सब एक संरक्षित वातावरण में पले बड़े हैं। ज्यादातर को जो मिला है बिना ज्यादा संघर्ष के मिला है। इन्होंने कोई आंदोलन किया नहीं, कोई लड़ाई लड़ी नहीं, कभी जेल गए नहीं और न ही पुलिस की लाठियां खाईं, जो तमाम गैर कांग्रेस दलों के नेताओं और पार्टियों ने किया। ये राजनीति के सुकुमार हैं। इन्हें अभी तक जो मिला वह माता-पिता से मिला या फिर गणेश परिक्रमा से। कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचार, भाई-भतीजावाद, वंशवाद और हकदारी (एनटाइटलमेंट) के कैंसर से ग्रस्त है। कांग्रेस ऐसा संगठन बन गई है जिसमें नेता अपने निजी हित से आगे देखने-सोचने को तैयार ही नहीं हैं। पार्टी की कार्यवाहक अध्यक्ष सोनिया गांधी को देश की कभी चिंता थी, यह कहना कठिन है। अब उनकी चिंता का एक ही विषय है कि संगठन की सत्ता कैसे परिवार के हाथों में रहे।

9

अखिलेश 2022 में ऐसी कोई गलती करने के मूड में नहीं हैं। बसपा भी किसी से चुनाव पूर्व गठबंधन नहीं करेगी। सपा और कांग्रेस भी बसपा से गठबंधन करने के इच्छुक नहीं। रही बात कांग्रेस की, तो उसके पास ना कार्यकर्ता हैं और ना वोट। ये हालात भाजपा के लिए मुंहमांगी मुराद हैं। पिछले महीने लखनऊ में सीएए के विरोध की आड़ में आयातित अराजक भीड़ ने सरकारी और निजी संपत्तियों का दहन किया और पुलिसकर्मियों सहित राहगीरों पर पत्थर चलाए तो इसे नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने कुछ लोगों को गिरफ्तार किया।

प्रियंका गांधी ऐसे कुछ लोगों के घर गईं। इसके कुछ दिन बाद मायावती और अखिलेश भी सीएए के खिलाफ कुछ बोले तो प्रियंका ने इस पर गहरी आपत्ति जताई। उनकी आपत्ति की ध्वनि यह थी कि सपा और बसपा को भाजपा का विरोध करने का अधिकार नहीं है। यूपी में कांग्रेस की जो भी हालत है, पर परिदृश्य में प्रियंका की मौजूदगी भर के लिए ही सही, पार्टी का हौसला तो बढ़ ही जाता है। इसके बावजूद कांग्रेस में फिलहाल वो

ताकत नहीं दिखती जो भाजपा का मुकाबला कर सके। पिछले तीन दशक से गैर कांग्रेस विपक्षी दल ही भाजपा से भिड़ते आ रहे हैं।

सपा और बसपा ने अपने बूते सरकार भी बनाई, पर भाजपा से खफा मतदाताओं ने कांग्रेस की तरफ देखा तक नहीं। वर्ष 2019 चुनाव में राहुल गांधी अमेठी में चुनाव हार गए। इसके बावजूद प्रियंका चाहती हैं कि भाजपा से मुकाबला करने की जिम्मेदारी सिर्फ कांग्रेस के पास रहे। उन्हें यह समझना चाहिए कि यह जनाधार के आधार पर तय होगा, उनकी चाहत से नहीं। फिलहाल सपा और बसपा इस दौड़ में कांग्रेस से बहुत आगे हैं। इन्हें पीछे करने के लिए कांग्रेस को आत्ममुग्धता त्यागकर जनता के बीच आना होगा। समझना होगा कि जब भाजपा के

विकल्प की बात आती है तो मतदाता कांग्रेस के नाम पर विचार क्यों नहीं करते। भाजपा का विकल्प निर्धारण कांग्रेस के अध्यक्ष का मनोनयन नहीं है कि उनका परिवार अदल-बदलकर यह जिम्मेदारी संभालता रहे।

उत्तर प्रदेश का अगला विधानसभा चुनाव, वर्ष 2024 लोकसभा चुनाव की बुनियाद तैयार करेगा, लिहाजा कांग्रेस को उस नजरिए से खुद



की ओवरहॉलिंग करनी चाहिए। मतदाता हर चुनाव में यह संकेत दे रहे हैं कि वे धार्मिक तुष्टीकरण, जातिवाद, परिवारवाद और पाखंड की राजनीति से आजिज आ चुके हैं। नई पीढ़ी व्यक्तिगत और सामूहिक विकास चाहती है। भाजपा इस सच्चाई को अच्छी तरह समझ चुकी है। इसीलिए उसका नेतृत्व गंगा के प्रति आस्था में भी अर्थव्यवस्था के सूत्र पकड़ता है। सपा और बसपा नेतृत्व भी किसी हद तक इस सच्चाई का दामन थामने की कोशिश करते दिखते हैं। इसके परिणामस्वरूप हाल के ज्वलंत मुद्दों पर इन दलों के स्टैंड में संतुलन दिखा, पर कांग्रेस अपने पूर्वजों के 40-50 वर्ष पुराने सियासी नुस्खों का मोह नहीं त्याग पा रही। देश की सबसे पुरानी पार्टी का नया नेतृत्व भी यदि पुरानी लीक पर ही

चलना चाहता है तो फिर क्या किया जा सकता है? सत्ता सरकार की हो या संगठन की, वह जिम्मेदारी और जवाबदेही की मांग करती है। राहुल गांधी पिछले सात साल में इसके लिए तैयार नहीं हो पाए हैं। जवाबदेही की मांग होने लगी तो डेढ़ साल में अध्यक्षी छोड़कर किनारे हो गए, पर सोनिया गांधी उन्हें 'जहर' की और खुराक देने की तैयारी कर रही हैं। इस परिवार से जो भी राजनीति में आता है उसे तुरूप का पत्ता बताया जाता है। पहले राहुल गांधी को बताया गया और लोकसभा चुनाव से पहले प्रियंका गांधी को।

बहुत पुरानी कहावत है 'करत-करत अभ्यास के, जड़मति होत सुजान।' राहुल गांधी इस कहावत को गलत साबित करने में पूरी सरह सफल रहे हैं। 16 साल में उनका राजनीतिक सफर जहां से शुरू हुआ था उससे ज्यादा आगे नहीं बढ़ा है। हर हार के बाद वह एक खीझे हुए व्यक्ति की तरह आचरण करते हैं। पार्टी और पार्टी से बाहर उनका माखौल उड़ाने वालों की तादाद कम होने के बजाय बढ़ती जा रही है। सोशल मीडिया पर तो अब वह एक ट्रोल की तरह व्यवहार करने लगे हैं।

सवाल है कि पार्टी के दूसरे नेता यह सब बर्दाश्त क्यों कर रहे हैं? पार्टी में दो वर्ग और तीन गुट हैं। परिवार के तीनों सदस्यों के अपने-

अपने गुट हैं। तीनों गुटों के सदस्य एक दूसरे पर हावी होने की कोशिश करते हैं। दिसंबर, 2018 में तीन राज्यों में कांग्रेस की सरकार बनी तो तीनों गुट अति सक्रिय हो गए। सोनिया और प्रियंका गुट ने मिलकर राहुल गुट को किनारे लगा दिया। मुख्यमंत्री वे लोग बने जिन्हें राहुल विरोधी गुट चाहता था। नतीजा यह हुआ कि मोदी-शाह युग में तीन राज्यों में कांग्रेस की सरकार बनने का श्रेय पार्टी अध्यक्ष को नहीं मिला। पार्टी अध्यक्ष के रूप में राहुल की नैतिक और सांगठनिक शक्ति उसी समय खत्म हो गई। पूरी पार्टी को पता चल गया कि पार्टी अध्यक्ष के ऊपर भी एक सत्ता केंद्र है और वही बड़े और निर्णायक फैसले करता है।

● इन्द्र कुमार

पार्टी के बुजुर्ग नेता पदों पर कुंडली मारकर बैठे हुए हैं

जहां तक दो वर्गों की बात है तो उसमें से एक है पार्टी के बुजुर्ग नेताओं का। वे पार्टी पदों पर कुंडली मारकर बैठे हुए हैं। इन्हें मालूम है कि इनका समय चला गया है, पर इन्हें अपने बेटे-बेटियों को पार्टी में एडजस्ट करना है। इस मुद्दे पर इनमें बड़ा एका है। जनार्दन द्विवेदी ने बुद्धिमतापूर्ण काम यह किया कि अपने बेटे के स्वतंत्र फैसला लेने में रोज़ा नहीं अटकाया। दूसरा वर्ग युवा नेताओं का है। जिन्हें भविष्य की राजनीति करनी है। सवाल है कि ये लोग इस पारिवारिक प्रहसन को क्यों बर्दाश्त कर रहे हैं? मां जाएगी तो बेटा आएगा। बेटा जाएगा तो मां आएगी। कभी अगर दोनों को हटना पड़े तो बेटे तैयार है। दामाद और दूसरे सदस्य प्रतीक्षा सूची में हैं।

भारत में खासकर महिलाओं और बच्चों को कुपोषण-मुक्त करने और उनमें एनीमिया यानी खून की कमी की समस्या दूर करने के मकसद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आठ मार्च 2018 को महिला दिवस के मौके पर राजस्थान के झुंझुनू में पोषण अभियान की शुरुआत की थी। योजना का मकसद 10 करोड़ से अधिक लोगों को फायदा पहुंचाना था। लेकिन हुआ ये है कि मिजोरम, लक्षद्वीप, बिहार और हिमाचल प्रदेश के अलावा भारत की कोई भी राज्य सरकार बीते तीन वित्तीय वर्षों के दौरान जारी रकम का आधा भी खर्च नहीं कर सकी है। लांसेट जर्नल के ताजा अंक में छपी एक रिपोर्ट में कहा गया है कि बीते दो दशकों के दौरान भारत में कुपोषण और मोटापे के मामले तेजी से बढ़े हैं।

सरकार ने हाल में संसद में पोषण अभियान से संबंधित जो आंकड़े पेश किए थे उनसे साफ है कि मिजोरम, लक्षद्वीप, हिमाचल प्रदेश और बिहार के अलावा दूसरे किसी राज्य में इस मद में आवंटित आधी रकम भी खर्च नहीं हो सकी है। महिला व बाल विकास मंत्रालय के इस प्लैगशिप कार्यक्रम का लक्ष्य वर्ष 2022 तक गर्भवती महिलाओं, माताओं व बच्चों के पोषण की जरूरतों को पूरा करना और बच्चों व महिलाओं में खून की कमी (एनीमिया) को दूर करना भी है। एक दिसंबर, 2017 को केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में मंजूरी के बाद तीन वर्षों के लिए 9,046.17 करोड़ के बजट के साथ इस योजना की शुरुआत हुई थी। इसमें से आधी रकम बजट प्रावधान के जरिए मिलनी थी। उसमें से भी केंद्र और राज्य को क्रमशः 60 और 40 फीसदी रकम देनी थी। पूर्वोत्तर राज्यों के मामले में केंद्र व राज्य सरकारों की भागीदारी क्रमशः 90 और 10 फीसदी है जबकि बिना विधायिका वाले केंद्र शासित प्रदेशों में पूरी रकम केंद्र सरकार के खाते से ही जाएगी।

हर बच्चे का हक है कि उसके जन्म होते ही उसको रजिस्टर किया जाए, नाम और राष्ट्रियता दी जाए, और अपने माता-पिता को जानने और उनकी परवरिश में रहने का मौका दिया जाए। इस योजना के तहत बाकी 50 फीसदी रकम विश्व बैंक या दूसरे विकास बैंकों से मिलनी है। नतीजतन केंद्र सरकार का हिस्सा 2,849.54 करोड़ आता है। लेकिन अब इस अभियान के तहत खर्च होने वाली रकम का आंकड़ा सामने आने के बाद तस्वीर बेहतर नहीं नजर आ रही है। केंद्रीय महिला व बाल कल्याण मंत्री स्मृति ईरानी ने संसद के शीतकालीन अधिवेशन के दौरान इस अभियान का जो आंकड़ा पेश किया उसमें कहा गया था कि केंद्र ने अब तक विभिन्न राज्यों व केंद्र-शासित प्रदेशों को 4,238 करोड़ की रकम जारी की है। लेकिन इस साल 31 अक्टूबर तक



गंभीर नहीं सरकारें

कमियों को कैसे करें दूर

स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉ. पुलकेश कुमार गांगुली कहते हैं, 'केंद्र सरकार की यह योजना तो ठीक है। लेकिन जमीनी स्तर पर इसे लागू करने के लिए कुशल तंत्र और इच्छाशक्ति जरूरी है। कुपोषण की यह समस्या इतनी गंभीर है कि तमाम गैर-सरकारी संगठनों को भी साथ लेकर काम करना जरूरी है।' गांगुली कहते हैं कि इस योजना को लागू करने के साथ ही आम लोगों में जागरूकता अभियान चलाना भी जरूरी है। इस काम में गैर-सरकारी संगठन अहम भूमिका निभा सकते हैं। पोषण अभियान की देख-रेख करने वाले नेशनल काउंसिल ऑन इंडिया न्यूट्रीशन चैलेंजर्स के सदस्य चंद्रकांत पांडेय कहते हैं, 'हम दूसरी खतरनाक बीमारियों की तरह कुपोषण के प्रति उतनी गंभीरता नहीं दिखाते। इसकी वजह यह है कि दूसरी जानलेवा बीमारियों के लक्षण तो सामने आते हैं लेकिन कुपोषण में यह प्रक्रिया बेहद धीमी है और इसके लक्षण शीघ्र नजर नहीं आते। इसलिए लोग इस पर ध्यान नहीं देते।' वह कहते हैं कि पोषण अभियान को कामयाब बनाने के लिए स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करने वाले तमाम हितधारकों को मिल कर काम करना होगा।

इसमें से महज 1,283.89 करोड़ यानी 29.97 फीसदी रकम ही खर्च हो सकी थी। पोषण अभियान के वित्त वर्ष 2017-18 के आखिर में

शुरू होने की वजह से उस साल के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। इस अभियान के तहत जारी रकम को खर्च करने में मिजोरम (65.12 फीसदी) और लक्षद्वीप (61.08 फीसदी) क्रमशः पहले व दूसरे स्थान पर रहे। इस मामले में पंजाब, कर्नाटक, केरल, झारखंड और असम का प्रदर्शन सबसे खराब रहा। वर्ष 2019-20 के दौरान 19 राज्यों को इस मद में रकम जारी की गई। हालांकि इनमें से 12 राज्य पहले दो वित्त वर्ष के दौरान महज एक तिहाई रकम ही खर्च कर सके थे।

भारत में कुपोषण की तस्वीर बेहद भयावह है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च (आईएमआरसी) की एक रिपोर्ट में वर्ष 2017 तक के आंकड़ों के हवाले से कहा गया है कि पांच साल तक के बच्चों में मौत की एक बहुत बड़ी वजह कुपोषण है। अब भी कुपोषण से पांच साल से कम आयु के 68.2 फीसदी बच्चों की मौत हो जाती है। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार और असम के साथ मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, नागालैंड और त्रिपुरा के बच्चे कुपोषण के सबसे ज्यादा शिकार हैं। इस बीच, यूनिसेफ की ओर से जारी एक अन्य रिपोर्ट में कहा गया है कि कुपोषण के मामले में दुनिया के बाकी देशों के मुकाबले भारत में हालात बदतर हैं। कुपोषण की वजह से बच्चों को बचपन तो गुम हो ही रहा है उनका भविष्य भी अनिश्चतता का शिकार है। पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन आफ इंडिया और नेशनल इंस्टीट्यूट आफ न्यूट्रीशन की ओर से कुपोषण की स्थिति पर हाल में जारी एक रिपोर्ट में कहा गया था कि वर्ष 2017 में देश में कम वजन वाले बच्चों के जन्म की दर 21.4 फीसदी रही। इसके अलावा एनीमिया से पीड़ित और कम वजन वाले बच्चों के जन्म की तादाद भी बढ़ी है।

● ऋतेन्द्र माथुर

छत्तीसगढ़ में भाजपा को एक ओर जहां चुनावों में लगातार हार का सामना करना पड़ रहा है, वहीं दूसरी तरफ प्रदेश संगठन नेताओं में आपसी सामंजस्य की कमी और उनके अंतर्विरोध से भी पार्टी काफी कमजोर हो रही है। यह इस बात से साफ हो जाता है कि 2018 में सत्ता से बेदखल होने के बाद पार्टी के दिग्गज नेताओं के बीच कभी एक साथ मिलकर सत्तारूढ़ दल कांग्रेस का सामना करने की सोच नहीं बन पाई है। पार्टी के जानकार मानते हैं कि भाजपा का वर्तमान प्रदेश

नेतृत्व भी इस दिशा में ऐसी कोई मजबूत पहल नहीं कर पाई है जिससे यह कहा जा सके कि 2018 के विधानसभा चुनाव में पिट जाने के बाद पार्टी ने कोई सबक लिया हो। संगठन के कुछ नेताओं का कहना है कि प्रदेश में पार्टी नेतृत्व को सभी गुटों को साथ लेकर चलने का जल्द ही कोई फॉर्मूला बनाना पड़ेगा वरना संगठन में व्यस गुटबाजी के चलते राज्य में होने वाले चुनावों में पार्टी को हमेशा मुंह की खानी पड़ेगी।

हालांकि प्रदेश भाजपा अध्यक्ष विक्रम उसेंडी संगठन के अंदर गुटबाजी को स्वाभाविक मतभेद की संज्ञा देते हैं लेकिन पार्टी के कुछ बड़े नेता यह साफ तौर पर कह रहे हैं कि कई धड़ों में बंटी छत्तीसगढ़ भाजपा के लिए आने वाले दिनों में यह बहुत घातक हो सकता है क्योंकि पार्टी इस दौर से पहली बार गुजर रही है। एक वरिष्ठ भाजपा नेता जो पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह के काफी करीबी माने जाते थे, नाम जाहिर न किए जाने की शर्त पर उन्होंने बताया कि राज्य के गठन को बीस साल बीत चुके हैं लेकिन ऐसा पहली बार हुआ है जब पार्टी संगठन सत्ता की मदद के बिना चल रहा है। इस नेता के अनुसार भाजपा के लिए संगठन में गुटबाजी एक बड़ी चुनौती साबित हो रही है।

प्रदेश के मुख्य विपक्षी दल में गुटबाजी का आलम यह है कि पार्टी के नेता अब कहने लगे हैं कि संगठन के क्षेत्रों को एक साथ लाने में राज्य का नेतृत्व असहाय है। अब इस दिशा में केंद्रीय नेतृत्व को ही कोई बड़ी पहल करनी होगी। भाजपा के एक आदिवासी विधायक कहते हैं 'बाहर से तो कुछ ज्यादा नहीं दिख रहा है लेकिन अंदरूनी तौर पर स्थिति 'अपनी-अपनी डफली अपना-अपना राग' वाली है। प्रदेश के बड़े नेता एक दूसरे के साथ दिखना भी नहीं चाहते। यहाँ तक कि संगठन के राजनीतिक कार्यक्रम भी बड़े नेता अपने धड़ों की आवश्यकता अनुसार तैयार कराकर उसमें भाग लेते हैं।'



भाजपा में गुटबाजी

प्रदेश नेतृत्व असहाय, केंद्रीय मूक दर्शक

पार्टी के अंदर व्याप्त गुटबाजी और एकजुटता की कमी का एक प्रमुख कारण प्रदेश इकाई के प्रति केंद्रीय संगठन का बेपरवाह रवैया भी है। प्रदेश संगठन में कुछ बड़े नेता मानते हैं कि रमन सिंह सरकार के जाने के बाद भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व ने राज्य की सुध लेना ही छोड़ दिया है। ये नेता कहते हैं कि केंद्रीय नेताओं को इस बात से कुछ लेना-देना नहीं है कि छत्तीसगढ़ भाजपा के अंदर क्या चल रहा है। नेता नाम न बताने की शर्त पर बताते हैं कि भाजपा केंद्रीय नेतृत्व की प्राथमिकता वे राज्य हैं जहां चुनावी प्रक्रिया या तो चल रही है या फिर आने वाले एक साल के अंदर चुनाव होना है। संगठन के एक पदाधिकारी कहते हैं, 'यही कारण है कि पार्टी की प्रदेश इकाई का केंद्र में कोई माई-बाप नहीं रह गया है और राज्य का नेतृत्व पिछले एक साल में इतना सक्षम नहीं हो पाया कि गुटबाजी को कम कर पाए। कई बार तो ऐसा लगता है कि भाजपा के अंदर बड़े नेता एक-दूसरे को देखना भी पसंद नहीं कर रहे हैं एकसाथ आना तो दूर की बात है। पार्टी के एक प्रवक्ता का कहना है कि 2018 के अंतिम महीने में सत्ता से बेदखल होने के बाद लोकसभा चुनाव 2019 को छोड़कर, वह भी संभवतः पार्टी हाईकमान के डर से, ऐसा कोई समय नहीं आया जब कार्यकर्ताओं के अंदर एक संदेश दिया जा सके कि भाजपा कांग्रेस का मुकाबला करने में सक्षम है। पिछले एक साल में पार्टी नेतृत्व द्वारा ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं चलाया गया जिसके तहत पार्टी के बड़े नेता भूपेश बघेल सरकार के खिलाफ मिलकर जनता के बीच जाएं।

वहीं दूसरी तरफ प्रदेश भाजपा अध्यक्ष कहते हैं 'पार्टी के अंदर किसी प्रकार की गुटबाजी नहीं है। हां, नेताओं में कभी-कभी मुद्दों के आधार पर वैचारिक मतभेद स्वाभाविक तौर पर होता है लेकिन यह कोई बड़ी बात नहीं है, सभी बड़े नेता जब भी अवसर आता है एकजुट होकर सत्तारूढ़ दल का सामना करते हैं।' उसेंडी आगे कहते हैं, 'नगरीय निकाय चुनाव में भाजपा के हार का मुख्य कारण है राज्य सरकार द्वारा सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग कर चुनाव में की गई गड़बड़ी। यह सर्व विदित है कि भूपेश बघेल सरकार ने नगर निगम मेयर, नगर पालिका अध्यक्ष और नगर पंचायत अध्यक्ष का चुनाव जनता द्वारा सीधे क्यों नहीं कराया। ईवीएम के बजाय मतपत्रों के माध्यम से चुनाव करवाना भी सरकार को शक के दायरे में लाता है।'

भाजपा अध्यक्ष के अनुसार नगरीय निकाय चुनाव के जीत का एजेंडा बघेल सरकार ने पहले से ही तय कर लिया था और सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग पार्षदों की खरीद फरोख्त के लिए किया। प्रदेश भाजपा नेताओं का कहना है कि गुटबाजी के चलते पार्टी आज करीब तीन से चार धड़ों में बंटी हुई है। हालांकि संगठन में मुख्यतः दो ही बड़े धड़े हैं जिनमें एक का नेतृत्व पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह करते हैं और दूसरे का उनके ही सरकार में 15 साल तक कैबिनेट मंत्री रहे बृजमोहन अग्रवाल। इनके अलावा भाजपा की राष्ट्रीय महासचिव सरोज पांडेय, प्रदेश अध्यक्ष विक्रम उसेंडी, पूर्व प्रदेश भाजपा अध्यक्ष और वर्तमान केंद्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष नंदकुमार साय के साथ-साथ पूर्व सांसद और त्रिपुरा गवर्नर रमेश बैस के भी अपने ही धड़े हैं। हालांकि बैस के गवर्नर बनने के बाद उनके समर्थकों ने अब दूसरे गुटों का सहारा लेना शुरू कर दिया है।

● रायपुर से टीपी सिंह

दिल्लि विधानसभा चुनाव में भले ही कांग्रेस का खाता न खुला हो लेकिन उत्तर प्रदेश में जमीनी स्तर पर संगठन को मजबूत करने के लिए कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी और प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू की जोड़ी लगातार मेहनत कर रही है। मिशन 2022 को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस अब उप्र में 'केजरीवाल मॉडल' का सहारा लेगी। कांग्रेस बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी और किसानों के मुद्दों को हथियार बनाने की रणनीति पर काम कर रही है।

दरअसल, दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी की बंपर जीत के पीछे केजरीवाल की 'फ्री स्कीम' का अहम योगदान माना जा रहा है। साथ ही शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में केजरीवाल सरकार द्वारा किए गए काम को भी जनता का समर्थन मिला है। लिहाजा अब कांग्रेस भी केजरीवाल के 'विकास मॉडल' को अपनाने की तैयारी में है। कांग्रेस उप्र में दिल्ली के तर्ज पर ही बिजली और पानी पर अपना विजन साफ करेगी। कांग्रेस शिक्षा और स्वास्थ्य की गारंटी भी देगी। इतना ही नहीं कांग्रेस उप्र में सुरक्षा और किसानों पर भी बात करेगी। कांग्रेस नेता सचिन नायक ने बताया कि प्रियंका गांधी आजमगढ़ पहुंची थीं। उनके दौरों को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं में उत्साह का माहौल रहा। वो लगातार जमीन से जुड़े मुद्दों को लेकर संघर्ष कर रही हैं। आजमगढ़ की जमीन से उन्होंने सीए और एनआरसी के विरोध में आवाज बुलंद की। इतना ही नहीं आम जन मानस से जुड़े मुद्दों को भी लेकर प्रियंका सड़क पर उतर रही हैं। कांग्रेस हमेशा से ही गरीबों, दलितों, किसानों, युवा और महिलाओं के मुद्दों पर संघर्ष करती रही है।

दरअसल, कांग्रेस ने उप्र में फ्रंट फुट पर खेलने का मन बना लिया है। सपा-बसपा गठबंधन के 24 घंटे के अंदर ही पार्टी ने उप्र की सभी 80 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। कांग्रेस के फ्रंट फुट पर खेलने की घोषणा से नए नवेलो सपा-बसपा गठबंधन को खुश होने का ज्यादा मौका नहीं दिया। कांग्रेस का एक धड़ा तो यही मुराद मांग रहा था कि सपा-बसपा से गठबंधन न हो। कई नेताओं ने गठबंधन में शामिल न होने के लिए राहुल गांधी को पत्र भी लिखा था। सपा-बसपा ने कांग्रेस को गठबंधन से बाहर करके कांग्रेस को फ्रंट फुट पर खेलने के लिए मजबूर नहीं किया है। वास्तव में कांग्रेस तो तीन राज्यों में मिली सत्ता के बाद से ही गठबंधन को खास तबज्जो नहीं दे रही थी। पर वो गठबंधन में शामिल न होने की बदनामी से बचना चाहती थी।

कांग्रेस से जुड़े सूत्रों की मानें तो कांग्रेस ने सपा-बसपा गठबंधन की काट ढूँढ ली है। कांग्रेस ने अपने दिग्गज चेहरों के आधार पर चुनाव

केजरीवाल मॉडल का सहारा



लगातार सड़कों पर नजर आ रही हैं प्रियंका

बता दें कि सोनभद्र में आदिवासियों के नरसंहार का मामला रहा हो, या फिर ब्राह्मणों की हत्या के बाद ब्राह्मण यात्रा, उन्नाव और शाहजहांपुर रेप पीड़ितों का मामला, या फिर सीए का विरोध करने वालों पर पुलिसिया कार्रवाई और गन्ना किसानों के भुगतान का मुद्दा सभी पर प्रियंका गांधी ने न सिर्फ मुखर होकर अपनी बात रखी बल्कि सड़कों पर भी वो उतरतीं। प्रियंका गांधी लगातार किसान, कानून व्यवस्था से जुड़े मुद्दों पर उप्र की सड़कों पर संघर्ष करती दिख रही हैं। जिसका असर भी देखने को मिल रहा है। हताश और निराश कांग्रेस कार्यकर्ताओं में प्रियंका गांधी और अजय कुमार लल्लू की जोड़ी ने जान फूंकने का काम किया है। अब आगे की रणनीति दिल्ली के 'केजरीवाल मॉडल' पर तय होगी। कांग्रेस नेताओं के मुताबिक पार्टी अब बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगार, महिलाओं और किसानों से जुड़े मुद्दों को लेकर सड़क पर उतरेगी।

लड़ने की योजना को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है। कांग्रेस अध्यक्ष भी क्षेत्र में प्रभावी चेहरों पर दांव लगाकर उनके दमखम और जमीनी हकीकत को आंकना चाहते हैं। उप्र में कांग्रेस का संगठन मजबूत न होने के कारण भी ऐसी रणनीति बनाई जा रही है। अगर ऐसा होता है तो रायबरेली से सोनिया गांधी और अमेठी से राहुल गांधी के अलावा अन्य कई सीटों से भी कई प्रमुख व खास चेहरे मैदान में होंगे। प्रतापगढ़ क्षेत्र से रत्ना सिंह व इलाहाबाद से प्रमोद तिवारी को मैदान में उतारा जा सकता है। वहीं, लखीमपुर खीरी की धौहरारा सीट से जितिन प्रसाद, बाराबंकी से पीएल पुनिया, गोंडा से बेनी प्रसाद वर्मा, कुशीनगर से आरपीएन सिंह, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सहारनपुर क्षेत्र से इमरान मसूद, फर्रुखाबाद से सलमान खुर्शीद, फैजाबाद से निर्मल खत्री और कानपुर से श्रीप्रकाश जयसवाल पर पार्टी दांव लगा सकती है। प्रदेश अध्यक्ष राज बब्बर को आगरा या फिरोजाबाद से उतारा जा सकता है। इन लोगों का अपने-अपने क्षेत्र में

प्रभाव भी है और ये अच्छे वोट भी बटोर सकते हैं। राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार सीटों के अलावा कांग्रेस को अकेले लड़ने में और भी फायदे नजर आ रहे हैं। प्रदेश की सभी 80 सीटों से चुनाव लड़ने से उसे हर एक लोकसभा सीट पर एक नेता मिल जाएगा, दूसरे पार्टी लोकसभा चुनाव के बहाने अपने कमजोर संगठन को एक बार फिर खड़ा कर सकती है। गठबंधन की स्थिति में उसके पाले में चंद सीटें ही आएंगी और संगठन भी वहीं रह पाएगा, पूरे राज्य में नहीं। कांग्रेस के कई नेता यह दावा करते हैं कि कांग्रेस सीटों के मामले में अकेले लड़कर भी गठबंधन की तुलना में ज्यादा ला सकती है। उधर कांग्रेस के तमाम जमीनी नेता भी यही चाहते हैं और लगातार मांग कर रहे हैं कि पार्टी अकेले चुनाव लड़े। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी 2017 के विधानसभा चुनाव में सपा के साथ गठबंधन के बाद मिली करारी पराजय की वजह से फूंक-फूंक कर कदम रख रही है।

● लखनऊ से मधु आलोक निगम

राजस्थान में अशोक गहलोत सरकार को बने एक साल से ज्यादा का वक्त हो गया है। लेकिन सत्ता और संगठन के बीच लगातार चली आ रही खींचतान के चलते प्रदेश में होने वाली राजनीतिक नियुक्तियां अभी तक अटकी हुई हैं। सत्ता और संगठन के बीच की

इस खींचतान और गुटबाजी को रोकने के लिए पिछले महीने पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी के निर्देश पर समन्वय समिति का गठन भी कर दिया गया है। लेकिन इस समिति की बैठक नहीं होने के चलते बहुप्रतिक्षित राजनीतिक नियुक्तियां अभी तक नहीं हो पाई हैं। प्रदेश के हजारों मायूस कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को इन राजनीतिक नियुक्तियों का लंबे समय से इंतजार है।

प्रदेश में कांग्रेस की गहलोत सरकार के बनते ही राजनीतिक नियुक्तियों की सुगबुगाहट शुरू हो गई थी जो कि आज तक जारी है। असल में इन नियुक्तियों का अब तक भी नहीं होने का प्रमुख कारण सीएम अशोक

गहलोत और डिप्टी सीएम व पीसीसी चीफ सचिन पायलट के बीच चली आ रही लंबी खींचतान है। लेकिन कांग्रेस नेताओं द्वारा इन नियुक्तियों के अब तक नहीं होने के समय-समय पर अलग-अलग कारण बताए गए। प्रदेश में सबसे पहले लोकसभा चुनाव के चलते इन नियुक्तियों को टाल दिया गया। इसके बाद उपचुनाव और फिर निकाय चुनाव तो अब **पंचायत चुनाव** की आचार संहिता का बहाना बनाकर इन नियुक्तियों को टाला जा रहा है।

बता दें, निकाय चुनाव के बाद ऐसा लगने ही लगा था कि अब नियुक्तियां होने वाली हैं लेकिन ठीक इसके बाद कांग्रेस की दिल्ली में **आयोजित हुई देशव्यापी** भारत बचाओ रैली के चलते ये नियुक्तियां नहीं हो पायीं। इस रैली में कांग्रेसी नेताओं को ज्यादा से ज्यादा संख्या में कार्यकर्ताओं को दिल्ली रैली में ले जाने के लिए कहा गया था। ऐसे में राजनीतिक नियुक्तियों में अपना दावा रखने वाले कांग्रेसी नेता इस रैली में अपने नंबर बढ़ाने और अच्छा पद पाने की लालसा लिए अपने साथ सैकड़ों कार्यकर्ताओं को दिल्ली लेकर भी गए। यहां तक कि संगठन की ओर से बकायदा चेक पोस्ट लगाकर कौन कितने लोगों को रैली में लेकर गया

उसकी गिनती भी हुई। लेकिन इस रैली के बाद भी इन नेताओं को निराशा ही हाथ लगी और एक बार फिर उसी खींचतान के चलते दिल्ली रैली के बाद भी नियुक्तियां नहीं हो पाईं।

खैर, प्रदेश में सत्ता और संगठन के बीच की इस अदावत को खत्म करने और बेहतर तालमेल

स्थापित करने के उद्देश्य से पिछले महीने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के निर्देश पर एक समन्वय समिति का गठन किया गया। प्रदेश कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे को समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया और सीएम अशोक गहलोत, डिप्टी सीएम व पीसीसी चीफ सचिन

पायलट, मंत्री भंवरलाल मेघवाल, हरीश चौधरी, विधायक दीपेंद्र सिंह शेखावत, हेमाराम चौधरी और महेंद्रजीत सिंह मालवीय को समिति का सदस्य नियुक्त किया गया। समिति के गठन के बाद एक बार फिर से आस दिखी कि अब शायद जल्द ही राजनीतिक नियुक्तियों की घोषणा प्रदेश में होगी। लेकिन इस गठित समन्वय समिति की एक बैठक भी आज तक नहीं हुई है।

यहां मजेदार बात यह भी है कि इस समिति का जो ढांचा है वो व्यवस्था तो प्रदेश कांग्रेस में पहले से भी थी, यानी सीएम गहलोत व उनके समर्थक नेता और पीसीसी चीफ सचिन

पायलट व उनके समर्थक नेता जो कि समिति में शामिल हैं, इनके बीच किसी भी मुद्दे पर चलने वाली **खींचतान** का समाधान पहले भी प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे यानी इस समन्वय समिति के अध्यक्ष ही करते आए हैं तो फिर इस समन्वय समिति में नई बात या नया चेहरा कौनसा है, यह बात थोड़ी समझ से परे है, लेकिन पार्टी ने तय किया है तो कुछ तो जरूर सोचा ही होगा।

खैर, समन्वय समिति के गठन के कुछ समय बाद ही दिल्ली में विधानसभा चुनाव के चलते पार्टी के सभी शीर्ष नेता दिल्ली चुनाव प्रचार में व्यस्त हो गए थे। ऐसे में पार्टी नेताओं की दिल्ली में व्यस्तता के कारण समन्वय समिति की बैठक नहीं हो पाई और राजनीतिक नियुक्तियां भी। वहीं अपने गुरु 'प्रदीप' की स्मृति में आयोजित सरकार के कार्यक्रम में शिरकत करने जयपुर आए प्रदेश कांग्रेस प्रभारी और समन्वय समिति के अध्यक्ष अविनाश पांडे ने कहा कि अभी तक सभी नेता दिल्ली चुनाव में व्यस्त थे, जिसके चलते समन्वय समिति की बैठक नहीं हो पाई अब बहुत जल्द समिति की बैठक भी होगी और उसके बाद राजनीतिक नियुक्तियां भी।

● जयपुर से आर.के. बिन्नानी



इंतहा हो गई इंतजार की

आखिर कब खुलेगी लॉटरी

बता दें, करीब 52 बोर्ड, आयोगों, समितियों और अकादमियों में ये नियुक्तियां होंगी जिनमें अध्यक्ष सहित विभिन्न पदों पर हजारों कांग्रेसी नेताओं और कार्यकर्ताओं को पद मिलने का इंतजार है। अब देखने वाली बात यह होगी कि सत्ता और संगठन में इन नियुक्तियों को लेकर किस तरह का आपसी सामंजस्य बैठेगा और कब तक ये नियुक्तियां हो पाती हैं। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनने से पहले और उसके बाद से लगातार जिस तरह से विभिन्न मुद्दों पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और डिप्टी सीएम सचिन पायलट के बीच की अदावत सामने आती रही है उसको देखकर कभी लगा नहीं कि यह कभी बिना किसी बड़े निर्णय के रुक जाएगी। जानकारों के अनुसार दोनों के बीच की खींचतान अबल दर्ज तक पहुंच चुकी है। अधिकांश मामलों में दोनों की राय एक-दूसरे से बिलकुल जुदा ही रहती है। न तीखी तकरार, न व्यंग्यों की बौछार, ना ही कमियां निकालने का दौर, और ना ही अभी एक-दूसरे को नीचा दिखाने का समय है। थोड़े समय के लिए ही सही लेकिन वक्त बदल गया है और बदले वक्त में राजस्थान की राजनीति की फिजा भी बदली-बदली सी नजर आ रही है। चंद दिनों पहले तक हर तरफ एक ही गूंज थी, राजस्थान सरकार के दो दिग्गजों के बीच वर्चस्व की लड़ाई चल रही है। दोनों की ओर से समय-समय पर अलग-अलग मुद्दों पर लगातार शब्दबाण छोड़े जा रहे थे। इस कारण राजनीतिक नियुक्तियां भी अटकी हुई हैं।

महाराष्ट्र में शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस की सरकार के चलते रहने की एकमात्र गारंटी शरद पवार हैं। पर सवाल है कि तीनों पार्टियों के नेता जितने तनाव पैदा कर रहे हैं उससे शरद पवार भी कैसे निपटेंगे? इसमें उनकी पार्टी भी शामिल है। आखिर उन्हीं की पार्टी के एक नेता ने इमरजेंसी को याद किया और कहा कि इंदिरा गांधी ने लोकतंत्र का गला घोटने का प्रयास किया था। यह बयान देने वाले नेता जितेंद्र अन्हाड पार्टी प्रमुख शरद पवार के बहुत खास हैं और उनके बयान देने से दो दिन पहले ही पवार ने उनकी जमकर तारीफ की थी। जब कांग्रेस ने उनके बयान पर आपत्ति जताई तो पार्टी से इससे पल्ला झाड़ा और उन्होंने जैसे-तैसे पिंड छुड़ाया।

अब शिवसेना प्रमुख और मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने सीएए पर अपना रुख बदलना शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा है कि इस कानून को गलत समझा गया है। पिछले हफ्ते उन्होंने एक कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि दोनों ने विकास के बहुत काम किए हैं। मुख्यमंत्री मार्च में अपनी सरकार के 100 दिन पूरे होने पर अयोध्या जाने वाले हैं और वे चाहते हैं कि कांग्रेस और एनसीपी के नेता भी उनके साथ जाएं।

इस बीच पिछले दिनों दिल्ली में विवादित बयान देने वाले जेएनयू छात्र शरजिल इमाम को लेकर शिवसेना के मुखपत्र सामना ने बहुत तीखी टिप्पणी की। असम के लोगों को भारत से अलग होने की सलाह देने वाले एक कथित वीडियो सामने आने के बाद शरजिल को गिरफ्तार किया गया है। सामना ने लिखा है कि उसका हाथ काट देना चाहिए। जाहिर है शिवसेना अपने को ज्यादा हिन्दुवादी दिखाने की होड़ में शामिल है। उसे महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के नेता राज ठाकरे की आक्रामक राजनीति से खतरा पैदा हो गया है। इस बीच महाराष्ट्र भाजपा के नेताओं ने यह कहना शुरू कर दिया है कि शिवसेना और भाजपा मिलकर काम करने को तैयार हैं।

इन सबके बीच कांग्रेस की स्थिति सबसे अजीबोगरीब है। उसे सरकार में रहना है और भाजपा को किसी तरह से सरकार में आने से रोकना है तो दूसरी ओर अपनी सेकुलर साख भी

बचाए रखनी है। तभी कांग्रेस के नेता इस बात के लिए दबाव बना रहे हैं कि राज्य सरकार मुस्लिम आरक्षण लागू करे। शिवसेना के लिए ऐसा करना संभव ही नहीं है। वह किसी तरह से

इस मामले में आगे नहीं बढ़ेगी। इस वजह से दोनों के बीच टकराव बढ़ सकता है। सावरकर का विवाद भी शिवसेना और कांग्रेस नेताओं के बीच चलता रहेगा। कांग्रेस नेता सावरकर पर हमले करेंगे और शिवसेना उनको भारत रत्न देने की मांग करती रहेगी।

त्रिशंकु सरकार में पोर्टफोलियो के बंटवारे में पहले तो कांग्रेस के हिस्से में कोई खास या महत्वपूर्ण मंत्रालय नहीं आया और खुद पार्टी के कई बड़े नेताओं के बीच आपसी मतभेद और मनमुटाव के चलते भी कांग्रेस के मंत्री जनता के पक्ष में कोई बड़ा फैसला नहीं ले पाए और ना ही कोई ऐलान अब तक कांग्रेस कर पाई। यही वजह है कि महाराष्ट्र में कांग्रेस के नेता सरकार में होने के बावजूद अब इनसिक्वोरिटी महसूस करने लगे हैं। उन्हें इस बात का डर सताने लगा है कि कहीं उनका वोटबैंक नाराज होकर उनके हाथ से खिसक ना जाए।

कांग्रेस के भीतर इनसिक्वोरिटी की यह भावना तब और भी जाहिर हो गई जब कांग्रेस के पूर्व मुंबई अध्यक्ष मिलिंद देवड़ा ने सोनिया गांधी के नाम एक चिट्ठी लिखी। मिलिंद देवड़ा ने इस चिट्ठी में साफ लिखा कि शिवसेना और एनसीपी ने अपने कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के जरिए किए वादों पर काम करना शुरू कर दिया है जबकि कांग्रेस ने जनता से किए अपने वादों को लेकर अब तक कोई पहल नहीं की है। देवड़ा ने पार्टी हाईकमान को सचेत भी किया यह कहते हुए कि वक्त रहते कांग्रेस अगर एक्शन में नहीं आई तो पार्टी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। जिस तरह से महाराष्ट्र में तीन अलग-अलग पार्टियों ने एक साथ आकर सरकार बनाई है, उसी तर्ज पर अब राज्य के सभी चुनाव शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी ने साथ लड़ने का मन बनाया है। इसकी शुरुआत नवी मुंबई महानगरपालिका के चुनाव से हो रही है जो कि इसी साल अप्रैल में होने वाले हैं। महाराष्ट्र सरकार बनाने के लिए तीनों ही पार्टियों ने चुनाव के बाद में गठबंधन किया, लेकिन अब चुनाव पूर्व गठबंधन किए जाएंगे। हाल ही में नवी मुंबई में एक कार्यक्रम के दौरान इस बात का ऐलान किया गया। तीनों पार्टियों के लिए अब सबसे पहली चुनौती नवी मुंबई महानगरपालिका का चुनाव जीतना है।

● बिन्दु माथुर

सरकार ऐसे कैसे चलेगी?



कांग्रेस के वादों का क्या होगा?

कांग्रेस ने त्रिशंकु सरकार के कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में जनता से वादा किया था कि वे झुग्गी झोपड़ियों में रहने वालों को कम से कम 500 रक्वायर फीट का मकान दिलाने के लिए काम करेगी। इस चुनावी वादे की घोषणा को कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने लोकसभा और विधानसभा चुनाव के दौरान अपने प्रचार में भी जमकर इस्तेमाल किया था। लेकिन महाराष्ट्र में सरकार बनाने के 2 महीने बीत जाने के बावजूद कांग्रेस के नेता जनता को किए वादों को पूरा करने के बजाय आपसी झगड़े में उलझे पड़े दिखाई दे रहे हैं। जानकारों का भी मानना है कि शिवसेना और एनसीपी दोनों ही पार्टी कांग्रेस के वोट बैंक में संघ लगा चुकी है। ऐसे में कांग्रेस अगर अपनी रणनीति में सुधार नहीं लाई तो ना सिर्फ आने वाले वीएम्सी चुनाव में कांग्रेस को उसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है बल्कि महाराष्ट्र में उसके अस्तित्व पर भी खतरा बढ़ सकता है। और शायद इस बात का अंदाजा खुद कांग्रेस के कई नेताओं को भी है। यही वजह है कि सरकार में अपने आप को इनसिक्वोर महसूस कर रहे यह नेता अब अपनी पार्टी के हाईकमान से उम्मीद लगाए बैठे हैं।

यह चुनावी साल है और नीतीश कुमार सुरक्षित खेल रहे हैं, उन्होंने खुद को विवादास्पद नागरिकता संशोधन कानून यानी सीएए से जोड़ने और भाजपा के साथ अपने गठबंधन को तोड़ने के किसी भी प्रयास को नाकाम कर दिया है। पार्टी के वरिष्ठ नेता पवन कुमार वर्मा और प्रशांत किशोर खुलकर नए कानून की आलोचना करते रहे और अब उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने अपने बिहार दौरे में ऐलान किया था कि नीतीश राज्य में गठबंधन की अगुवाई करेंगे और इसी वजह से शायद नीतीश के रुख में बदलाव आया। नीतीश ने इन दोनों नेताओं के लिए 'आप कहीं भी जाने के लिए स्वतंत्र हैं' कहकर इस बाबत स्पष्ट संकेत दे दिया था।

16 जनवरी को वैशाली जिले में अमित शाह ने कहा कि वे यहां सभी अफवाहों को खत्म करने के लिए आए हैं। उन्होंने कहा, 'एनडीए बिहार विधानसभा का अगला चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ेगा। भाजपा-जद(यू) का गठबंधन अटूट है।' शाह का बयान इस मामले में अंतिम लगता है, यह मुख्यमंत्री पद के भाजपा के अधीर राज्य नेताओं को चुप कराने के लिए भी पर्याप्त संकेत है। शाह के बिहार दौरे से ठीक तीन दिन पहले नीतीश ने शाह की प्रिय परियोजना राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर (एनआरसी) को खारिज किया था और सीएए सहित सभी विषयों पर चर्चा करने की इच्छा जताई थी। भाजपा के कई नेता इससे नाराज हुए और उन्हें शाह से कड़ी प्रतिक्रिया की उम्मीद थी। आमतौर पर आक्रामक शाह ने इसे नजरअंदाज किया, जिसे बिहार में जिताऊ गठबंधन को बिगाड़ने की उनकी अनिच्छा के रूप में देखा जा रहा है।

हाल ही में महाराष्ट्र और झारखंड चुनाव में हाथ जला चुका भाजपा नेतृत्व स्पष्ट तौर पर बिहार में एक और संकट खड़ा नहीं करना चाहता। बिहार से 40 लोकसभा सांसद आते हैं। चुनाव में महज 10 महीने बचे हैं और जद(यू) के एक नेता नाम न छापने की शर्त पर कहते हैं, 'भाजपा को यह समझना होगा कि 68 साल के नीतीश बतौर मुख्यमंत्री आखिरी कार्यकाल चाह रहे हों। प्रदेश भाजपा नेताओं को धैर्य रखना चाहिए और उनका साथ देना चाहिए।'

2019 के लोकसभा चुनाव परिणामों की गहन जांच से पता चलता है कि 17 सीटों और कुल चार करोड़ मतों में से 96 लाख मतों के बावजूद भाजपा राज्य में सबसे ज्यादा बढ़त हासिल करने वाली पार्टी नहीं थी। लगभग 90 लाख मत नीतीश की पार्टी जद(यू) को मिले। भाजपा को 2015 के विधानसभा चुनाव में 93 लाख मत मिले थे, यह चुनाव वह राजद-जद(यू) गठबंधन से हार गई थी। भाजपा के लोकसभा वोट के आंकड़े में 3,10,000 वोटों की बढ़त दर्ज की गई।

ताकतवर सहयोगी



बिहार में उभर रही है नई लीडरशिप

दिल्ली के बाद राजनीति का केंद्र बिहार शिफ्ट हो जाएगा। सबका फोकस बिहार पर बनेगा। इस बार बिहार में नया नेतृत्व उभरने की गुंजाइश देखी जा रही है। ध्यान रहे बिहार में पिछले 30 साल से राजनीति जयप्रकाश नारायण के आंदोलन से जुड़े रहे नेताओं के ईर्द-गिर्द घूम रही है। तीन शीर्ष पार्टियों के नेता जेपी आंदोलन से निकले हैं। राजद के लालू प्रसाद, जदयू के नीतीश कुमार और भाजपा के सुशील कुमार मोदी तीनों जेपी आंदोलन के नेता हैं। राजद में तो आधिकारिक रूप से नेतृत्व का हस्तांतरण हो गया है और लालू प्रसाद के बेटे तेजस्वी पार्टी की राजनीति संभाल रहे हैं। लालू के साथ रहे तमाम पुराने नेताओं ने तेजस्वी यादव को नेता मान लिया है। जनता दल (यू) में फिलहाल नीतीश कुमार का विकल्प नहीं है। पर भाजपा में नया नेतृत्व आगे किया जा रहा है। अमित शाह और भूपेंद्र यादव ने नित्यानंद राय को बिहार भाजपा का चेहरा बनाया है। उनके बाद मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह भी नेतृत्व की दावेदारी में हैं। इनके अलावा बिहार की राजनीति में इस बार दो लोगों पर खास नजर रहेगी। जदयू से निकाले गए प्रशांत किशोर और सीपीआई के कन्हैया कुमार। कन्हैया इस समय बिहार में दौरा कर रहे हैं और हर शहर में उनकी रैलियों में भारी भीड़ जुट रही है। उनके दम पर सीपीआई अपने पुराने दिन हासिल करने की उम्मीद कर रही है।

जद(यू) को 89 लाख वोट मिले, जो 2015 के आंकड़ों से 38.7 फीसद की चकित करने वाली छलांग है।

2014 के लोकसभा चुनाव के बाद से बिहार में 61 लाख नए मतदाता जुड़े हैं और जद(यू) नेतृत्व का मानना है कि हर दूसरा नया मतदाता नीतीश के लिए वोट करता है। यही एक कारण है कि पार्टी नया गठबंधन नहीं करना चाहती। जद(यू) के एक नेता का कहना है, 'हम दागी गठबंधन (चारा घोटाले में राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव के संदर्भ में) का हिस्सा नहीं बनना चाहते। युवा मतदाता इसे बहुत विनम्रता से नहीं स्वीकार कर सकते।'

जद(यू) नेताओं का एक वर्ग हालांकि सीटों के बंटवारे को लेकर आशंकित है। 2010 के विधानसभा चुनाव में नीतीश भाजपा से गठबंधन

करके चुनाव लड़ रहे थे। जद(यू) ने 141 सीटों पर अपने प्रत्याशी खड़े किए थे जबकि भगवा पार्टी ने 102 सीटों पर। लेकिन पिछले वर्ष के लोकसभा चुनाव में दोनों दलों ने बराबर सीटों पर उम्मीदवार खड़े किए थे।

सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि नतीजों में भाजपा ने बिहार में अपनी सभी 17 सीटों पर जीत दर्ज की, जिसने उसे स्पष्ट रूप से जद(यू) के बराबर पहुंचा दिया। निश्चित रूप से सीट बंटवारे पर बातचीत भाजपा की ओर से 2010 की तुलना में ज्यादा सीटों की मांग के साथ शुरू होगी। लेकिन जैसा कि जद(यू) के नेता कहते हैं, 'विधानसभा का चुनाव कुल मिलाकर मुख्यमंत्री का चुनाव है। यहां पार्टी को यकीन है कि तुरुप का पत्ता उसके पास रहेगा।'

● विनोद बक्सरी

अबकी बार फिर ट्रंप सरकार

अमेरिका के निवासी अपने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिकी नरेंद्र मोदी कहते हैं। अमेरिकी नागरिकों के अनुसार दोनों ही नेताओं की सबसे बड़ी खासियत यह है कि एक बार उनके मन में जो आ जाता है उसे पूरा करके ही वे दम लेते हैं। उन्हें किसी की जरा भी परवाह नहीं होती है। उनकी एक बड़ी खासियत यह भी रही कि मोदी ने अपनी अमेरिकी यात्रा के दौरान भारतीय बहुल इलाके में की गई अपनी रैली में 'अबकी बारी ट्रंप सरकार' के नारे भी लगवाए थे। अब ट्रंप अगले महीने भारत आ रहे हैं। हाल ही में जिस तरह से ट्रंप को उनके चुनाव के पहले अमेरिकी संसद (सीनेट) ने महाभियोग के आरोप से मुक्त कर दिया है वह उनकी ताकत को दर्शाता है।

अमेरिकी राष्ट्रपति दुनिया का सबसे ताकतवर व प्रभावशाली व्यक्ति माना जाता है। पिछले साल 24 सितंबर 2019 को सदन की अध्यक्ष नैसी पोलेसी ने डोनाल्ड ट्रंप पर अपनी हैसियत का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया था। इस आरोप की जांच के लिए महाभियोग की जांच शुरू करने के आदेश दिए थे। उन पर लगाए गए आरोपों में यूक्रेन के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेन्स्की पर दबाव डालकर जो बाइडेन व उनके बेटे हंटर के खिलाफ आरोपों के मामले को अपने देश में जांच शुरू करने को कहा था। उन्होंने उनसे कहा था कि वे 2016 के राष्ट्रपति चुनाव में हस्तक्षेप करने के मामले की जांच रूस में किए जाने की जगह अपने देश में करें। अमेरिकी गुप्तचर विभाग का मानना था कि रूस इस बात के जरिए दबाव बना रहा है कि यूक्रेन ने 2016 में राष्ट्रपति चुनाव में यह जांच अमेरिका के लिए सही नहीं थी। अमेरिका इंटेलीजेंस समुदाय व गुप्त रिपोर्ट का मानना था कि रूस ने 2016 में राष्ट्रपति चुनाव में ट्रंप को फायदा पहुंचाया था।

अमेरिका की प्रतिनिधि सभा को वहां की डेमोक्रेटिक पार्टी का बहुमत है जो कि विपक्ष में है जबकि डोनाल्ड ट्रंप रिपब्लिकन पार्टी से हैं। वे महाभियोग का सामना करने वाले तीसरे अमेरिकी राष्ट्रपति हैं। उन पर यूक्रेन की मदद से अपना चुनाव जीतने के लिए विपक्षी नेता के खिलाफ दूसरे देश से जांच करवाने का आरोप था। विपक्ष ने कहा कि ऐसा करके अमेरिका के राष्ट्रपति ने अमेरिकी संविधान व राष्ट्रीय सुरक्षा व चुनावों की वैधता पर ही सवाल खड़े कर दिए थे। ट्रंप चाहते थे कि यूक्रेन अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बाइडेन जो कि 2020 के राष्ट्रपति चुनाव में उनके खिलाफ लड़ना चाहते थे उनके खिलाफ अपने यहां भ्रष्टाचार के मामले की जांच शुरू करें। ट्रंप ने आरोप लगाया था कि उपराष्ट्रपति रहते हुए जोर्ड बिडेन ने अपने बेटे



जारी रहेगी जांच

सीनेट में महाभियोग खारिज हो जाने के बावजूद डेमोक्रेटिक पार्टी की देखरेख में चल रही जांच समाप्त नहीं होगी। वहीं दोबारा उन्हें जिताने के लिए की जा रही रैलियों में उनके कट्टर दक्षिणपंथी समर्थकों ने जी जान लगा दी है। इस जीत से खुश ट्रंप अब कह रहे हैं कि उनके नेतृत्व में नौकरियों का सृजन हो रहा है। लोगों की आय बढ़ रही है। गरीबी कम हुई है। हमारा देश बहुत सम्मानित तरीके से बढ़ रहा है। अमेरिका की किस्मत बुलंद है व भविष्य उज्ज्वल है। उनके कार्यकाल में देश की आज़िबिका बेहतर हुई है। अमेरिका का सपना लौट आया है। खराब अर्थव्यवस्था का समय लद चुका है। अमेरिका तेज रफतार से आगे बढ़ रहा है। गैर कानूनी तरीके से अमेरिका आने वाले हर व्यक्ति को तुरंत बाहर किया जाएगा। यह सब सुनकर लगा कि ट्रंप नहीं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोल रहे हैं जो कि खुद भी ट्रंप की तरह दक्षिणपंथी ही है। वैसे डोनाल्ड ट्रंप को मोदी की तरह इस बार अपने चुनाव में यह नारा लगाना चाहिए कि 'अबकी बार ट्रंप सरकार'।

हंटर बिडेन की कंपनी के खिलाफ यूक्रेन में की जा रही भ्रष्टाचार की जांच कर रहे एक अधिकारी को हटाने के लिए कहा था। बिडेन ने इसका खंडन किया था जबकि ट्रंप ने अपने आरोप साबित करने के लिए कोई प्रमाण नहीं दिए थे। डेमोक्रेट ने दावा किया कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने यूक्रेन पर दबाव डालने के लिए उसे सुरक्षा के लिए दी जाने वाली 400 अरब डॉलर की मदद रोक दी थी। यूक्रेन द्वारा जांच में देरी किए जाने की खबर आने के बाद ट्रंप ने उसे यह राशि दी। डेमोक्रेट का यह भी आरोप था कि ट्रंप ने अमेरिकी संसद के कामकाज में हस्तक्षेप डालने के लिए अपने प्रशासन के सदस्यों को उसका सहयोग करने से रोका था जो कि वहां के संविधान के खिलाफ था। इसकी पुष्टि करने के लिए अनेक अफसरों ने कहा था कि ट्रंप ने उनसे उस अधिकारी से सहयोग करने को कहा था जो कि उनके पक्ष में जांच कर रहा था। ट्रंप को सबसे बड़ा झटका तब लगा जबकि यूरोपीय यूनियन के अमेरिकी राजदूत गार्डन सॉडलैंड ने खुलासा किया कि ट्रंप ने उन पर यूक्रेन पर दबाव डालने को कहा था व इस काम में प्रशासन के आला अफसर शामिल थे। यूक्रेन समझ गया था कि सुरक्षा के लिए पैसा हासिल करने के बदले उन्हें जांच के आदेश देने पड़ेंगे। मगर अमेरिकी सीनेट (संसद) ने डोनाल्ड ट्रंप को महाभियोग के सभी आरोपों से बरी कर दिया हालांकि पहले से ही यह माना जा रहा था कि ट्रंप बरी हो जाएंगे।

उधर, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आगामी 24-25 फरवरी को भारत दौरे पर आने वाले हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति के इस दौरे पर दोनों देशों के बीच व्यापार को लेकर कुछ समझौते हो सकते हैं। हालांकि इसी हफ्ते 13 फरवरी को यूएस के व्यापार प्रतिनिधि रॉबर्ट लेथाइजर भारत आने वाले थे, लेकिन उन्होंने अपना यह दौरा रद्द कर दिया था। दौरा रद्द होने के लिए अमेरिका की तरफ से कोई वजह नहीं बताई गई थी। रॉबर्ट लेथाइजर के दौरा रद्द करने से भारत को अमेरिका के साथ ट्रेड डील करने की उम्मीदों को बड़ा झटका लगा है। हालांकि ऐसी खबरें हैं कि रॉबर्ट लेथाइजर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के भारत आने वाले प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा हो सकते हैं। अब देखना यह है कि भारत और अमेरिका में होने वाले समझौते का असर भारत की अर्थव्यवस्था पर कितना पड़ता है। गौरतलब है कि भारत की अर्थव्यवस्था इस समय कमजोर स्थिति में है।

● अक्स ब्यूरो

महिला सुरक्षा का संकट

देश में बलात्कार की बढ़ती घटनाओं ने महिला सुरक्षा के सवाल की उपेक्षा को एक बार फिर उग्र आंदोलन का रूप दे दिया है। ऐसा लगता है कि अब इस तरह की घटनाएं हमें विचलित नहीं करतीं, अपितु ये सामान्य-सी घटना लगने लगती हैं। कभी चार महीने की बच्ची के साथ तो कभी सत्तर साल की बुजुर्ग के साथ इन घटनाओं की पुनरावृत्ति हमारे सभ्य समाज के मुंह पर एक जोरदार तमाचा है।

हैदराबाद में एक महिला चिकित्सक के साथ सामूहिक बलात्कार और हत्या की घटना ने देश को हिला कर रख दिया। पुलिस ने समय पर शिकायत दर्ज नहीं की, महिला को न्याय दिलाने के लिए लोग सोशल मीडिया पर अभियान छिड़ा, नेताओं-मंत्रियों ने कहा कि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए कठोर कदम उठाए जाएंगे, हमारी संवेदनाएं पीड़िता के परिवार के साथ हैं, नागरिक समाज देश के विभिन्न हिस्सों में कैंडल मार्च करता है, और फिर इस मामले के आरोपियों को पुलिस मुठभेड़ में ढेर कर दिया गया। लेकिन सवाल है इससे क्या पीड़िता को न्याय मिला? क्या ऐसा करने से बलात्कार की घटनाओं को रोका जा सकता है?

किसी भी देश में पुलिस मुठभेड़ को वैधता प्रदान नहीं की जा सकती, क्योंकि अगर जनता की चेतना में मुठभेड़ की वैधता को स्थापित होने का मौका मिल रहा है तो यह समग्र देश के लिए और लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। कहा जाता है कि न्याय की देवी की आंखों पर काली पट्टी इसलिए बंधी है, ताकि सबके साथ समान न्याय हो सके, किसी के भी साथ लैंगिक, जाति, वर्ग, भाषा, राजनीति या क्षेत्र के आधार पर भेदभाव न हो सके। फिर यह भेदभाव क्यों? न्याय की देवी की आंखों पर काली पट्टी संभवतः शक्तिशाली लोगों ने ही बांधी है, ताकि न्याय की समूची प्रक्रिया अन्याय को देख न सके। निर्भया, कठुआ और उन्नाव कांड क्या कम दर्दनाक थे कि संभल (उत्तर प्रदेश) में एक किशोरी को उसके पड़ोसी ने बलात्कार के बाद जिंदा जला दिया। राजधानी दिल्ली में चाय की दुकान चलाने वाली पचपन साल की महिला से बलात्कार के बाद उसकी हत्या कर दी गई, रांची में कानून



मानसिकता बदलने की जरूरत

आश्चर्य तो तब होता है जब पुरुष समाज यह कहता है कि लड़कियों को रात को घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए या उन्हें आधुनिक शैली के कपड़े नहीं पहनने चाहिए, उन्हें मोबाइल नहीं देना चाहिए। उनसे पूछिए जरा कि घर के अंदर भी लड़कियां कहां सुरक्षित हैं? न पिता से, न भाई से, न दादा से, न मामा से, किसी के साथ भी तो सुरक्षित नहीं है। क्या परंपरागत परिधान पहनने वाली महिलाओं या लड़कियों का बलात्कार नहीं हुआ, क्या मोबाइल का प्रयोग नहीं करने वाली लड़कियों के साथ हिंसा नहीं होती? इस तरह के कथन या विचार पुरुष समाज की विकृत मानसिकता के द्योतक हैं। संविधान में पुरुष और महिला को समानता का दर्जा दिया गया है, समान अधिकार दिए गए हैं, यहां तक कि यह भी लिखा है कि कानून की नजर में सब समान हैं। इसलिए यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि आखिर क्यों बलात्कार के मामले, घरेलू हिंसा के मामले सालों लंबित रहते हैं और आरोपी खुले घूमते रहते हैं। यही वह वजह है कि अपराधियों में कानून का कोई भय नहीं होता क्योंकि वे जानते हैं कि कानून केवल कागजी हैं। ऐसे अनेक उदाहरण भरे पड़े हैं जहां तेजाब फेंकने, देहज हत्या या बलात्कार के मामले में पीड़िता के परिवारजनों को अदालतों के चक्कर लगाते-लगाते सालों बीत गए, पर इंसाफ नहीं मिला।

की छात्रा का अपहरण कर सामूहिक बलात्कार किया गया और राजस्थान में एक महिला को पति ने पहले तलाक दिया और उसके बाद ससुर समेत सभी रिश्तेदारों ने उसके साथ मुंह काला किया, यह कहते हुए कि अब वह उनके परिवार की बहू नहीं है। सुना था मनुष्य पहले एक जानवर था, लेकिन इस तरह की वीभत्स घटनाएं बता रही हैं कि मनुष्य आज भी एक जानवर ही है।

आंकड़े बताते हैं कि भारत में हर पंद्रह मिनट में एक लड़की या महिला बलात्कार का शिकार हो जाती है। हाल में एक तमिल फिल्म निर्देशक ने यह कह डाला कि महिलाओं के विरुद्ध जो अपराध हो रहे हैं, उनके लिए वे खुद जिम्मेदार हैं, वे ऐसी स्थिति बनाती हैं कि घटना घटे। अगर वे सही तरह से व्यवहार करें तो सब ठीक रहेगा। उनका कहना है कि पहले महिलाओं पर बंदिशें थीं जो मोबाइल के आने के बाद खत्म हो गईं। उन्होंने

महिलाओं पर लगने वाली बंदिशों को सही ठहराया। जिस देश में ऐसी सोच रखने वाले लोग हों उस देश में संभवतः ऐसी घटनाएं चौंकाती नहीं हैं। खेत से लेकर घर, बाजार, दफ्तर, क्लब, स्कूल, कॉलेज, सड़क, बस, ट्रेन, कैब और शौचालय शायद ही कोई जगह ऐसी बची हो, जहां महिला सुरक्षित अनुभव करती हों। यह हमारे समाज की भयावह तस्वीर है।

अब तक की ज्यादातर घटनाओं से यही तथ्य सामने आते हैं कि कानून की लचर व्यवस्था और पुलिस प्रणाली इस तरह के मामलों में संवेदनहीनता का परिचय देती रही है। पीड़िता के परिवारीजनों को एक थाने से दूसरे थाने तक चक्कर लगवाना, लड़कियों को ही दोषी ठहराना, ज्यादातर मामलों में पुलिस द्वारा एफआईआर दर्ज न करना पुलिस के अमानवीय व्यवहार का ही परिचायक है। फिर जो मामले थानों और अदालतों तक पहुंचते भी हैं, वे कानूनी पेचीदगियों का शिकार हो जाते हैं। निर्भया का मामला इसका जीता-जागता उदाहरण है। क्या इसे तात्कालिक न्याय कहा जा सकता है। महिलाओं के विरुद्ध होने वाले जघन्य अपराधों को सरकार और कानून के रखवाले इतने हलके में कैसे ले सकते हैं, यह गंभीर सवाल है।

● ज्योत्सना अनूप यादव

म गवत गीता जीवन का मार्गदर्शन है। श्रीमद्भगवत गीता में जीवन का गूढ़ रहस्य छिपा हुआ है। कुरुक्षेत्र में जब सारथी बनकर भगवन कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया तो उसे सुनकर अर्जुन को अपने सारे सवालों का जवाब मिल गया और उन्होंने हाथ

जोड़कर श्रीकृष्ण से कहा कि प्रभु आपने तो जीवन का सार ही समझा दिया है। हर प्रकार की तृष्णाओं को मिटा दिया है। इस उपदेश को सुनकर ऐसा प्रतीत हो रही है कि आत्मा शुद्ध हो गई है। गीता के उपदेशों में आत्मा की शुद्धि पर विशेष बल दिया गया है। गीता के उपदेश व्यक्ति को महान बनने के लिए प्रेरित करते हैं।

जिसे अपने अग्रजों का आशीर्वाद, अनुजों का प्यार और मित्रों का स्नेह प्राप्त होता है वह समाज में सदा ही सम्मान प्राप्त करता है। ऐसे व्यक्ति समाज में अनुकरणीय बन जाते हैं। ऐसे लोग अपने आचरण से लोगों के लिए प्रेरणा बन जाते हैं। व्यक्ति का यह चरित्र उसे लोकप्रिय और महान बनाता है। व्यक्ति को अपने जीवन में ऐसा व्यवहार और आचरण करना चाहिए जिससे उसे सदैव बड़ों का आशीर्वाद मिलता रहे, छोटे भी उसे प्यार करें और मित्रों-सखाओं का स्नेह मिलता रहे। सामने वाला व्यक्ति आपको सम्मान प्रदान करे इसके लिए सबसे पहले आपको भी उस व्यक्ति को सम्मान देना होगा। सम्मान देना सम्मान लेने की ही एक प्रक्रिया है। ये ठीक वैसा ही है जैसा वक्ता बनने से पहले अच्छा श्रोता बनना। जो दूसरों की नहीं सुनेगा तो भला उसकी कौन सुनेगा। इसी तरह से जब किसी को सम्मान देते हैं तो दूसरा भी आपको सम्मान देने के लिए बाध्य हो जाता है। दवाब में कराया गया सम्मान भविष्य में मुसीबत पैदा करता है। सम्मान पाने के लिए सदैव सही मार्ग अपनाना चाहिए।

मां किसी भी व्यक्ति की पहली शिक्षक होती है। विद्यामंदिर और गुरुकुल में बच्चा उतना ग्रहण नहीं करता है जितना वह अपनी से ग्रहण करता है। इसलिए मां को हमेशा बच्चों के सामने उच्च आदर्श प्रस्तुत करना चाहिए। वही परिवार तरक्की करता है जिसमें स्त्रियां आधिक जागरूक और आर्दश होती हैं। ऐसी माताओं के पुत्र हमेशा इतिहास रचते हैं। ऐसी माताओं के पुत्रों को ये धरती युगों-युगों तक याद रखती है। जो मां अपने बच्चों में नैतिक गुणों को विकसित नहीं कर पाती है, ऐसी मां को पुत्र की असफलता पर कष्ट सहना पड़ता है। मां ही बच्चे में अच्छे संस्कार डालती है जो राष्ट्र के निर्माण में एक अहम भूमिका निभाते हैं। श्रीमद्भगवत गीता के उपदेशों में मानव के

जीवन का मार्गदर्शन है भागवत गीता



कल्याण का रहस्य छिपा हुआ है। धर्मयुद्ध में जब अर्जुन धर्मसंकट में फंस गए तब भगवान ने उन्हें गीता का रहस्य समझाया। आज भी गीता के उपदेश लोकप्रिय हैं। करोड़ों लोग इन उपदेशों को आत्मसात करके जीवन का आनंद ले रहे हैं। जो व्यक्ति गीता के उपदेशों को जीवन में उतार लेता है उसे सही मायने में जीने की कला आ जाती है। रणभूमि में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि हे अर्जुन कुछ भी स्थाई नहीं होता है। जो आया है वह जाएगा। जिसने जन्म लिया है उसे मरना ही पड़ेगा। ऐसे में मोह व्यर्थ है। जो व्यक्ति इस मोह में धिर जाता है वह सिर्फ अपनी परेशानियों को ही बढ़ाता है। ये संसार, शरीर कुछ भी स्थाई नहीं है। मनुष्य का जीवन जब तक है तब तक श्रेष्ठ कार्य करने चाहिए। लोगों के हित में कार्य करने चाहिए। आपके द्वारा अच्छे कार्यों की छाप रह जाती है बाकी सब मिट जाता है। इसलिए जीवन में ऐसे कार्य करने चाहिए जिससे आने वाली पीढ़ियां उदाहरण लें। ये दुनिया इसी तरह से चलती है। और आगे भी चलती रहेगी। व्यक्ति को सदा ही अच्छे कार्यों की तरफ अग्रसर रहना चाहिए।

व्यक्ति के जीवन में बहुत कुछ घटित होता रहता है। लेकिन ज्ञान और जागरूकता के अभाव में यह निर्णय नहीं ले पाता है कि उसे किन चीजों का हिस्सा बनना चाहिए। सफल व्यक्ति हर चीज का ज्ञान रखता है फिर वह बुरी हो या अच्छी। जानकारी हर चीज की होनी चाहिए। लेकिन अच्छी चीजों का हिस्सा बनना चाहिए और बुरी चीजों का नहीं। लेकिन बुरी चीजें व्यक्ति को अधिक प्रभावित करती हैं। ऐसे में व्यक्ति अच्छी

चीजों को त्यागकर बुरी चीजों को अपना लेता है और यहीं से उसके पतन का आरंभ होता है।

भगवत गीता में सेहत को प्राथमिकता दी गई है, अर्थात् सेहत है तो सबकुछ है। अच्छी सेहत के लिए मनुष्य को नियमित समय पर संतुलित आहार लेना चाहिए। भगवान श्रीकृष्ण ने कहा है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ आत्मा का वास होता है। मनुष्य स्वस्थ रहेगा तभी वह नियमित भगवान की भक्ति, उपासना, साधना, दैनिक एवं सामाजिक कार्य कर पाएगा। अच्छी सेहत ही सफलता की ओर अग्रसर करती है। इसलिए नए साल में आप भी सेहत को पहली प्राथमिकता दें और संतुलित आहार लेने की आदत डालकर चुस्त-दुरुस्त बनें और प्रगति करें।

कहा जाता है कि व्यक्ति जैसा भोजन करता है, उसका मन भी वैसा ही होता है फिर वह वैसा ही सोचता है और वैसा ही काम करता है। गीता में भोजन को बहुत महत्व दिया गया है। भगवान श्रीकृष्ण ने कहा है कि जीवन में सफल बनने के लिए मनुष्य को सदैव सात्विक और पोषक तत्वों से युक्त एवं पौष्टिक भोजन करना चाहिए। समय बहुत मूल्यवान होता है। अगर मनुष्य ने समय की कीमत समझ ली तो उसे जीवन में सफलता प्राप्त करने में कोई अड़चन नहीं आएगी। गीता में कहा गया है कि जिसने समय के महत्व को जान लिया उसने अपने जीवन के पहले पड़ाव को पार कर लिया। समय पर काम करने की आदत व्यक्ति को न सिर्फ सफल बनाती है बल्कि वह अपने जीवन में हमेशा उन्नति ही करता है।



सीधी-सच्ची बात

काँइ - काँइ करती हुई लंगड़ी कुतिया अपना टूटा पैर खींचती हुई बाहर चली गई। काकी ने बड़ी जोर से बेचारी कुतिया की पीठ पर डडोका (लट्टू) जो मारा था।

काकी की ये हरकत आर्यन को कतई अच्छी नहीं लगी। वो रुआंसा सा होकर काकी से बोला - 'काकी तुम बुरी हो, तुमने उस बेचारी कुतिया में डंडा क्यों मारा? अगर तुम उसे रोटी का एक टुकड़ा भी नहीं डाल सकती तो कम से कम डंडा तो मत मारो। बेचारी का एक पैर टूटा है।'

'अरे! वो जाती कहाँ है? कितनी बार भगाया, बार-बार आ जाती है।' काकी झल्लाती हुई बोली।

'और वो तिलक वाला! जो आड़े-तिरछे तिलक लगाकर रोज-रोज आता है। उसे तो तुम थाली भरकर आटा दे देती हो। देखा नहीं कितना मोटा-तगाड़ा पट्टा जवान है।' आर्यन काकी पर गुस्सा होता हुआ बोला।

'अरे बेटा! वे ब्राह्मण देवता हैं, अगर उन्हें दान-दक्षिणा नहीं देंगे तो वे श्राप दे देंगे। समझे!' काकी आर्यन को समझाते हुए प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोली।

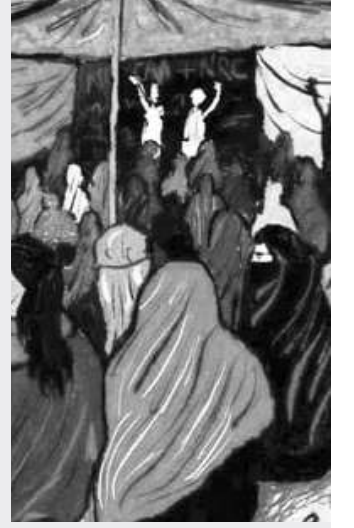
'पर काकी, बेचारी उस लंगड़ी कुतिया का तो कोई घर नहीं, कोई खेत नहीं, उसके पास खाने को भी कुछ नहीं ऊपर से पैर भी टूटा और भूल से किसी के घर - आंगन चली जाए तो मार खाती है, फिर भी किसी को श्राप नहीं देती। कितनी अच्छी है न वो' आर्यन एक सांस में सीधी-सच्ची बात कह गया।

आर्यन के इस भोलेपन पर लट्टू होते हुए काकी ने उसे अपने सीने से चिपका लिया।

— मुकेश कुमार ऋषि वर्मा

कोई तो कागज होगा!

ना रोटी ना कथरी होगी
और गिरस्ती बिखरी होगी
ठनठन होंगे बर्तन भांडे
सांस-सांस सांसत में होगी
ना कोई साया,
ना छावज होगा
पर कोई तो कागज होगा!
कौन मुलुक है
कहाँ जनम है
किस मिट्टी का दीन-धरम है
बरसों बीते होंगे यां पे
इनकी गिनती कहाँ रकम है
कहता फिरता देसी हूँ मैं
उनको लगता
जारज होगा
कोई तो कागज होगा
पाण्डुरंग से बच्चे तेरे
औज मरियम सी एक बीवी है
चर्खे-पीर से वालिद हैं तो
अम्मी जैनब की पीरी है
होगा पा-ए-कैस का छाला
तंगहाल सा एक गुवाला
पुरइन-पात-पखावज होगा
पर कोई तो कागज होगा
बुर्ज और बारादरियों में
जो नहीं रहीं उन बाबरियों में
क्या कोई दुआ तेरी बाकी है?
उम्मीदों के इस मकतल में
क्या ख्वाबों का इक घर बाकी है?
बे-दस्तावेजी जीता आया
अब क्या पसे मुर्दन
दो गज होगा?
कोई तो कागज होगा?
जल-जंगल-जमीन तेरे थे



मोमिन और मतीन तेरे थे
हर पैमाइश से बच जाएं
ऐसे सब यकीन तेरे थे
आदिवास के दावे होंगे
अबसे चौपट नगरी मरकज होगा,
कोई तो कागज होगा?
सरहद-सरहद के खेलों में
कबीर-ओ-सरमद की बातें कैसी?
राष्ट्रवाद के जमे नगर में
चलती दुनिया की ऐसी-तैसी
बसना और उखड़ना छोड़ो
मिलना और बिछड़ना छोड़ो
तकसीमों के इस मौसम में
ये सहारा है अपना छोड़ो
जो इंसां का मुजरिम होगा
वो ही इंसां का जज होगा
कोई तो कागज होगा।

— सौम्य मालवीय

सी मा कोई अच्छी कामवाली बाई तो बता जो घर का पूरा काम कर सके।

अरे, अभी तुने छः महीने पहले ही तो उस देवकी को काम पर रखा था और रहने के लिए जगह भी दी थी।

बहुत ही मक्कार थी वह तो। दिनरात अपने घर-परिवार की बात, बेटे-बहू का रोना और ढंग से काम नहीं करना। हमेशा बेटे-बहू की बुराई करना और बहुओं को झगड़ालू बताना। ऐसे में यदि उसके काम में कुछ नुकस निकालो तो फालतू की बहसबाजी शुरू कर देती थी। बात-बात पर लड़ने-झगड़ने को भी आमदा



झगड़ालू

स्वयं अपने स्वभाव को लेकर कुछ सोच में पड़ गई।

रहती थी। मुझे तो लगता है कि इसीलिए उसके बहू-बेटे उसे साथ नहीं रखते थे और वह इतनी दूर आकर हमारे घर काम करने आ गई थी।

लेकिन रीना तेरे बेटा-बहू भी तो तेरे साथ नहीं रहते!

अरे, वह तो हम लोग खुद ही किसी के बंधन में नहीं रहना चाहते, तेरे जीजाजी को भी पसंद नहीं है वरना तो बहू-बेटा तो बुलाते नहीं थकते।

रीना ने कह तो दिया लेकिन वह

— डॉ. प्रदीप उपाध्याय

विराट कोहली और सचिन तेंदुलकर में कौन सबसे अच्छा वनडे रन चेजर यानी लक्ष्य का पीछा करने वाला है? कुछ कहेंगे कोहली, तो कुछ कहेंगे सचिन, लेकिन आंकड़े क्या कहते हैं? भारत को जीत दिलाने के लिए लक्ष्य का पीछा करते हुए सचिन तेंदुलकर ने 124 इनिंग में 55.45 रन के एवरेज से अपने पूरे करियर में करीब 5490 रन बनाए। वहीं दूसरी ओर विराट कोहली ने 86 इनिंग में 96.21 के एवरेज से अब तक 5388 रन बना लिए हैं। उन्हें तो दुनिया में चेज मास्टर भी कहा जाता है। तो क्या एक दिवसीय मैचों में विराट कोहली सचिन तेंदुलकर से भी अच्छे चेजर हैं? चलिए आंकड़ों की जुबानी इसे समझने की कोशिश करते हैं।

डॉन ब्रैडमैन, सचिन तेंदुलकर, वसीम अकरम, शेन वॉर्न और डेल स्टेन जैसे खिलाड़ियों ने क्रिकेट की दुनिया में एक अलग ही मुकाम हासिल किया है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ब्रैडमैन ने कितने शतक बनाए थे, लेकिन आज भी टीम को मैच जीतने के लिए विरोधियों के खिलाफ उनकी जरूरत है। इसी तरह बाकी खिलाड़ी भी टीम के लिए बेहद अहम हैं। तेंदुलकर और कोहली में कौन बेस्ट, ये बहस तब तक अधूरी है, जब तक उनके वक्त के खिलाड़ियों के आंकड़ों को ना देखें। इस बहस को एक सही दिशा देने के लिए हम तेंदुलकर के करियर को दो हिस्सों में बांट कर देखेंगे। पहला उनके डेब्यू से लेकर 1996 तक और दूसरा 1996 से उनके रिटायर होने तक। 1996 को ही इसलिए चुना गया है, क्योंकि जब भारत के दो बल्लेबाज सौरव गांगुली और राहुल द्रविड़ ने क्रिकेट में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नाम कमाना शुरू किया था। तेंदुलकर के साथ मोहम्मद अजहरुद्दीन, नवजोत सिंह सिद्धू, अजय जडेजा जैसे खिलाड़ी हुआ करते थे।

1989-96 तक हुए सभी 31 मैचों में भारत ने लक्ष्य का पीछा करते हुए उसे हासिल करने में सफलता पाई। इनमें कुल 6 छक्के लगे, जिनमें 2 तेंदुलकर और 2 सिद्धू के नाम दर्ज हैं। तेंदुलकर ने 43.82 के एवरेज से रन बनाए। ये वो वक्त था, जब 1-2 अहम विकेट गिरने के बाद टीम दबाव में आ जाती थी, लेकिन गांगुली और द्रविड़ के आने के बाद वो सब बदल गया। गांगुली ने ओपनर की तरह टीम में आकर तेंदुलकर के साथ शानदार जोड़ी बनाई, जिसकी लोग आज भी तारीफें करते हैं। सचिन और सौरव के नाम अभी भी सबसे अधिक मैचों (17) में 100 रन की जोड़ी बनाने का रिकॉर्ड है।

1996 से लेकर तेंदुलकर के रिटायर होने तक भारतीय टीम के पास तीन अहम बल्लेबाज (अजहर, युवराज और गांगुली) थे, जिससे भारत



लक्ष्य का पीछा करने में बेस्ट कौन है...?

सचिन और विराट दुनिया के बेस्ट चेजर

अब इन सब बातों से निष्कर्ष ये निकलता है कि भारतीय टीम 1990 के दशक से 2000 के दशक तक आते-आते एक दिवसीय मैचों में टारगेट चेज करने में बेहतर होती गई है। सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली दुनिया के दो बेस्ट चेजर साबित हुए हैं। उनकी मदद की है गांगुली, युवराज, धोनी, रोहित और अन्य खिलाड़ियों ने, जिन्हें भी टीम इंडिया का इतना अच्छा चेजर बनने के लिए क्रेडिट मिलना जरूरी है। रही ये बात कि तेंदुलकर और कोहली में बेस्ट चेजर कौन है तो आंकड़े साफ करते हैं कि विराट कोहली ने क्रिकेट में बाकियों से बड़ा योगदान दिया है। अगर अभी के हिसाब से देखा जाए तो बेशक विराट कोहली सचिन तेंदुलकर से भी अच्छे चेजर साबित हुए हैं।

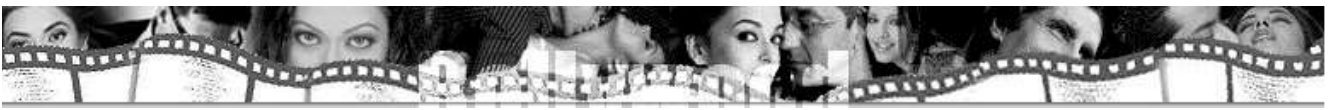
का रन चेज करने में एवरेज 59 के करीब था। इस दौरान सचिन ने चेजिंग करते हुए 12 शतक मारे, जबकि द्रविड़, धोनी, युवराज और सहवाग ने 1000 रन से अधिक बनाए। चेजिंग की ये विरासत धोनी को कप्तान बनने पर मिली और

उन्होंने इसे विराट कोहली को सौंप दिया। टीम ने इसकी अहमियत को ना सिर्फ बनाए रखा, बल्कि खिलाड़ी इसे एक अलग ही लेवल पर ले गए।

2008 में डेब्यू के बाद से ही कोहली ने टारगेट चेज करने में खूब नाम कमाया। टारगेट चेज करते हुए खेलकर विराट कोहली ने अब तक 5388 रन बना लिए हैं। ये रन उन्होंने 96.21 के औसत के बनाए हैं, जो उन्हें बाकियों से आगे दिखाने के लिए काफी है। लेकिन तेंदुलकर की तरह ही कोहली को भी मदद चाहिए थी, ताकि रिकॉर्ड तोड़े जा सकें। रोहित शर्मा, शिखर धवन, गौतम गंभीर और महेंद्र सिंह धोनी ये सब विराट कोहली के अहम पार्टनर रहे हैं, जिन्होंने टीम को जीत की ओर बढ़ाने में मदद की।

वैसे तो कोहली के 22 वनडे शतकों की कोई तुलना नहीं, लेकिन उनके साथी खिलाड़ियों ने भी खूब शतक मारे हैं, जिसने टीम को एक बड़ा स्कोर खड़ा करने में मदद की है। इस दौरान टारगेट का पीछा करते हुए रोहित शर्मा ने 10, धवन ने 5, गंभीर ने 4 और धोनी ने एक शतक मारा है। तस्वीर काफी हद तक साफ हो जाती है, जब हम भारत की जीत-हार के अनुपात को 3 चरणों में देखेंगे। सचिन के पूरे करियर में जो अनुपात 1.4 था, वह कोहली के समय में तेजी से ऊपर गया। इस समय भारत पूरी दुनिया में एक दिवसीय मैचों में टारगेट चेज करने वाली सबसे बेस्ट टीम है।

● आशीष नेमा



मुझे कभी किसी ने प्रपोज नहीं किया है: दिशा

इस समय बॉलीवुड की सबसे फिट और ग्लैमरस ऐक्ट्रेस में दिशा पाटनी का नाम शामिल नहीं किया जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। दिशा की अभी कुछ ही फिल्में आई हैं लेकिन उनकी लंबी-चौड़ी फैन फॉलोइंग है। वैसे पिछले काफी दिनों से दिशा और टाइगर श्रॉफ के कथित अफेयर के काफी चर्चे रहे हैं। हालांकि इस पर दोनों ने ही हमेशा खामोशी बरती है। वैसे अगर दिशा की मानें तो आज तक उन्हें कभी किसी लड़के ने प्रपोज नहीं किया है।

एक रिपोर्ट के मुताबिक, खुद दिशा ने ऐसा कहा है कि उन्हें किसी लड़के ने प्रपोज नहीं किया है। हाल में दिशा अपनी हालिया रिलीज फिल्म मलंग के कारण चर्चा में हैं और इसी के प्रमोशन के दौरान उन्होंने कहा कि उन्हें किसी ने प्रपोज नहीं किया। दिशा ने कहा, दरअसल स्कूल में टॉमबॉय थी, इसलिए किसी ने प्रपोज नहीं किया। दिशा ने आगे यह भी कहा कि उनके पिता पुलिस में रहे हैं इसलिए भी शायद किसी ने उनसे पूछा नहीं। उन्होंने कहा, डैड पुलिस में थे, किसी ने पूछा नहीं कभी। फिर कॉलेज में भी किसी ने नहीं पूछा। फिर इधर आ गई। इधर कोई पार्टी-वार्टी में नहीं जाती हूँ तो मिली नहीं किसी से। सैड लाइफ रही है काफी। इस समय फिल्म मलंग में दिशा की परफॉर्मेंस की काफी तारीफ हो रही है। इस समय वह सलमान खान के ऑपोजिट फिल्म राधे: योर मोस्ट वॉन्टेड भाई में काम कर रही हैं।



सलमान खान 16 से 18 रीटेक करते हैं: प्रभुदेवा

प्रभुदेवा को देश के सबसे बेहतरीन डांसरों में से एक माना जाता है। फिर जब बात स्टारडम की आती है तो सलमान की पॉप्युलैरिटी के आसपास कुछ ही लोग हैं। ऐसे में वे जब भी साथ में किसी प्रॉजेक्ट को लेकर आते हैं तो वह हिट हो जाता है। वॉन्टेड और दबंग 3 के बाद दोनों अब राधे में कर रहे हैं। ऐसे में जब हाल ही में प्रभुदेवा, जो कि एक कोरियोग्राफर भी हैं, से पूछा गया कि वह सलमान के डांसिंग टैलेंट को लेकर क्या सोचते हैं, इस पर उन्होंने कहा कि सलमान एफर्टलेस परफॉर्मर हैं। प्रभुदेवा ने सलमान से जुड़ा एक इंटरव्यू फैंक्ट बताते हुए कहा, वह 16 से



18 रीटेक करते हैं जबकि उसकी जरूरत भी नहीं होती है। क्यों दरअसल, सलमान परफेक्शन का खास ध्यान रखते हैं और अपने निर्देशकों को थोड़ा भी असंतुष्ट नहीं छोड़ना चाहते हैं। प्रभुदेवा ने आगे कहा, यह डायरेक्टर्स के ऊपर है कि वह कैसे सलमान को बेस्ट रूप में कैप्चर कर सकते हैं क्योंकि उनका यूनीक स्टाइल और ऐटिट्यूड है। डायरेक्टर्स और कोरियोग्राफर्स को सलमान से चीजें नहीं करानी चाहिए। उन्हें सलमान को वह करने देना चाहिए जो वह सबसे अच्छा करते हैं।

असल जिंदगी में भी टीचर रह चुके हैं राजकुमार

अपने दमदार अभिनय से दर्शकों का दिल जीतने के बाद अभिनेता राजकुमार राव आनेवाली फिल्म छलांग के साथ सबका मनोरंजन करने के लिए तैयार हैं। वह फिल्म में एक स्कूल टीचर की भूमिका निभाते हुए नजर आएंगे, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि कम लोगों को ही पता होगा कि राजकुमार राव असल जिंदगी में भी एक टीचर रह चुके हैं। हाल में राजकुमार ने इस बारे में बात की। इस बारे में बात करते हुए राजकुमार ने बताया, मैं अपनी ग्रैजुएशन की पढ़ाई के दौरान 3



महीने तक ट्यूमेटिक्स पढ़ा रहा था और उन 3 महीनों में मैंने एक नाटक का निर्देशन भी किया था। मैं टीचर से ज्यादा एक दोस्त की तरह था क्योंकि हमारे बीच उम्र का फासला ज्यादा नहीं था। मैं अक्सर अभिनय तकनीकों की खोज के बारे में बेहद उत्साहित रहता था और उस समय हर दिन सीखने के लिए एक रोमांचक अनुभव हुआ करता था।

विचारधारा की लड़ाई

विपक्ष कितनी घटिया हो गई है वोट के राजनीति के लिए कितना गिरेगी। अरे भाई मेरे शरीर पर मेरे भोजन पर मेरे निजी जिंदगी पर अपने फायदे के लिए हमला कर रही है। खैर मैं हमले के लिए तैयार हूँ, मुझ पर हमले करना हो जितना कर लो मगर मेरी प्यारी जनता के प्रति मैं एक भी शब्द नहीं सुन सकता हूँ।



ने ताजी का चुनाव चल रहा था भाषणबाजी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही थी, नेताजी अपने निर्वाचन क्षेत्र में जगह-जगह विपक्ष को कोस रहे थे। कुछ टीवी समाचार वालों ने सोचा क्यों नहीं अमेरिका की तरह यहां पर डायरेक्ट प्रत्याशियों का डिबेट हो जाए तो कितना अच्छा रहता। एक बड़े मैदान में मंच लगा वहां पर तमाम नेता और लोगों का जमावड़ा हो गया। हां आज क्षेत्र के माननीय विधायक जी और कुछ विपक्ष के नेता एकत्रित हुए हैं हम उनसे क्षेत्र की मूलभूत समस्या शिक्षा, बेरोजगारी एवं स्वास्थ्य सेवाओं पर चर्चा करेंगे।

वर्तमान विधायक- हमने अपने क्षेत्र की चौमुखी विकास के लिए एक सपना देखा था मगर विपक्ष की साजिश देखो मुझे सपना देखने भी नहीं देती, मुझे समाजसेवी नेता पर पानी के छिंटे मारकर जगा देती है। मैंने सपना देखा कि आप सबका विकास हो रहा है आप सबको सभी सुविधाएं मिल रही हैं, मगर ये सपना देखते-देखते मेरे 5 वर्ष गुजर गए अब मैं जाग गया हूँ, आप सभी मुझे अपना बहुमूल्य वोट देने की कृपा करें जिससे मैं पुनः विजय होकर अपने सपने को साकार करके आप सभी का विकास करना चाहता हूँ। विपक्ष को धूल चटा दो।

उधर विपक्ष वाले- महोदय आप सब बताइए उनके सपने में हम लोगों ने कोई खलल भी नहीं डाला। वो 5 साल तक दिल्ली में पड़े हुए थे, कभी उन्होंने पलटकर अपने निर्वाचन क्षेत्र में देखा भी नहीं। बड़े-बड़े चुनाव में उनकी बड़ी-बड़ी बोली लगती थी। बड़े फाइव स्टार होटलों में बड़े-बड़े बैग में बड़ी-बड़ी नोट देखने को जिसे मिले सच में जिसको क, ख, ग नहीं आए वह राजा की जिंदगी जीने लगे, उसे पूरा 5 वर्ष सपना ही सपना लगेगा।

अरे कल तक वह दुबला पतला डांगर सा हड्डी लगता था, मगर 5 साल की सत्ता की मलाई में देखो कैसे मोटा ताजा हो गया। अरे विकास तो उसका हुआ है पहले 2 मीटर कपड़ा लगता, लेकिन अब साढ़े 3 मीटर का लगने लगा।

वर्तमान विधायक- विपक्ष कितनी घटिया हो गई है। वोट के राजनीति के लिए कितना गिरेगी। अरे भाई! मेरे शरीर पर मेरे भोजन पर मेरे निजी जिंदगी पर अपने फायदे के लिए हमला कर रही है। खैर मैं हमले के लिए तैयार हूँ मुझ पर हमले करना हो जितना कर लो मगर मेरी प्यारी जनता के प्रति मैं एक भी शब्द नहीं सुन सकता हूँ।

विपक्ष वाले- हमारे क्षेत्र की सड़क बहुत बुरी तरह से टूट गई है, जगह-

जगह गड्ढे हो गए हैं। पैदल चलना भी दुश्वार हो गया है। अरे! गड्ढे में सड़क के मामले में इस क्षेत्र का गिनीज बुक में नाम दर्ज कर लिया जाना चाहिए।

वर्तमान विधायक- मैं मानता हूँ, मेरे क्षेत्र की सड़क की दुर्दशा हो रही है। इसके लिए विपक्ष जिम्मेदार है, क्योंकि जब मैं इस क्षेत्र का विधायक चुना गया उस समय यहां पर अपराध बहुत जोरों पर चल रहा था। मैंने एक कमेटी का गठन किया, उस दौरान मुझे पता चला तो मेरा सिर चकरा गया। अरे! विपक्ष ने उस समय सड़क इतना बढ़िया बनवा दिया था कि कोई भी अपराध करके आसानी से सड़क से भाग जाता। सो मुझे हारमोनियम साहब ने बताया कि अगर सड़क टूटी रहेगी तो अपराधी का मनोबल टूट जाएगा, फिल्हाल अपराध में भारी कमी आ गई।

मेरी प्यारी जनता... देखिए विपक्ष वालों की साजिश मुझे बदनाम करने की। खैर...! मुझे जितना बदनाम करना हो कर लो, मगर मेरे क्षेत्र को मत करो।

भीड़ में से आवाज आई...अरे भैया! यहां पर इस क्षेत्र के विकास को लेकर चर्चा हो रही है, उस पर चर्चा करो। मगर जोर-जोर की नारों के बीच में वह आवाज दब गई।

विपक्ष वाले- ओ आप तो राजा हरिशचंद्र हो उनकी खानदान के हो, कितना झूठ बोल रहे हो, ईश्वर माफ कर दे मगर यहां की जनता माफ नहीं करेगी।

वर्तमान विधायक- मैं हरिशचंद्र नहीं, गांधी विचारधारा से हूँ। मेरा हर कार्यकर्ता गांधीजी की प्रेरणा लेकर राजनीति में अपने प्रतिद्वंद्वी विचारधारा से मुकाबला कर रहा है। यहां पर हर कार्यकर्ता महात्मा गांधी है।

विपक्ष वाले- हो महात्मा गांधी की विचारधारा पर हम लोग चलने वाले हैं। सच कहें ईमानदारी से तो हमारे पार्टी का कार्यकर्ता महात्मा गांधी है तभी तो आप के चमचे यहां पर आपके नाम पर जमकर वसूली कर रहे थे।

तभी दोनों पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आपस में झगड़ना शुरू कर दिया। कुर्सियां एक-दूसरे पर खींच-खींच कर मारना शुरू हो गए, देखते-देखते मंच के सामने युद्ध का मैदान बन गया। पुलिस ने जमकर लाठियां भांजी अगले दिन अखबारों में मुखपृष्ठ पर निकला गांधीवादी विचारधारा की लड़ाई में 10 लोगों का सिर फूट गया, 4 लोगों का हाथ और भगदड़ में 10 का पैर टूटा।

● अभिषेक राज शर्मा



43 वर्षों की गौरवशाली परम्परा...

बीडीए है तो विश्वास है...

भोपाल विकास प्राधिकरण

सम्पत्ति क्रय करने का सुनहरा अवसर

बुकिंग दिनांक

10.02.2020 से

24.02.2020

तक

लॉयर्स चेम्बर्स योजना के अंतर्गत उपलब्ध चेम्बर्स

चेम्बर्स/इकाईयों का विवरण	चेम्बर्स/इकाईयों का उपयोग	अनु. क्षेत्रफल वर्गमीटर/वर्गफिट में	श्रेणी अनारक्षित	प्राधिकरण द्वारा नियत कीमत रुपये प्रति संपत्ति मूल्य	रजिस्ट्रीकरण प्रभार (पंजीयन राशि) रुपये	वार्षिक भू-भाटक
चेम्बर क्र.- 355	अधिवक्ता चेम्बर	10.95 वर्गमीटर	अधिवक्ता हेतु आरक्षित	11,47,359/-	1,14,735/-	9485/-
चेम्बर क्र.- 339	अधिवक्ता चेम्बर	9.30 वर्गमीटर	अधिवक्ता हेतु आरक्षित	9,74,469/-	97,446/-	8056/-
चेम्बर क्र.- 103	अधिवक्ता चेम्बर	9.30 वर्गमीटर	अधिवक्ता हेतु आरक्षित	12,03,048/-	1,20,304/-	8056/-
चेम्बर क्र.- 229	अधिवक्ता चेम्बर	7.50 वर्गमीटर	अधिवक्ता हेतु आरक्षित	8,73,180/-	87,318/-	6496/-
चेम्बर क्र.- 232	अधिवक्ता चेम्बर	10.95 वर्गमीटर	अधिवक्ता हेतु आरक्षित	12,74,843/-	1,27,484/-	9485/-
चेम्बर क्र.- 257	अधिवक्ता चेम्बर	10.95 वर्गमीटर	अधिवक्ता हेतु आरक्षित	12,74,843/-	1,27,484/-	9485/-
चेम्बर क्र.- 402	अधिवक्ता चेम्बर	9.30 वर्गमीटर	अधिवक्ता हेतु आरक्षित	8,77,018/-	87,701/-	8056/-
चेम्बर क्र.- 213	अधिवक्ता चेम्बर	10.77 वर्गमीटर	अधिवक्ता हेतु आरक्षित	12,53,886/-	1,25,388/-	9329/-
चेम्बर क्र.- 214	अधिवक्ता चेम्बर	10.77 वर्गमीटर	अधिवक्ता हेतु आरक्षित	12,53,886/-	1,25,388/-	9329/-
चेम्बर क्र.- 132	अधिवक्ता चेम्बर	10.95 वर्गमीटर	अधिवक्ता हेतु आरक्षित	14,16,492/-	1,41,649/-	9485/-
चेम्बर क्र.- 254	अधिवक्ता चेम्बर	10.95 वर्गमीटर	अधिवक्ता हेतु आरक्षित	12,74,843/-	1,27,484/-	9485/-
चेम्बर क्र.- 306	अधिवक्ता चेम्बर	9.30 वर्गमीटर	अधिवक्ता हेतु आरक्षित	9,74,469/-	97,446/-	8056/-

व्यवसायिक संपत्तियों के ऑफर दिनांक 25.02.2020
समय दोपहर 1.00 बजे तक प्राप्त किये जावेंगे तथा समय
1.30 बजे से उपस्थित ऑफरकर्ताओं के समक्ष खोले जावेंगे।

संपत्तियों का विवरण हमारी वेबसाइट पर उपलब्ध है।
Website: <http://www.bda.org.in>

फार्म का
मूल्य - 500/-

30 वर्ष की
लीज पर

अधिक जानकारी के लिये कार्यालय में संपर्क करें।

प्रगति भवन, प्रेस कॉम्प्लेक्स, जोन-1, एम.पी. नगर, भोपाल 462 011 (म.प्र.)

जनसम्पर्क अधिकारी दूरभाष: 0755-2701836/37/38, 2557273/2557276

E-mail: info@bda.org.in

उपमुख्य कार्यपालन
अधिकारी (राजस्व)

विश्वसनीय खबरों के लिए पढ़ते रहिए

In Pursuit of Truth

आक्ष

www.akshnews.com



लॉगऑन करें

www.akshnews.com

वार्षिक सदस्यता के लिए संपर्क करें, 150, जोन-1, एम.पी.नगर भोपाल
 फोन: 0755-4017788, 2575777